



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 26072021-228471  
CG-DL-E-26072021-228471

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2021/श्रावण 4, 1943

No. 205]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2021/SHRAVANA 4, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

(मामला सं. ओआई-17/2020)

**विषय:** चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका से "रबर केमिकल पीएक्स-13" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

**फा. सं. 6/20/2020-डीजीटीआर.**—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1. मैसर्स नोसिल लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" कहा गया है) ने चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से रबर केमिकल पीएक्स-13 (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं

संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार टीपीएम कंसल्टेंट के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे अगर लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 27 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या 06/20/2020-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
3. प्राधिकारी ने इस अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखकर अंतरिम शुल्क की सिफारिश करने के लिए इसे उपयुक्त माना और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 11 नवंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 6/20/2020-डीजीटीआर के माध्यम से प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किया। तथापि, दिनांक 21 अक्तूबर, 2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 354/121/2020-टीआरयू के माध्यम से केन्द्र सरकार ने अनंतिम पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया।

#### ख. प्रक्रिया

4. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
  - क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत की कार्रवाई से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
  - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 27 मई, 2020 को सार्वजनिक सूचना जारी की।
  - ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को 27 मई, 2020 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने अनुरोध से अवगत कराएं।
  - घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
  - ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ उन्हें भेजी गई थी।
  - च. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर हितबद्ध पक्षकारों को उनके उत्तर तथा अनुरोध दायर करने के लिए समय बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी। दिनांक 30 जून, 2020 के पत्र द्वारा समय 24 जुलाई, 2020 तक बढ़ाया गया था। 23 जुलाई, 2020 के पत्र द्वारा 7 अगस्त, 2020 तक समय बढ़ाया गया था।
  - छ. निम्नलिखित सरकार ने लिखित आवेदन उपलब्ध कराए हैं:
    - i. कोरिया सरकार
    - ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:
      - i. मै. चीन सनशाइन केमिकल होल्डिंग्स लिमिटेड

- ii. मै. सेनिक्स कं. लिमिटेड - सिनोकेम इंटरनेशनल (जियांग्सु सिनोरगैम टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड)
- iii. मै. शानडोंग यंगु हुटाई केमिकल कं. लिमिटेड
- iv. मै. चांगदे डिंगयुआन केमिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड
- v. मै. डोंडियांग बो केन केमिकल कंपनी लिमिटेड
- vi. मै. जिनान रंगुआन केमिकल कं. लिमिटेड
- vii. मै. नानजिंग केमिकल प्लांट (एनसीपी)
- viii. मै. झेजियांग योंगजिया केमिकल प्लांट
- ix. मै. हेनान कैलू केमिकल कं. लिमिटेड
- x. मै. रोंगचेंग केमिकल जनरल फैक्ट्री कंपनी लिमिटेड
- xi. मै. डालियान रिचोन केमिकल कं. लिमिटेड
- xii. मै. झेनजियांग नंबर 2 केमिकल फैक्ट्री
- xiii. मै. हेबेई हुआफेंग केमिकल ग्रुप
- xiv. मै. शेन्जेन हुआरेन इंडस्ट्रियल कं.
- xv. मै. यिक्सिंग डोंगफांग फिंस केमिकल्स
- xvi. मै. झेजीना युएजिंग अल्ट्राफाइन पाउडर्स एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xvii. मै. लायन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xviii. मै. लिंकवेल रबर केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xix. मै. केमई केमिकल कं. लिमिटेड
- xx. मै. हेबी हुआक्सिया ऑक्सीलरी कं. लिमिटेड
- xxi. मै. किंगदाओ झोंगजियान रबर केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xxii. मै. नॉर्थईस्ट ऑक्सीलरी केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमिटेड
- xxiii. मै. पुयांग विलिंग केमिकल्स कं. लि.
- xxiv. मै. झेजियांग हुआंग्यान झेडोंग रबर ऑक्सीलरी कंपनी लिमिटेड
- xxv. मै. डोंगींग वानटोंग रबर ऑक्सीलरी कंपनी लिमिटेड
- xxvi. मै. ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, टोंगलिंग केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप की कंपनी
- xxvii. मै. शंग्यु लिक्सिंग केमिकल कं. लिमिटेड
- xxviii. मै. तियानजिन ईस्ट रिक्सन रबर एडिटिक्स कं. लिमिटेड
- xxix. मै. डोंगलोंग इंडस्ट्री लिमिटेड, जियांग्सु की कंपनी
- xxx. मै. जिनचेंग स्काई सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमिटेड
- xxxi. मै. हेबेई हांक्सिंग केमिकल कं. लिमिटेड
- xxxii. मै. जिनचेंग तियांचेंग केमिकल कं.
- xxxiii. मै. हेबी उहू रबर केमिकल्स कं. लिमिटेड
- xxxiv. मै. कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड
- xxxv. मै. देवू इंटरनेशनल कारपोरेशन

xxxvi. मै. लैक्सेस कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका

झ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों तथा उनके संबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों ने उत्तर दिया है और निर्यातक की प्रश्रावली का उत्तर और/अथवा कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किया:

- i. मै. लैक्सेस कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका (लैक्सेस)
- ii. मै. कुम्हो पेट्रो केमिकल कंपनी लिमिटेड कोरिया गणराज्य (कुम्हो)
- iii. मै. सेनिक्स कं. लिमिटेड शानडोंग, चीन जन. गण.
- iv. मै. सेनिक्स कं. लिमिटेड ताइवान, चीन जन. गण.
- v. मै. सेनिक्स सिंगापुर पीटीई. लिमिटेड
- vi. मै. सेनिक्स इंक. संयुक्त राज्य अमेरिका
- vii. मै. सेनिक्स कं. लिमिटेड, चीन जन. गण.
- viii. पॉस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, कोरिया (पॉस्को)

ञ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्रावलियां भेजीं:

- i. मै. लैक्सेस इंडिया पी. लि.
- ii. मै. पीएमसी रबकेम पी. लि.
- iii. मै. अपोलो टायर्स
- iv. मै. एटीसी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
- v. मै. बिडला टायर
- vi. मै. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- vii. मै. ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- viii. मै. जे.के. फेनर (इंडिया) लिमिटेड
- ix. मै. सिएट लिमिटेड
- x. मै. राल्सन
- xi. मै. एमआरएफ लि.
- xii. मै. जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xiii. मै. टीवीएस श्रीचक्र
- xiv. मै. गुडइयर इंडिया लि.
- xv. मै. मल्होत्रा रूबर्स लिमिटेड
- xvi. मै. मेट्रो टायर्स लिमिटेड
- xvii. मै. स्पीडवेज रबर कंपनी

ट. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है और आयातक/प्रयोक्ता की प्रश्रावली का उत्तर और/अथवा कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किया:

- i. मैसर्स लैक्सेस इंडिया प्रा. लिमिटेड
- ii. मैसर्स रिशिरूप लिमिटेड

- iii. मैसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड
  - iv. मैसर्स सिएट लिमिटेड
  - v. मैसर्स जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - vi. मैसर्स एमआरएफ लिमिटेड
- ठ. प्राधिकारी ने दिनांक 27 मई, 2020 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भारत में संबद्ध सामानों की निम्नलिखित ज्ञात संघों को भेजी:
- i. ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए)
- ड. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित संघों ने जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर दिया गया है और कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किया:
- i. ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए)
  - ii. ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एआईआरआईए)
- ढ. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 4 मार्च, 2021 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित आम सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया। उन पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में और उसके बाद प्रत्युत्तर संबंधी अनुरोध, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। इन पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने अगोपनीय अनुरोधों को साझा किया और उन्हें सलाह दी गई थी कि वे अपने खंडन प्रस्तुत करें।
- ण. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध के अगोपनीय रूपांतर को ई-मेल करने के लिए उन सभी को इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था क्योंकि सार्वजनिक फाइल जारी वैश्विक महामारी के कारण भौतिक रूप से प्राप्त करने योग्य नहीं थी।
- त. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 माह) है। क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 और जांच की अवधि के रूप में मानी गई है।
- थ. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद अपने विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- द. आवेदक से उस सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी, जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के उद्देश्य से उस सीमा तक किया गया था, जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया।
- ध. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को ध्यान में रखकर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- न. जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, दिए गए तर्कों पर विचार इस अंतिम जांच परिणाम में उस सीमा तक किया गया है, जिस सीमा तक उसके समर्थन में साक्ष्य हैं और जिस सीमा तक वर्तमान जांच से उन्हें संगत माना गया।

- प. जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना, जो इस अंतिम जांच परिणाम का यथासंभव आधार बनता है, की सटीकता के संबंध में अपने आप को संतुष्ट किया और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन उस सीमा तक किया, जिस सीमा तक उसे संगत और संभव माना गया।
- फ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- ब. इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 15 जुलाई, 2021 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उसके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया, का समाधान इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात् किए गए अधिकांश अनुरोध उनके द्वारा पूर्व में किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। हालांकि, प्रकटन पश्चात् अनुरोधों की जांच इन अंतिम जांच परिणामों में उस सीमा तक की जा रही है, जिस सीमा तक उसे संगत माना गया।
- भ. जहां कहीं भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच दिए जाने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है या इस जांच में काफी हद तक बाधा पहुंचा है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम को रिकॉर्ड किया है।
- म. इस अंतिम जांच परिणाम में "\*\*\*\*" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना को दर्शाते हैं।
- य. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.65 रुपए है।

#### ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. जांच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"विचाराधीन उत्पाद "रबर केमिकल पीएक्स-13" (जिसे यहां आगे पीएक्स-13 भी कहा गया है) है जिसे 6पीपीडी, एंटीऑक्सीडेंट 6पीपीडी, कुमानोक्स 13, सेंटोफ्लेक्स 6पीपीडी, सिरनटोक्स 6पीपीडी, वुल्कानोक्स 4020, एंटीऑक्सीडेंट 4020, दुसानटोक्स 6पीपीडी, एंटेज 6सी, एन-1.3, 3-डिमिथाइलबुटाइल-एन-फिनाइल-पी-फिनाइलेनेडायमीन, इत्यादि के रूप में भी जाना जाता है।

पीएक्स-13 एक एल्काइल-अराइल-पीपीडी एंटीडिजैट है जो व्यापक रूप से अधिकतर रबर उद्योग के टायर तथा गैर-टायर क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। पीएक्स-13 जो ओजोन (स्थिर तथा गतिशील), फ्लैक्स-क्रेकिंग एवं फैटिंग, ऑक्सीडेटिव हीट एजींग, मेटल-आयन कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेटिव एजींग, यूवी लाइट एवं वैदरिंग जैसे डिग्रेडेटिव फोर्सेस के विरुद्ध रबर वुल्कानाइजेट्स में उत्कृष्ट प्रतिरोधकता प्रदान करता है। इसका प्रयोग प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर (एसबीआर, बुटाडीन रबर, नाइट्राइल रबर, कार्बोक्सिलेटेड रबर) और रबर उत्पाद का वांछित जीवन-चक्र प्राप्त करने के लिए विभिन्न रबर उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अन्य सिंथेटिक रबर आधारित मिश्रणों के शोधन में एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में किया जाता है। पीएक्स-13, 4एडीपीए और एमआईबीके के रिडिक्टिव एल्कीलेशन द्वारा विनिर्मित किया जाता है।

यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण 3812 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 38 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के तहत विचाराधीन उत्पाद के लिए भी आयात होते हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

**ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

6. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद "रबर केमिकल पीएक्स-13" जिसे 6पीपीडी, एंटीऑक्सीडेंट 6पीपीडी, कुमानोक्स 13, सेंटोफ्लेक्स 6पीपीडी, सिरनटोक्स 6पीपीडी, वुल्कानोक्स 4020, एंटीऑक्सीडेंट 4020, दुसानटोक्स 6पीपीडी, एंटेज 6सी, एन-1.3, 3-डिमिथाइलबुटाइल-एन-फिनाइल-पी-फिनाइलेनेडायमीन के रूप में भी जाना जाता है, है।
  - पीएक्स-13 एक एल्काइल-अराइल-पीपीडी एंटीडिटर्जेंट है जो व्यापक रूप से अधिकतर रबर उद्योग के टायर तथा गैर-टायर क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। पीएक्स-13 जो ओजोन (स्थिर तथा गतिशील), फ्लैक्स-क्रैकिंग एवं फैटिंग, ऑक्सीडेटिव हीट एजींग, मेटल-आयन कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेटिव एजींग, यूवी लाइट एवं वैदरिंग जैसे डिग्रेटिव फोर्सेस के विरुद्ध रबर वुल्कानाइजेट्स में उत्कृष्ट प्रतिरोधकता प्रदान करता है। पीएक्स-13 पेस्टाइल्स सभी प्रकार की तुलन प्रणालियों पर सार-संभाल करने में आसान हैं और निम्न प्रसंस्करण तापमानों पर भी रबर मिश्रणों में तेजी से फैल जाते हैं।
  - यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 और 38 के तहत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद 8 अंकीय एचएस कोडों 29215130, 29215190, 38121000, 38123030, 38123910, 38123990 और 38123100 के तहत आयात किए जा रहे हैं। प्राधिकारी द्वारा रबर रसायनों के पूर्व जांच परिणामों में शुल्क की सिफारिश हमेशा 4 अंकीय स्तरों पर की गई है।
  - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है और वे इन वस्तुओं की भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण, वितरण एवं वितरण और प्रशुल्क वर्गीकरण के संबंध में तुलनीय हैं।
  - आवेदक ने आयातित उत्पादों की समान वस्तु का उत्पादन किया है।

**ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

7. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- द्रव/पिघला हुआ रूप समान वस्तु नहीं है और इसीलिए उसे संबद्ध सामानों के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए।
  - कंपनी ने भारत को द्रव रूप में निर्यात किया है जबकि भारत में द्रव एवं ठोस रूप दोनों को बेचा है।
  - भारत को निर्यातित द्रव रूप पूरा संबद्ध कंपनी को बेचा गया था जिसने इसका आगे प्रसंस्करण किया और भारत में अंतिम ग्राहकों को ठोस रूप में बेचा।

**ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

8. विचाराधीन उत्पाद "रबर केमिकल पीएक्स-13" जिसे 6पीपीडी, एंटीऑक्सीडेंट 6पीपीडी, कुमानोक्स 13, सेंटोफ्लेक्स 6पीपीडी, सिरनटोक्स 6पीपीडी, वुल्कानोक्स 4020, एंटीऑक्सीडेंट 4020, दुसानटोक्स 6पीपीडी, एंटेज 6सी, एन-1.3, 3-डिमिथाइलबुटाइल-एन-फिनाइल-पी-फिनाइलेनेडायमीन के रूप में भी जाना जाता है।
9. पीएक्स-13 एक एल्काइल-अराइल-पीपीडी एंटीडिटर्जेंट है जो व्यापक रूप से अधिकतर रबर उद्योग के टायर तथा गैर-टायर क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। पीएक्स-13 जो ओजोन (स्थिर तथा गतिशील), फ्लैक्स-क्रैकिंग एवं फैटिंग, ऑक्सीडेटिव हीट एजींग, मेटल-आयन कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेटिव एजींग, यूवी लाइट एवं वैदरिंग जैसे डिग्रेटिव फोर्सेस के विरुद्ध रबर वुल्कानाइजेट्स में उत्कृष्ट प्रतिरोधकता प्रदान करता है। इसका प्रयोग प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर (एसबीआर, बुटाडीन रबर, नाइट्राइल रबर, कार्बोक्सिलेटेड रबर) और रबर उत्पाद का वांछित जीवन-चक्र प्राप्त करने के लिए विभिन्न रबर उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अन्य पृष्ठ 6 के 2 सिंथेटिक रबर

आधारित मिश्रणों के शोधन में एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में किया जाता है। पीएक्स-13, 4एडीपीए और एमआईबीके के रिडक्टिव एल्कीलेशन द्वारा विनिर्मित किया जाता है।

10. यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण 3812 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 38 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के तहत भी आयात किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक माना गया है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। जहां कहीं विचाराधीन उत्पाद के आयात सूचित किए गए हैं, वहां वर्तमान निर्धारण के प्रयोजन के लिए उन पर विचार किया गया है।
11. जहां तक द्रव/पिघले हुए रूप को हटाने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी संबद्ध कंपनी से द्रव रूप में आयात किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध निर्यातक/उत्पादक ने द्रव एवं ठोस रूप, दोनों की घरेलू बाजार में बिक्री की है। भारत में यह आयातक पीएक्स-13 का उत्पादक है। कंपनी ने आयातित द्रव पीएक्स-13 को ठोस में प्रसंस्कृत किया है और उसके बाद कंपनी द्वारा उत्पादित पीएक्स-13 के साथ संभावित गिरावटों को बेचा है। इस प्रकार, जहां तक विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं का संबंध है, उन्होंने पीएक्स-13 का ठोस रूप खरीदा है। यह मामला ऐसा होने के नाते द्रव एवं ठोस रूप को दो भिन्न वस्तुओं के रूप में नहीं माना जा सकता और द्रव रूप को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता।
12. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित सामानों की समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक एवं केमिकल विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया है और कर रहे हैं।

#### घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

##### घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
  - क. आवेदक नोसिल लिमिटेड का भारत में संबद्ध सामानों के भारतीय उत्पादन का "प्रमुख अनुपात" है। आवेदक का भारत में संबद्ध सामानों के लिए कुल भारतीय उत्पादन का 70.13 प्रतिशत हिस्सा है।
  - ख. आवेदक ने संबद्ध देशों से जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है।
  - ग. आवेदक संबद्ध देशों में किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध सामानों के आयातकों से संबद्ध नहीं हैं।
  - घ. लेनसेक्स इंडिया को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसके उत्पादन पर भारतीय उत्पादन में आवेदक के हिस्से की गणना करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अपनी सहयोगी कंपनी अर्थात् लेनसेक्स कार्पोरेशन, यूएसए से संबद्ध वस्तुओं का आयात कर रहा है और निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हुए बिना संबद्ध वस्तुओं के रूप को केवल परिवर्तित करता है। एसडीएच पारेसन उपकरण, सीपीवीसी रेसिन में जांच परिणामों का संदर्भ लिया गया है जिसमें प्राधिकारी ने यह माना कि प्रत्येक घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।
  - ड. लेनसेक्स यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कंपनी को पाटित कीमतों पर सामग्री उपलब्ध होना जारी रहे।

##### घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
  - क. लेनसेक्स को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से लेनसेक्स द्वारा किए गए आयातों की मात्रा की स्थिति का निर्धारण किए बिना केवल इस आधार पर बाहर नहीं रखा जा सकता है कि इसने संबद्ध देश से पीयूसी का आयात किया है।



- ख. यह तथ्य कि लेनसेक्स 4एडीपीए का आयात कर रहा है, इसकी स्थिति को विचाराधीन उत्पाद के घरेलू निर्माता के रूप में नहीं बदल सकता है।
- ग. नोसिल अपने बल पर भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत “बड़े हिस्से” की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। कुल भारतीय उत्पादन में लेनसेक्स के उत्पादन सहित घरेलू उद्योग के रूप में नोसिल के आधार का फिर से आकलन करने के अनुरोध और क्या इसका कुल भारतीय उत्पादन में बड़ा हिस्सा है।
- घ. लेनसेक्स प्रमुख घरेलू उत्पादकों में से एक है और इसने तल रूप में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और अपने उत्पादन को पूरा करने के लिए फ्लेक्स में परिवर्तित किया है। जांच की अवधि में आयात किए गए सामानों की बिक्री तरल रूप में नहीं की गई है।
- ड. लेनसेक्स इंडिया ने चीन और कोरिया से आयातों, जो आधार को पूरा नहीं करता था और जिसका विरोध नोसिल द्वारा किया गया था, पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता दर्शाते हुए डीजीटीआर से संपर्क किया।
- च. घरेलू उद्योग उनके द्वारा किए गए आयातों पर ध्यान दिए बिना घरेलू उत्पादक को शामिल करने के लिए प्राधिकारी के पास उपलब्ध विवेकाधिकार पर विचार करने में असफल रहा है।
- छ. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए कोई प्रमाणित दावे नहीं किए हैं कि लेनसेक्स बहुत अधिक बड़ी मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रहा है और उससे यह घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने के लिए अपात्र हो गया है अथवा यह कि उत्पादन से आयात पर बल दिया है।
- ज. प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादक, जिन्होंने आयात किया है अथवा जो किसी आयातक से संबंधित हैं अथवा पिमेंट, पैपरोलेक्टम के आयातों के संबंध में जांच में पात्र घरेलू उद्योग के रूप में आयात करता है। एट्राजाइन टेक्निकल और सतत् कास्ट कॉपर वायर रोड्स के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांचों में, घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने कच्चे माल का आयात किया था, का घरेलू उद्योग के रूप में कुल लागत का बहुत बड़ा हिस्सा है।
- झ. लेनसेक्स को इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि क्या यह एक पात्र घरेलू उत्पादक है अथवा नहीं, क्षति विश्लेषण के उद्देश्यों से बाहर नहीं रखा जा सकता है।
- ञ. घरेलू उद्योग के रूप में लेनसेक्स इंडिया को नहीं माने जाने के दावे की निकटता से जांच की जानी चाहिए और यदि तथ्य पात्रता को सिद्ध करते हों तब अधिक हिस्से की जांच अवश्य की जानी चाहिए।

### घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:  
*“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”*
16. यह आवेदन पत्र मैसर्स नोसिल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो जांच की अवधि में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं।
17. भारत में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन निम्नलिखित कंपनियों द्वारा किया जाता है:
  - i. लैंक्सेस इंडिया प्रा. लि.
  - ii. पीएमसी रबरकेम प्रा. लि.

18. लैक्सेस द्वारा दी गई सूचना से यह देखा जाता है कि कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाराधीन उत्पाद का काफी मात्रा में आयात किया है। यह भी नोट किया जाता है कि कंपनी निर्यातक से संबद्ध है और स्वयं में आयातक है तथा ऐसे आयातों की मात्रा काफी अधिक (संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों की समग्रता इस कंपनी द्वारा है) है। प्राधिकारी ने लैक्सेस को एक घरेलू उत्पादक माना है, परंतु नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग नहीं माना है। जहां तक लैक्सेस इंडिया की पात्रता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लैक्सेस इंडिया की अपात्रता 4-एडीपीए के आयातों के कारण नहीं है। वह पीएक्स-13 के आयातों और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के साथ उसके संबंध के कारण है।
19. आवेदक के उत्पादन में समग्र भारतीय उत्पादन (लैक्सेस सहित) में \*\*\* प्रतिशत हिस्सा है और लैक्सेस के उत्पादन को हटाने के बाद \*\*\* प्रतिशत है।
20. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, आवेदक का भारतीय उत्पादन में बहुत बड़ा हिस्सा है। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक इस नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है। इसके अलावा प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस आवेदन ने इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा किया।

## **ड. गोपनीयता**

### **ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

21. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
  - i. निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली के उत्तरों में बिक्री माध्यमों, कारपोरेट ढांचा, बेचे गए उत्पादों की सूची आदि के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
  - ii. निर्यातकों ने सार्वजनिक डोमेन में निशुल्क उपलब्ध सूचना के गोपनीय होने के रूप में दावा किया है।
  - iii. प्रयोक्ताओं/आयातकों ने प्रश्नावली के उत्तरों की अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और गोपनीय के रूप में दावा की गई सूचना का एक तर्कसंगत सार उपलब्ध नहीं कराया है।
  - iv. प्रयोक्ताओं/आयातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर पूर्ण नहीं हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक डोमेन में सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है।
  - v. घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका इस नियमावली के नियम 7, व्यापार सूचना सं. 1/2013 और व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुसार है।
  - vi. लागत संबंधी सूचना की गोपनीयता के संबंध में, यह एक व्यापार प्रोपराइटी सूचना है जिसका सारांश नहीं किया जा सकता है। निर्यातकों ने स्वयं लागत संबंधी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है और अलग-अलग मानदंड सही पक्षकारों के लिए लागू किया जाना चाहिए। अनवर जूट स्पिनिंग मिल्स बनाम संघ सरकार/निर्दिष्ट प्राधिकारी का संदर्भ लिया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उत्पादन की लागत और घरेलू उद्योग का संबंधित आंकड़ा गोपनीय प्रकृति का है। घरेलू उद्योग ने भी नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी पर विश्वास किया है।
  - vii. याचिकाकर्ता ने वार्षिक रिपोर्टों की गोपनीयता का दावा नहीं किया है और यह वेबसाइट पर निशुल्क रूप में उपलब्ध है।

### **ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

22. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
  - i. घरेलू उद्योग व्यापार सूचना 10/2018 के अंतर्गत, मानदंडों का उपयुक्त रूप से विश्लेषण नहीं किया है, यह व्यापार सूचना 10/2018 का उल्लंघन करते हुए कुछ निर्दिष्ट मानदंडों के वास्तविक आंकड़ों को उपलब्ध कराने में असफल रहा है। घरेलू उद्योग को यह निदेश दिया जाना चाहिए कि वे मार्च, 2020 के लिए वास्तविक जो अब उपलब्ध है, पर विचार करते हुए, प्रवृत्ति, कार्य-निष्पादन संबंधी मानदंडों और आंकड़ों को फिर से प्रस्तुत करें।

- ii. इस याचिका का अगोपनीय रूपांतर उचित रूप से समझने की अनुमति नहीं देता है और इस नियमावली के नियम 7 और दिनांक 9 दिसंबर, 2013 की व्यापार सूचना सं. 1/2013 में अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है।
- iii. खंड VI (लागत संबंधी सूचना) बिल्कुल ही प्रस्तुत नहीं किया गया है और कोई औचित्य नहीं दिया गया है। बहुत अधिक हद तक आंकड़ों को उचित रूप से एनसीवी में अनुक्रमित नहीं किया गया है अथवा नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ताओं को यह निदेश दिया जाना चाहिए कि वे इन दस्तावेजों को तथा उसका सार/अनुक्रमित आंकड़े उपलब्ध कराएं।
- iv. याचिकाकर्ता ने वार्षिक रिपोर्ट की अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जो सार्वजनिक डोमेन में पहले से ही उपलब्ध है। व्यापार सूचना 1/2013 यह उल्लेख करता है कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से वार्षिक रिपोर्ट और तुलन-पत्र उपलब्ध कराना चाहिए।
- v. प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। गोपनीय के रूप में दावा की गई सूचना व्यापार संवेदनशील है और उसका सारांश नहीं दिया जा सकता है।
- vi. इस जांच को उचित गोपनीयता के संबंध में मुद्दे उठाकर निष्प्रभावी नहीं बनाया जाना चाहिए।
- vii. शानडोंग हुआहोंग केमिकल कं. लि. में इक्विटी के अर्जन का यह मतलब नहीं है कि सेनिक्स कं. लि. में ढांचे में परिवर्तन हुआ है क्योंकि वे दो अलग-अलग कंपनियां हैं। साइनोकेम इंटरनेशनल अपने आप विचाराधीन उत्पाद के साथ शामिल नहीं है।

### ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गयी सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

*"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।*

25. जहां तक अत्यधिक गोपनीयता के दावे के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की और संतुष्ट होने पर गोपनीयता संबंधी दावे की अनुमति दी। प्राधिकारी मानते हैं कि जो सूचना प्रकृति में गोपनीय है (उदाहरण के लिए क्योंकि उसको प्रकट करना प्रतिस्पर्द्धी के लिए काफी प्रतिस्पर्द्धी लाभकारी होगी अथवा क्योंकि इसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर अथवा उस व्यक्ति पर जिससे उस व्यक्ति ने वह सूचना प्राप्त की है, पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा), अथवा किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई है, अच्छा कारण दर्शाए जाने पर प्राधिकारी द्वारा उसी प्रकार मानी जाएगी। वह सूचना उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशेष अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जा सकती।

26. जहां तक जांच की अवधि संबंधी सूचना के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत के बाद, जांच की अवधि के लिए आवेदन की अद्यतित प्रति याचिका द्वारा दायर की गई थी और उसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत् रूप से परिचालित किया गया है। यह स्मरण किया जा सकता है कि **जांच की शुरुआत के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया आवेदन जांच की अवधि के रूप में अप्रैल, 2019 से फरवरी, 2020 की अवधि के लिए सूचना पर आधारित थी क्योंकि मार्च, 2020 के लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना शेष था।** प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम में जांच की अवधि अर्थात् अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 के लिए इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया है।

## च. विविध अनुरोध

### च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. प्रयोक्ता संघ नामतः आल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एआईआरआईए) ने अपने आप को पंजीकृत किया है लेकिन इसके किसी भी सदस्य अथवा संघ ने स्वयं की याचिका के संबंध में कोई टिप्पणियां अथवा अन्य सूचना प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमाओं के भीतर प्रस्तुत नहीं की है।
- ii. कुमहो पैट्रो केमिकल्स द्वारा दी गई सूचना गलत और भ्रामक है। निर्यातक ने घरेलू और निर्यात के लिए एक ही लागत का दावा किया है। लागत कीमत और लाभ के बीच कोई निरंतरता नहीं है।
- iii. लैसेक्स ने उत्तर प्रस्तुत किया है जिसमें खामी है और उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। निर्यातक ने जांच की शुरुआत के बाद 72 दिन दिए जाने के बावजूद पूर्ण उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और वह प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा इसे नोट किए जाने के बाद भी उस खामी को ठीक नहीं कर पाया।
- iv. अत्यधिक शुल्क संरक्षण के संबंध में, घरेलू उद्योग को कोई अत्यधिक संरक्षण नहीं है और पाटनरोधी शुल्क केवल अनुचित व्यापार शुल्क को रोकने के लिए है। प्राधिकारी तभी शुल्क लगाते हैं, जब सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाता है। निर्यातक अनुचित कीमतों पर आदतन निर्यात कर रहे हैं और घरेलू उद्योग को प्राधिकारी के पास जाने से नहीं रोका जा सकता है।
- v. आवेदक ने 28 अप्रैल, 2020 को वर्तमान आवेदन दायर किया। दिनांक 24 जनवरी, 2020 को दायर किया गया आवेदन आवेदक द्वारा वापस ले लिया गया था और उसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।
- vi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क कि अस्वीकार करने के लिए आधार जो 2017-18 में थे, जांच की अवधि में भी हैं, का कोई आधार नहीं है। वर्तमान जांच एक नई जांच है और घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित है कि वह वास्तविक क्षति को स्थापित करे। प्राधिकारी ने यह माना है कि इन आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है और वास्तविक क्षति का खतरा उत्पन्न हो रहा है।
- vii. न्यायालयों से राहत मांगना घरेलू उद्योग का कानूनी अधिकार है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की जहां तक बात है, उसका वर्तमान जांच में कोई संगतता नहीं है।
- viii. नियम 5 की आवश्यकताओं को घरेलू उद्योग द्वारा समुचित रूप से पूरा किया गया है। साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता में जांच में प्रगति होने के बाद सुधार होता है। जांच की शुरुआत के उद्देश्य से पर्याप्त सूचना निर्धारण के उद्देश्य से पर्याप्त नहीं हो सकता है और निर्धारण के लिए अपेक्षित सूचना पर जांच की शुरुआत के समय बल नहीं दिए जाने की जरूरत है। प्रतिवादियों ने इस मामले का संदर्भ लेते समय मेक्सिको-स्टील पाइप्स ऐंड ट्यूब्स में डब्ल्यूटीओ के पैनल के जांच परिणाम जिसमें यह नोट किया गया था कि जांच की शुरुआत के दौरान यह आवश्यक नहीं है कि इस तरह का प्रमाण उपलब्ध हो, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, को उद्धृत नहीं किया।
- ix. पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देशों से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

- x. प्रयोक्ता उद्योग पर संभावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव पूर्ण रूप से बहुत मामूली है।
- xi. इन शुल्कों को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के साथ समाप्त कर दिया गया था और इस कारण से यह याचिका सीईपीए के अनुच्छेद 2.19 के अनुसार दायर की गई है।

## च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. नोसिल 10 वर्षों से अधिक से पीएक्स-13 के संबंध में शुल्क संरक्षण के अधीन रहा है। शुल्कों को एक्सिलरेटर केमिकल्स और अन्य सहायक उत्पादों जैसे ओक्सो-एल्कोहल, एसिक्लिक एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल पर भी लगाया गया है।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा याचिका दायर करने की तिथि में विसंगति है।
- iii. 2011 में पूर्व रक्षोपाय जांच में, नोसिल ने यह तर्क दिया था कि यह शुल्क संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है ताकि यह घरेलू मांग को पूरा करने तथा अपनी लागत को कम करने के लिए भी सक्षम होने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि कर सके। दिनांक 6 जून, 2011 के पीएक्स-13 अथवा 6पीपीडी (रबर केमिकल्स) के भारत में आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच में अंतिम जांच परिणाम में यह संदर्भ उपलब्ध कराया गया था। उसके बाद, रक्षोपाय शुल्क जिसे 2011 में लगाया गया था, की समीक्षा जांच में, घरेलू उद्योग अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए अपने समायोजन योजना के माध्यम से पालन करने में असफल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप रक्षोपाय महानिदेशक ने 2014 में विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क समाप्त कर दिया। दिनांक 24 अप्रैल, 2014 के भारत में पीएक्स-13 अथवा 6पीपीडी(रबर केमिकल्स) पर लगाए गए रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम में संदर्भ दिया गया है।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा 2018 में दायर किए गए निर्णायक समीक्षा आवेदन, जिसमें यह माना गया था कि यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सूचना नहीं थी कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई थी अथवा क्षति होने की संभावना थी, अस्वीकार करते समय डीजीटीआर द्वारा विचार किए गए कारक और परिस्थितियां भी इस समय मौजूद हैं।
- v. वर्तमान जांच में जांच की अवधि के दौरान प्रतिदाय ऐतिहासिक प्रतिदायों की सीमा के भीतर आता है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि संबद्ध देशों से पीयूसी के वर्तमान आयातों के फलस्वरूप प्रतिदायों में गिरावट आ रही है। इसके अलावा, अन्य कारक हैं जिसने घरेलू उद्योग के गिरते हुए कार्य-निष्पादन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है जो संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं हैं।
- vi. याचिकाकर्ता ने दूसरी निर्णायक समीक्षा शुरू करने के लिए प्राधिकारी को विवश करने की सीमा तक जाकर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों को प्राप्त करने के लिए अनेक मंचों का उपयोग किया जब निहित पाटनरोधी अधिसूचना पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.5.2018 को निरस्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक छानबीन के साथ की जानी चाहिए कि अनुकूल सिफारिशें धोखे से प्राप्त न किया जा सके।
- vii. वर्तमान जांच की शुरुआत कानूनी की दृष्टि से सही नहीं और उसे समाप्त किया जाना चाहिए। प्राधिकारी द्वारा लागू की गई समीक्षा का मानक कानून के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। इस याचिका में आरोप अधिकांशतः अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित हैं और याचिकाकर्ता तार्किक निष्कर्ष निकालने में असफल रहा। यूएस-कनाडा से साफ्टवुड लुम्बर, गुआटेमाला-सीमेंट II और मेक्सिको-स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स कस संदर्भ लिया गया था।
- viii. अंतिम पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाते समय वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किए गए कारकों को भी नोट किया जाना चाहिए। पाटनरोधी शुल्क एमएसएमई क्षेत्रों, अंतिम प्रयोक्ताओं, टायर उद्योगों आदि की अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। वर्तमान में बेरोजगारी दर भारत में सबसे अधिक है और एमएसएमई क्षेत्र मुख्य रोजगार सृजक है।

- ix. एक साल के पूर्व नई जांच की शुरुआत सीईपीए के अनुच्छेद 2.19 के संदर्भ में उचित नहीं है।
- x. प्रारंभिक जांच परिणाम कानून की नजर में सही नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार ने प्राधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों और दिए गए जांच परिणामों को स्वीकार नहीं किया और घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों में कोई नया तर्क अथवा साक्ष्य नहीं दिया।
- xi. परिस्थितियों की समग्रता पर विचार किया जाना चाहिए और वर्तमान जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।
- xii. लैसेक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर पूरा नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा इन आरंभिक जांच परिणामों में उल्लिखित छोटी-छोटी कमियों के संबंध में कोई कमी संबंधी जापन जारी नहीं किया गया था।
- xiii. घरेलू उद्योग को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में कुमहो की वास्तविक कच्चे माल की कीमत को अस्वीकार करने के कारण अनुचित रूप से संरक्षण दिया गया है जिसके फलस्वरूप बढ़ा हुआ पाटन मार्जिन भी प्रयोक्ता उद्योग पर बहुत बड़ा भार रहा है।
- xiv. प्रयोक्ता संघ एक हितबद्ध पक्षकार है और इसके पास जांच में भाग लेने के लिए अधिकार है। रिशिरूप लिमिटेड इस संघ का एक सदस्य है और इसने उत्तर दिया है।

### च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

29. जहां तक घरेलू उद्योग को अत्यधिक संरक्षण दिए जाने का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क लगाए जाने के लिए सिफारिश तभी की जाती है जब अपेक्षित कानूनी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। इसके अलावा, किसी निर्धारित उत्पाद पर लगाए जाने वाले अथवा दिए जाने वाले शुल्क की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
30. इस अनुरोध के संबंध में कि इस याचिका में जांच की शुरुआत का औचित्य ठहराने के लिए प्रथमदृष्टया साक्ष्य नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस आवेदन में जांच की शुरुआत के उद्देश्य से संगत सभी सूचना थी। प्राधिकारी ने, इस तथ्य के बारे में संतुष्ट होने के बाद कि इस आवेदन में जांच की शुरुआत का औचित्य ठहराने के लिए पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य दिया गया था, वर्तमान जांच शुरू करने का निर्णय लिया।
31. इस तर्क के संबंध में कि तथ्य और परिस्थितियां जो 2018 में मौजूद थीं, अब भी मौजूद हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का संबंध केवल जांच की अवधि से है और वर्तमान अवधि के दौरान मौजूद कारकों पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया है। वे कारक जो 2018 में मौजूद थे, की वर्तमान जांच में कोई संगतता नहीं है।
32. इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान जांच की शुरुआत एक वर्ष के पूरा होने के पहले की गई थी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के विरुद्ध शुल्कों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इस कारण से, वर्तमान जांच की शुरुआत सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही की गई है।
33. प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में तर्क के बारे में, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि किस प्रकार से पाटनरोधी शुल्क उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताने तथा किस प्रकार से पाटनरोधी शुल्क लगाने से उन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा, की विस्तार से व्याख्या करने के लिए प्रयोक्ताओं के वास्ते सभी प्रपत्रों को उपलब्ध कराने के बावजूद किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को हितबद्ध पक्षकारों ने सिद्ध नहीं किया है। इसके अलावा, यदि इस पर विचार भी कर लिया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है, यह नोट किया जाता है कि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क के द्वारा विशेषकर यदि पाटनरोधी शुल्क की लेवी घरेलू उद्योग को क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक राशि तक प्रतिबंधित नहीं है, कमी नहीं आएगी। पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की परिपाटियों के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को समाप्त करने, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोकने और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करने के लिए है।

34. लैसेस के त्रुटिपूर्ण उत्तर के तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि अपेक्षित सूचना निर्यातक द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद उपलब्ध कराई गई है और उस पर अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
35. जहां तक एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में आल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एआईआरआईए) की स्थिति का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि न तो संघ के किसी सदस्य ने निर्धारित प्रश्नावली प्रस्तुत की है और न ही संघ ने जांच की प्रक्रिया के दौरान कोई सूचना दी है। हालांकि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्यों से उनके अनुरोध पर विचार किया।

## **छ. व्यापार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**

### **छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

36. बाजार अर्थव्यवस्था, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध वस्तुओं की कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे।  
तथापि, इस कारण उपयुक्त तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और इसलिए कि इस उत्पाद का कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है।
  - आवेदक ने उचित लाभ मार्जिन की वृद्धि के साथ उत्पादन की संरचित लागत के आधार पर कोरिया और यूएसए के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किए जाने का दावा किया है क्योंकि एक उपयुक्त तीसरे देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य के संबंध में सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थी।
  - चूंकि यह स्थापित तथ्य है कि कोरिया कुमहो (कोरिया में पीएक्स-13 का एक मात्र ज्ञात विनिर्माता) प्रमुख कच्चा माल 4-एडीपीए की आवश्यकता जो कुल लागत का 70'80 प्रतिशत है, चीन की कंपनियों से पूरा कर रहा है, जैसाकि पहले ही आरंभिक जांच परिणामों में उल्लेख किया गया है, कोरिया की लागत और कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाया नहीं जा सकता है।
  - कोरिया कुमहो की कीमत को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कुमहो को एक विशेष बाजार स्थिति का सामना करना पड़ा है। यह बहुत अधिक अस्वाभाविक है कि कुमहो ने पीएक्स-13 के एक प्रमुख उत्पादक होने और इसके पास 80,000 एमटी की क्षमता होने के बावजूद 4एडीपीए के उत्पादन में कभी भी निवेश नहीं किया। कंपनी को जून, 2012 में पेटेंट भी दिया गया था। कोरिया कुमहो सेनिक्स से 4एडीपीए की खरीद करता है। इसके अलावा, यद्यपि सेनिक्स के लिए कुमहो को आपूर्ति रोकना और बाजार पर कब्जा करना आसान है, फिर भी इसने वैसा नहीं किया है। वर्तमान स्थितियों में प्रमुख कच्चे माल का आयात दर्शाता है कि रिकॉर्ड में बिक्री कीमत स्वाभाविक रूप से गलत तरीके से पेश किया गया है।
  - कुमहो के उत्पादन की लागत को 4एडीपीए जो पीएक्स-13 के उत्पादन में अंतिम मध्यवर्ती है और जिसकी खरीद बढ़ाई गई कीमतों पर की जा रही है, के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।
  - पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) को इस प्रकार से नहीं पढ़ा जा सकता है जिससे यह अर्थ निकले कि अलग-अलग सामान्य मूल्य है और प्राधिकारी का एकमात्र दायित्व अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करना है।
  - संबद्ध निर्यातक द्वारा की गई घरेलू बिक्री सामान्य मूल्य की जांच में सफल नहीं होता है और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इसका त्याग किया जाना चाहिए। प्राधिकारी केवल इस कारण से विचाराधीन लेन-देन पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं हैं क्योंकि वे घरेलू बिक्री कारोबार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - यदि लागतों के कारक भी निर्यातक द्वारा रखे गए रिकॉर्डों पर आधारित हो सकती है तब इसका आशय यह नहीं है कि प्राधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट हुए बिना निर्यातक के उत्पादन की लागत को अपनाने के लिए बाध्य हैं कि क्या वे उत्पादन के साथ संबद्ध लागत और विचाराधीन उत्पाद की बिक्री को तर्कसंगत तरीके से दर्शाते हैं।

- ix. अनुबंध-1 के अंतर्गत एसजीए और लाभ के निर्धारण से संबंधित प्रावधान आगे यह सिद्ध करता है कि संरचित सामान्य मूल्य हमेशा संबंधित उत्पादक के आंकड़ों पर ही आधारित नहीं है और इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण केवल उत्पादक के आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता है।
- x. कोरियाई लागत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब चीन की लागतों को गलत तरीके से दर्शाए जाने के आधार पर अस्वीकार किया जा रहा है और यह बर्ताव कोरिया के उत्पादक जिसमें चीन से अपना अंतिम मध्यवर्ती की खरीद की है, के लिए अलग नहीं हो सकता है।
- xi. लिखित करार व्यापार करने के लिए अनिवार्य नहीं है और इन पक्षकारों की कार्यवाही भी स्पष्ट रूप से इस प्रकार के करार को दर्शाता है। इसके अलावा, कुमहो ने कभी भी करार के होने से इंकार नहीं किया है जब इस मुद्दे को पूर्व की जांचों में भी उठाया गया था। कुमहो द्वारा सेनिक्स अथवा सेनिक्स द्वारा कुमहो को मांग से बहुत अधिक क्षमताएं और बहुत अधिक निर्यातोन्मुखीकरण होने के बावजूद कोई निर्यात नहीं किया गया था, जिससे प्रतिस्पर्धा नहीं करने की उनके बीच गुप्त करार को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।
- xii. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विगत में कुमहो की 4एडीपीए लागत को अस्वीकार किया है और इसे सेस्टैट तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया था।
- xiii. अन्य देशों जैसे यूरोपीय यूनियन की उस स्थिति में कच्चे माल की खपत कीमत को अस्वीकार करने की स्थापित कार्य-पद्धति है जब इनपुट उत्पादन की कुल लागत से 17 प्रतिशत अधिक होता हो और गलत तरीके से दर्शाए जाने का पर्याप्त साक्ष्य हो।
- xiv. कुमहो और सेनिक्स को संबंधित पक्षकार के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि कुमहो अनन्य रूप से 4एडीपीए खरीदता है जो सेनिक्स से लागत का अधिकांश भाग होता है।
- xv. निर्दिष्ट प्राधिकारी तभी सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अनुबंध-1 के पैरा 1-6 का अनुसरण करेंगे, यदि उत्तर देने वाली चीन की कंपनियां यह स्थापित करती हों कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना ऐसी है कि अलग-अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सकता है और अलग-अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार करेंगे।
- xvi. चूंकि चीन के उत्पादकों के पास बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव का हक नहीं है, अतः अनुबंध-1 के पैरा 7 का अनुसरण सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है। चूंकि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य पर नहीं किया जा सका क्योंकि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। आवेदक ने विधिवत् समायोजित भारत में भुगतान योग्य कीमत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
- xvii. प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार करना चाहिए। सामान्य मूल्य किसी मानक पर आधारित नहीं होना चाहिए, चाहे वह सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय कच्चा माल अथवा परिवर्तन लागत के लिए हो।
- xviii. चूंकि लैक्सेस यूएसए विचाराधीन उत्पाद का निर्यात लैक्सेस इंडिया को कर रहा है, अतः यह एक संबंधित पक्षकार का लेन-देन है और इस कारण से इन लेन-देनों की निर्यात कीमत पर विचार निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है। निर्यात कीमत को विधिवत् समायोजित लैक्सेस इंडिया की पुनः बिक्री कीमत से संरचित किए जाने की आवश्यकता है।
- xix. लैक्सेस यूएसए की निर्यात कीमत को समायोजित किया जाना अपेक्षित है क्योंकि भारत में इसके संबंधित पक्षकार ने तरल रूप को फ्लेक्स में परिवर्तित किया है, लैक्सेस इंडिया की बिक्री कीमत घाटे पर चल रही है क्योंकि इसकी बिक्री कीमत आयात कीमतों और परिवर्तन लागतों सहित खरीद लागतों की तुलना में कम है और लैक्सेस यूएसए द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली का उत्तर भी दर्शाता है कि यह जांच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों से घाटे पर भारत को निर्यात कर रहा है।
- xx. संबद्ध देशों का पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तरों से ऊपर है और यह बहुत अधिक तथा वास्तविक है।



- xxi. निर्यात कीमत पर व्यापार समायोजनों, जिसका दावा कुमहो द्वारा इसकी घरेलू बिक्री के लिए किया गया है, के स्तर को सही तरीके से अस्वीकार किया गया है और निर्यातक के तर्क में कानूनी आधार भी नहीं है।
- xxii. दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में, वह गुण-दोष के आधार पर नहीं था। 4एडीपीए कीमतों के अस्वीकरण को सही ठहराने वाला सेस्टेट का आदेश प्राधिकारी पर बाध्यकारी है।
- xxiii. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 की व्याख्या करते समय, पारिभाषिक शब्द “सामान्य रूप से” को ऐसी स्थिति का संदर्भ लेते हुए पढ़ा जाना चाहिए जिसमें किसी निर्यातक की लागतों की गणना निर्यातक अथवा उत्पादक के द्वारा रखे गए रिकॉर्डों के आधार पर किया जा सकता है। इसका आशय यह होता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है, जिसमें निर्यातक अथवा उत्पादक के रिकॉर्डों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन-बायोडीजल में विश्व व्यापार संगठन के पैनल के निर्णय की निर्यातक की व्याख्या सही नहीं है। ब्रोआइलर और मिस्त्र – स्टील रबर में डब्ल्यूटीओ के पैनल की रिपोर्ट का भी संदर्भ लिया गया था।
- xxiv. यूरोपीय यूनियन-बायोडीजल में विश्व व्यापार संगठन के पैनल में यह उल्लेख है कि इस नियम को कुछ शर्तों के अधीन नहीं माना जा सकता है, जिसे बाद में आस्ट्रेलिया -ए4 कॉपी पेपर में पुष्टि की गई थी जिसमें यह भी टिप्पणी की गई थी कि प्राधिकारी ऐसी स्थिति में जहां प्राधिकारी वैसा करने के लिए बाध्यकारी कारण पाते हों, में प्रावधान में उल्लिखित दो शर्तों से अलग कारणों से भी निर्यातकों की लागतों को नहीं मान सकते हैं।
- xxv. चीन जन.गण. को प्राधिकारी द्वारा हाल की सभी जांचों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया है।
- xxvi. भारत ने “करार का पालन अवश्य किया जाना चाहिए” के प्रावधानों के साथ असंगत रूप से कार्यवाही नहीं की है। चीन को केवल घरेलू विनियमों के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना जा रहा है बल्कि चीन के आरोहण नवाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के आधार पर भी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना जा रहा है जो 11 दिसंबर, 2016 के बाद भी कार्य कर रहा है। चीन आरोहण नवाचार के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहा है और बाजार के द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमतों की अनुमति इन गलत कीमतों को दूर करने के लिए असफल रहा जिसके फलस्वरूप डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्य भी जिसमें यूएसए और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं, ने चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानना जारी रखा है।

## छ.2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

37. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निर्यातक/उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- पाटन मार्जिन का निर्धारण उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर और कच्चे माल की वास्तविक खरीद कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। कच्चे माल की खपत कीमत को अस्वीकार करना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 का उल्लंघन करते हुए किया गया है और यूरोपीय यूनियन-बायोडीजल, यूक्रेन-अमोनियम नाइट्रेट में अपीलिय निकाय की रिपोर्टों तथा यूरोपीय यूनियन-लागत समायोजन पद्धति तथा रूस से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क में पैनल की रिपोर्टों का उल्लंघन करते हुए किया गया है – दूसरी शिकायत जो यह उल्लेख करती है कि निर्यातक/उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराई गई कीमतों की तर्कसंगतता का आकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  - यह तथ्य कि चीन के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां हैं, यह नहीं सूचित करता है कि खरीद कीमत को अस्वीकार किया जा सकता है। सेस्टेट की पूर्व की जांच में 4एडीपीए की वास्तविक लागत को अस्वीकार करने को सही ठहराने वाला निर्णय संगत नहीं है क्योंकि यह विश्व व्यापार संगठन के न्याय-शास्त्र के प्रतिकूल है।

- iii. याचिकाकर्ता ने संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पूर्व के अंतिम जांच परिणामों पर विश्वास किया है जिसमें कच्चा माल 4एडीपीए की वास्तविक कीमत को प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि दिनांक 29.4.2014 के अंतिम जांच परिणामों को पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.5.2018 के इसके निर्णय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी के लिए इस पुनः मामले में उसी सिद्धांत को लागू करने का कोई आधार नहीं है।
- iv. जहां तक कुमहो और साइनोकेम के बीच विशेष करार का मुद्दा है, प्राधिकारी ने ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए “सफेद सीमेंट” के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच पूर्व में आयोजित की है कि प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दे प्रतिस्पर्धा आयोग में उठाया जाना है और यह डीजीटीआर के आवश्यक नहीं है कि वह ऐसे मुद्दों की जांच करे।
- v. उत्पादक अथवा निर्यातक द्वारा रखे गए रिकॉर्डों के आधार पर लागत की गणना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अनुसार है। यदि कोरिया के निर्यातक अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत दो शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं तब प्राधिकारी इन उत्पादकों/निर्यातकों के द्वारा रखे गए रिकॉर्डों पर विचार कर सकते हैं। कुमहो की कीमत को केवल इस कारण से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने चीन जन.गण. के लिए कच्चे माल का आयात किया।
- vi. कुमहो ने चीन जन.गण. के एक असंबंधित आपूर्तिकर्ता जो संबद्ध वस्तुओं के एक उत्पादक और निर्यातक के रूप में वर्तमान जांच में भाग भी ले रहा है, से जांच की अवधि के दौरान अधिकांश 4एडीपीए की खरीद की थी। यह वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक नहीं है कि चीन जन.गण. में आधारित कुमहो के प्रतिस्पर्धी कुमहो को प्रमुख कच्चा माल 4-एडीपीए की बिक्री उस कीमत पर करेगा जो बाजार कीमत से कम है और इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड का कोई साक्ष्य नहीं है।
- vii. याचिकाकर्ता के इस तर्क के विपरीत कुमहो का कच्चे माल और संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन अथवा बिक्री के संबंध में एक दूसरे की बिक्री बाजार को सीमित करने अथवा प्रतिस्पर्धा को सीमित करने का कोई स्पष्ट अथवा संसूचित करार अथवा प्रतिबद्धता नहीं है।
- viii. याचिकाकर्ता को कुमहो पर अनुचित रूप से अधिक शुल्कों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है क्योंकि प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में कुमहो द्वारा सूचित की गई 4एडीपीए वास्तविक कच्चा माल की कीमत को अस्वीकार किया है जिसके फलस्वरूप पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई है और इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है और यह पाटनरोधी करार के अनुच्छेद-II का उल्लंघन है।
- ix. प्राधिकारी द्वारा सेस्टेट के निर्णय के आधार पर लागत को अस्वीकार करने के लिए अपनाई गई पद्धति सीमा शुल्क, बंगलौर बनाम जीएम एक्सपोर्ट्स में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर उपयुक्त नहीं है जिसमें यह माना गया था कि जहां किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसरण में संविधि बनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर व्याख्या का अनुसरण पूर्व के घरेलू दृष्टांतों के बजाय किया जाना चाहिए।
- x. प्रतिनिधिक देश की पद्धति का उपयोग इस तथ्य पर विचार किए बिना इस मामले के लिए सामान्य मूल्य की गणना में नहीं किया जाना चाहिए कि क्या चीन को बाजार अर्थव्यवस्था के देश के रूप में माना गया है। भारत का गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का उपयोग करते हुए सामान्य मूल्य की गणना के लिए कोई आधार नहीं है।
- xi. भारत “करार का अवश्य पालन किया जाना चाहिए” से बंधा हुआ है और इसे संगत करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को अवश्य पूरा करना चाहिए और संगत घरेलू विनियमों में संशोधन कर चीन की पूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जा को माना जाना चाहिए।
- xii. घरेलू उद्योग ने यह तर्क नहीं दिया है कि क्या कुमहो कोरिया द्वारा रखे गए रिकॉर्ड कोरिया जन.गण. के जीएएपी के अनुसार है और यदि ऐसा नहीं है तब इसके द्वारा रखे गए और प्रस्तुत किए गए रिकॉर्डों पर विचार किया जाना चाहिए।

- xiii. इनपुट की कीमतों की उपेक्षा की जा सकती है, जब वे कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य की तुलना में कम हों।
- xiv. कोरिया कुमहो के रिकॉर्ड पर विचार किया जाना चाहिए जहां इसका रिकॉर्ड घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के पर्याप्त रूप से अनुरूप सेनिक्स से कच्चा माल 4-एडीपीए का अधिग्रहण करने के लिए प्रदत्त कीमत को दर्शाता हो।
- xv. जांच की गई निर्यातक की लागत उस कीमत को दर्शाती है जिस पर इसने कच्चे माल की खरीद की है और तदंतर विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में लागत वहन की है और यह वास्तविक नहीं है कि क्या इसने चीन जन.गण. जो एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है, से खरीद की है। पहुंच मूल्य का समायोजन करने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है और इस प्रकार का तर्क कानून में मानने योग्य नहीं है।
- xvi. कुमहो और सेनिक्स संबंधित पक्षकार नहीं हैं और उनका संबंध केवल वाणिज्यिक क्रियाकलापों के संबंध में है। वे सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयात की गई वस्तुओं का निर्धारण) नियमावली, 2007 के नियम 2(2) तथा दिनांक 10 मई, 2018 की व्यापार सूचना सं. 9/2018 के अंतर्गत संबंधित पक्षकार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।
- xvii. कोरिया गणराज्य एक बाजार अर्थव्यवस्था है और भारत संगत रूप से कोरिया गणराज्य को शामिल करते हुए पाटनरोधी जांचों में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस अधिनियम के खण्ड 9क(ग) को लागू करता रहा है।
- xviii. घरेलू उद्योग यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि किस प्रकार से कुमहो की घरेलू बिक्री कीमत व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं है और किस प्रकार से कुमहो की लागत को गलत तरीके से दर्शाया गया है और प्रारंभिक जांच परिणामों ने यह निर्णय दिया है कि कुमहो की घरेलू बिक्री व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में है।
- xix. कुमहो का कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता भी वर्तमान जांच में भाग ले रहा है और भारत सहित अनेक बाजारों में कुमहो के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। यह चीन जन.गण. में आधारित एक प्रतिस्पर्धी के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक नहीं है कि वह कुमहो को उस कीमत पर प्रमुख कच्चा माल 4-एडीपीए की बिक्री करे जो बाजार कीमत से कम हो। कुमहो ने जांच की अवधि के दौरान केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित बाजार कीमतों पर 4-एडीपीए की खरीद की थी।
- xx. चीन जन.गण. ने कुमहो और कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता के पास एक दूसरे के बिक्री बाजार को सीमित करने अथवा प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए कच्चे माल और संबद्ध वस्तुओं की बिक्री अथवा उत्पादन के संबंध में कोई स्पष्ट अथवा निहित करार या प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।
- xxi. एनएमई दर्जा की मान्यता अन्य देशों को वास्तविक निर्यात कीमत को अस्वीकार करने का प्रावधान नहीं करता है।
- xxii. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 अथवा पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत कीमत की तर्कसंगतता का आकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xxiii. कुमहो ने सही रूप से वर्तमान मामले में व्यापार समायोजन के स्तर के लिए अनुरोध किया है और उसे प्राधिकारी द्वारा अवश्य अनुमति दी जानी चाहिए।

### छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

39. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके में सूचना उपलब्ध कराएं। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दायर कर इस जांच में सहयोग किया है:

- i. मैसर्स लैक्सेस कारपोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका
- ii. मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
- iii. मैसर्स सेनिक्स कं, लिमिटेड शानडोंग, चीन जन. गण.
- iv. मैसर्स सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, ताइवान, चीन जन. गण.
- v. मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर पीटीई. लिमिटेड
- vi. मैसर्स सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका
- vii. मैसर्स सेनिक्स कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.
- viii. मैसर्स पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, कोरिया

40. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है।

#### **छ.4 सामान्य मूल्य का निर्धारण**

##### **कोरिया में सामान्य मूल्य**

##### **कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि. ("केकेपीसी") अथवा ("कुम्हो")**

41. मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि. ("केकेपीसी") कोरियाई वाणिज्यिक कानून के तहत स्थापित एक सीमित दायित्व कंपनी है। कंपनी ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करते हुए निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।
42. इस उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स केकेपीसी ने घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। यह भी नोट किया जाता है कि केकेपीसी ने भारत को सीधे ही तथा एक असंबद्ध कोरियाई व्यापारी अर्थात् पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। मैसर्स पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन ("पोस्को") ने भी निर्धारित प्रश्नावली प्रपत्र में सभी संगत सूचनाएं दी हैं।

##### **सामान्य मूल्य**

43. मैसर्स केकेपीसी ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री तथा बिक्री लागत के ब्यौरे प्रस्तुत करते हुए निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। जांच की अवधि के दौरान मैसर्स केकेपीसी ने घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है।
44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 4-एडीपीए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में एक प्रमुख कच्ची सामग्री है। याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग और कुम्हो द्वारा दी गई सूचना यह दर्शाती है कि 4-एडीपीए में पीएक्स-13 की कुल

उत्पादन लागत का काफी बड़ा भाग है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 4-एडीपीए का व्यापक तौर पर उत्पादन केवल चीन तथा भारत के उत्पादक द्वारा किया जा रहा है जिसमें कुछ मात्रा का उत्पादन यूरोपीय यूनियन में किया जा रहा है। उत्तरदाता उत्पादक द्वारा दी गई सूचना यह दर्शाती है कि कुम्हो ने अधिकांशतः चीन जन. गण. से 4-एडीपीए लिया है। चीनी उत्पादकों द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर यह दर्शाता है कि वे अपना 4-एडीपीए उत्पादन करते हैं। चीन जन. गण. के उत्तरदाता उत्पादकों ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है।

45. वर्तमान जांच में केपीसी के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के वास्ते विगत पाटनरोधी जांचों में कुम्हो की 4एडीपीए लागत को संगत रूप से अस्वीकार किया है। कोई साक्ष्य अथवा तर्क उपलब्ध नहीं कराया गया है कि वर्तमान जांच में इस स्थिति में उसी देश से इस उत्पाद पूर्व की जांचों से जहां वही सहयोगी उत्पादक और निर्यातक ने भाग लिया था अर्थात् मूल जांच, मध्यावधि समीक्षा जांच और निर्णायक समीक्षा जांचों में कोई प्रमुख परिवर्तन हुआ है। आगे यह नोट किया जाता है कि उसी मुद्दे को माननीय सेस्टेट और उच्चतम न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया है और अब कुम्हो द्वारा सूचित की गई 4एडीपीए लागत के व्यवहार के संबंध में अंतिम फैसला प्राप्त हो गया है। माननीय सेस्टेट का संगत उद्धरण नीचे फिर से प्रस्तुत किया गया है।
46. माननीय सेस्टेट ने 2015(322) ई.एल.टी.514 (ट्राई-डीईएल) के रूप में सूचित किए गए अपने फैसले में निम्नानुसार माना:

*“19. पाटन जांचों में प्राधिकारी इस तथ्य की जांच करने के उद्देश्य से रूटीन तरीके से कीमत और लागत, दोनों से संबंधित सूचना का अनुरोध करते हैं कि क्या घरेलू बिक्री लागत से कम पर की जाती है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में, निर्यात करने वाले देश के घरेलू बाजार में समान उत्पाद की बिक्री उत्पादन की लागत योग एसजीए लागत प्रति इकाई से कम (निर्धारित और परिवर्तनीय) से कम कीमतों पर बिक्री को कीमत के कारण से व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं होने के रूप में माना जाएगा। खंड 9क(1)(ग)(i) के अंतर्गत निर्यात करने वाले देश ने व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में खपत के उद्देश्य से समान वस्तु के लिए तुलनीय कीमत का पता लगाने के उद्देश्य से, उसमें दर्शाई गई कीमत पर संगत अवधि के लिए लेखा/रिकार्ड में दर्शाई गई बिक्री को सामान्य तौर पर तब स्वीकार किया जाएगा जब रिकार्ड तर्कसंगत रूप से ऐसी वस्तु के उत्पादन और बिक्री से संबद्ध लागत को दर्शाता हो। हालांकि जब एक प्रमुख इनपुट का आयात गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से किया जाता है तब रिकार्ड में दर्शाई गई बिक्री कीमत की छानबीन उपयोग की गई इनपुट के गैर बाजार अर्थव्यवस्था कीमत के फलस्वरूप गलत तरीके से दर्शाई गई कीमत का पता लगाने और उसे ठीक करने के लिए किया जाना होगा, जिसकी लागत को उस वस्तु के उत्पादन की गलत तरीके से प्रस्तुत लागत को सही करने के उद्देश्य से तय किया जाना अपेक्षित है। प्राधिकारी रिकार्ड के रूप में दर्शाई गई घरेलू बिक्री कीमत को अस्वीकार करने में सही हैं जब प्रश्नगत इनपुट का उत्पादन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के भीतर किया गया था, क्योंकि ऐसी इनपुट के लिए कीमत को गलत तरीके से पेश किया जाएगा क्योंकि वे सामान्य बाजार अर्थव्यवस्था खरीद कीमत को नहीं दर्शाते हैं। गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं में कीमतों अथवा लागतों को इस आधार पर सामान्य मूल्य की गणना के लिए एक उपयुक्त आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है कि कीमतों और लागतों को सरकार द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है और इस कारण से वे बाजार शक्तियों के अधीन नहीं हैं। चीन से भारत को 4एडीपीए की निर्यात कीमत को भी उसी गलत कीमतों से हानि होगी। इस प्रकार हमारे विचार से, अंतर्राष्ट्रीय कीमत जैसाकि भारत को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से 4एडीपीए के लिए आयात आकड़ों द्वारा दर्शाया गया है, 4एडीपीए के वास्तविक मूल्य का पता लगाने के लिए उचित आधार है.....”*

47. माननीय सर्वोच्च बेंच ने दिनांक 8.5.2015 को कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कं. लि. द्वारा 2015 (322) ई.एल.टी. 514 (ट्राई –डीईएल) (कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी) में सूचित किए गए अनुसार दिनांक 26.12.2014 के सेस्टेट के अंतिम आदेश सं. एडी/ए/54808-54810/2014-सीयू(डीबी) के विरुद्ध 2015 की विशेष अनुमति याचिका (सी) सीसी सं. 8088 के साथ 2015 की अपील (सिविल) सं. 12086-12087 के लिए विशेष अनुमति के वास्ते याचिका का निपटारा किया। इन याचिकाओं का निपटारा करते समय, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“एसएलपी(सी) सं. 12086-12087/2015

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता अनुदेशों पर इस न्यायालय की अनुमति आदेश की सत्यता पर प्रश्न खड़ा करने, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशक द्वारा पारित किया जाए उन सभी तर्कों जो उनके पास उपलब्ध हों, जिनमें इन विशेष अनुमति याचिकाओं में दिए गए तर्क शामिल हों, को लेकर उपयुक्त मंच के समक्ष प्रश्न खड़ा करने के लिए याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता देते हुए, यदि वे वैसा चाहते हों, इन विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस लेने की मांग करते हैं।

48. कुमहो ने पुनः माननीय सेस्टेट के समक्ष रिमांड जांच परिणाम को चुनौती दी, माननीय सेस्टेट ने 2016(342) ई.एल.टी. 573 (ट्राई-डीईएल.) के रूप में सूचित किए गए अनुसार दिनांक 9-9-2016 के अपने अंतिम आदेश सं. एडी/ए/53452-53453/2016-सीयू(डीबी) के माध्यम से अपील खारिज की और निम्नानुसार फैसला दिया:

6. हमने सभी हितबद्ध पक्षकारों के पक्ष को सुना है और लिखित अनुरोधों सहित अपील के रिकॉर्ड का अवलोकन किया। हम नोट करते हैं कि अपील के पहले चरण में, न्यायाधिकरण ने निर्णय के लिए दो मुद्दों की जांच की। पहली अपील सामान्य मूल्य तय करने के लिए 6 पीपीडी (संबद्ध वस्तुओं में से एक) के उत्पादन के लिए लागत संरचना की सत्यता के बारे में थी और परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तुओं पर पाटन मार्जिन और क्षति संबंधी निर्णय के बारे में थी। विस्तृत चर्चा के बाद, न्यायाधिकरण ने यह रिकॉर्ड किया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने साइनोर्गचेम से 4एडीपीए की कीमत को और 4एडीपीए जो 6पीपीडी के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है, की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना के बाद उस कीमत को सही तरीके से अस्वीकार किया। न्यायाधिकरण ने चीन से 4एडीपीए की कीमत को अस्वीकार करने और 4एडीपीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर आधारित सामान्य मूल्य तय करना सही माना। इस कारण से, अपीलकर्ताओं के लिए सामान्य मूल्य संरचित करने में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति से संबंधित मुद्दे अंतिम दौर में पहुंच गए हैं। न्यायाधिकरण के निर्णय को किसी उच्चतर न्यायिक मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है।

49. माननीय उच्चतम न्यायालय की पीठ ने दिनांक 13.2.2017 को कुमहो पेट्रोकेमिकल्स कं. लि. द्वारा 2016 (342) ई.एल.टी. 573 (ट्राई-डीईएल) (रिशिरूप पोलिमर्स प्रा. लि. बनाम संघ सरकार) में सूचित किए गए अनुसार दिनांक 9.9.2016 के सेस्टेट के अंतिम आदेश सं. एडी/ए/53452-53453/2016-सीयू(डीबी) के विरुद्ध दायर की गई 2017 की अपील सं. 3079 के लिए विशेष अनुमति के वास्ते याचिका खारिज कर दी। याचिका को खारिज समय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किए:

“विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है”

50. उपर्युक्त को देखते हुए उसी मुद्दे का निपटारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया गया है और आगे माननीय सेस्टेट और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह फैसला दिया गया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कुमहो द्वारा सूचित की गई 4एडीपीए की खपत कीमत को स्वीकार नहीं किया है।
51. वर्तमान जांच में कुमहो पेट्रोकेमिकल्स उसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था कंपनी से अधिकांश 4एडीपीए मंगा रहा है, जिसके साथ कुमहो पेट्रोकेमिकल्स ने पूर्व में विशेष संबंध होने की सूचना दी थी और कोई तथ्य अथवा साक्ष्य वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष नहीं लगाया गया है कि या तो उक्त कंपनी की स्थिति अथवा दो कंपनियों के व्यापार क्रियाकलापों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूर्व में किए गए निर्धारण के समय से कोई परिवर्तन हुआ है।
52. इस कारण से, यह माना गया है कि उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था कंपनी से केकेपीसी द्वारा 4एडीपीए की वास्तविक खरीद कीमत का उपयोग तर्कसंगत तरीके से पीएक्स-13 (6पीपीडी) के उत्पादन से संबद्ध लागत को दर्शाएगा और इस कारण से, कुमहो पेट्रोकेमिकल्स द्वारा सूचित की गई 4एडीपीए की खपत कीमत को उत्पादन की लागत के निर्धारण के उद्देश्य से अपनाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा, वर्तमान जांच में जांच की अवधि के दौरान बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को 4एडीपीए का कोई आयात नहीं हुआ है। हालांकि, जांच की प्रक्रिया के दौरान, भारत से यूएसए को 4एडीपीए की निर्यात कीमत हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और उसे समुद्री भाड़ा, बीमा और अंतरदेशीय भाड़ा के रूप में समायोजनों को जोड़ने के बाद स्वीकार किया गया है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान 4एडीपीए की प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमत और विचाराधीन उत्पाद के लिए कुमहो के उत्पादन की लागत में तदनुसार संशोधन किया गया है। जैसाकि कुमहो द्वारा दावा किया गया

पीएक्स-13 के उत्पादन की लागत के शेष भाग को स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार से संरचित पीएक्स-13 (6पीपीडी) की बिक्री की संशोधित लागत पर व्यापार की सामान्य प्रक्रिया ("ओसीटी") जांच के लिए के लिए विचार किया गया है।

53. उपर्युक्तानुसार, निर्धारित बिक्री की लागत के आधार पर प्राधिकारी ने साधारण व्यापार प्रक्रिया ("ओसीटी") जांच की है, जो यह दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान की गई 80 प्रतिशत से कम घरेलू बिक्री लाभप्रद थी। तदनुसार, लाभप्रद घरेलू बिक्री पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स केकेपीसी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में केआरडब्ल्यू \*\*\* प्रति कि.ग्रा. (\*\*\*) अमेरिकी डॉलर प्रति कि.ग्रा.) की औसत बीजक कीमत पर संबद्ध वस्तुओं के \*\*\* मी. टन की बिक्री की है।
54. मैसर्स केकेपीसी ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, पैकिंग लागत और व्यापार के स्तर के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केकेपीसी ने प्रस्तुत निर्यात प्रश्नावली के उत्तर में व्यापार समायोजन के स्तर को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त साक्ष्य नहीं दिए हैं। इस कारण से व्यापार समायोजन के स्तर पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया गया है। केकेपीसी द्वारा किए गए अन्य समायोजनों का दावा एक्स-फैक्ट्री स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

### **संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य मूल्य**

#### **i. लैंक्सेस कारपोरेशन**

55. मैसर्स लैंक्सेस कारपोरेशन ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। मैसर्स लैंक्सेस कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोगी उत्पादक और निर्यातक द्वारा दायर आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि उन्होंने द्रव रूप में अपने संबद्ध पक्षकार लैंक्सेस इंडिया को भारत में सीधे ही संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। यह भी नोट किया जाता है कि भारत में संबद्ध पक्षकार ने सामग्री को केवल टुकड़े रूप में बेचा है और इसीलिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के प्रयोजन के लिए टुकड़े से टुकड़े की तुलना करना उपयुक्त माना जाता है। प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि उत्तरदाता ने संबंधित परिशिष्ट में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमत के ब्यौरे दिए हैं। यह भी नोट किया जाता है कि मै. लैंक्सेस कारपोरेशन यूएसए ने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की \*\*\* एमटी की बिक्री की है। इसमें से \*\*\* एमटी द्रव्य है और शेष \*\*\* एमटी बाजार में टुकड़ों में है। उनके उत्तर के आधार पर यह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में घरेलू बाजार में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्री लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया की जांच की है। यदि लाभ अर्जित करने वाले लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हो तब प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के वास्ते घरेलू बाजार में सभी लेन-देन पर विचार किया है। जहां लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम हो, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है। व्यापार की सामान्य प्रक्रिया की जांच के आधार पर, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया गया है क्योंकि यह देखा गया है कि 20 प्रतिशत से अधिक बिक्री उत्पादन की लागत से कम पर हुई है।
56. कारखानाबाह्य सामान्य मूल्य निकालने के लिए प्राधिकारी ने उत्तरदाता उत्पादक की बीजक कीमत से अंतर्देशीय भाड़ा और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों (अमेरिकी डॉलर/ मी. टन में) पर विचार किया है। तदनुसार, कारखानाबाह्य सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है और पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

#### **ii. संयुक्त राज्य अमेरिका में असहयोगी निर्यातक**

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी भी अन्य निर्यातक/ उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी असहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए प्राधिकारी तथ्यों और सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से निर्धारित करते हैं और वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

### चीन में सामान्य मूल्य

#### चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति

58. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद- VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

59. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, तथापि अभिगम नयाचार के 15 (क) (i) के तहत दायित्वों के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/ आंकड़ों के माध्यम से पूरा किए जाने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित



मानदंड की अपेक्षा है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/ निर्यातक ने निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

60. तदनुसार, संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित किया गया है।

#### **चीन जन. गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य**

61. चूंकि, चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने आंकड़ों/ सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जो कि निम्नलिखित रूप में पठित है :

*“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”*

62. यह नोट किया जाता है कि उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद की कीमत तथा निर्मित मूल्य अथवा उस तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमतें न तो आवेदक द्वारा और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और न ही प्राधिकारी के पास किसी सार्वजनिक स्रोत से उपलब्ध हैं, इस प्रकार सामान्य मूल्य लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित, भारत में प्रदत्त एवं देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है जो बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उपयुक्त लाभ के लिए जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दिया गया है।

#### **छ.5 निर्यात कीमत का निर्धारण**

##### **कोरिया गणराज्य**

##### **कुम्हो पैट्रोकेमिकल कं. लि.**

63. जांच की अवधि के दौरान, मैसर्स केकेपीसी ने भारत को सीधे ही तथा असंबद्ध कोरियाई व्यापारी अर्थात् पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से केकेपीसी को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। मैसर्स केकेपीसी और मैसर्स पोस्को ने अपेक्षित प्रपत्र में सभी संगत सूचनाएं दी हैं। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मैसर्स केकेपीसी ने भारत को \*\*\* मी. टन का निर्यात केआरडब्ल्यू \*\*\* प्रति कि.ग्रा. (\*\*\*) अमेरिकी डॉलर प्रति कि. ग्रा.) की औसत बीजक कीमत पर किया है।
64. मैसर्स केकेपीसी ने अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, पत्तन एवं अन्य संबद्ध खर्चों, विदेशी बीमा, सीमा शुल्क दलाल शुल्क, कमीशन खर्च, पैकिंग व्यय, ऋण लागत, बैंक प्रभार और शुल्क वापसी के निमित्त समायोजनों का दावा किया है तथा प्राधिकारी द्वारा शुल्क वापसी को छोड़कर उसकी अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। निर्धारित कारखानाबाह्य निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

कोरिया से असहयोगी निर्यातकों के लिए

65. कोरिया से किसी भी अन्य निर्यातक के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आगे की जांच होने तक अनंतिम रूप से निर्धारित की गई है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस में सूचित किए गए अनुसार और उत्तरदाता उत्पादक एवं निर्यातक के प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार आयातों पर अनंतिम रूप से विचार किया है। निर्धारित कारखानाबाह्य निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

संयुक्त राज्य अमेरिकालैंक्सेस कारपोरेशन

66. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में उत्पादक/ निर्यातक ने उल्लेख किया कि जांच की अवधि के दौरान उन्होंने भारत में अपने संबद्ध पक्षकार को सीधे ही \*\*\* मी. टन का निर्यात किया। भारत में संबद्ध आयातक ने संबद्ध सामानों के द्रव रूप को टुकड़े रूप में परिवर्तित किया है और इसीलिए प्राधिकारी ने परिवर्तन लागत के निमित्त आवश्यक समायोजन किए हैं। चूंकि, उनकी संबद्ध सामानों की बिक्री कीमत उनकी खरीद कीमत से कम है, जिसमें आयात कीमतें और परिवर्तन लागत शामिल है, अतः उनकी पहुँच कीमत और निवल निर्यात कीमत से उपयुक्त समायोजन किए हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अंतर्देशीय भाड़ा, विदेशी भाड़ा, समुद्री भाड़ा, ऋण लागत और अंतर्देशीय परिवहन के निमित्त सत्यापन के अध्यक्षीन निर्यातक द्वारा दावा किए गए समायोजन को अनंतिम रूप से स्वीकार किया है। तदनुसार, निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है। निर्धारित निर्यात कीमत ठोस एवं पैकड सामग्री के संबंध में लैंक्सेस यूएसए की कारखानाबाह्य निर्यात कीमत के रूप में मानी गई है। अतः उसकी तुलना लैंक्सेस यूएसए द्वारा बेची गई ठोस एवं पैकड सामग्री के सामान्य मूल्य से की गई है। निर्धारित कारखानाबाह्य निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में असहयोगी निर्यातकों के लिए

67. संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी निर्यातक के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस में सूचित तथा उत्पादक एवं निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर में सूचित किए गए अनुसार आयातों पर अनंतिम रूप से विचार किया है। निर्धारित कारखाना बाह्य निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

चीन जन. गण.

सेनिक्स कं. लि., शानडोंग, चीन. जन. गण. (उत्पादक), सेनिक्स कं. लि., शंघाई, चीन जन. गण. (निर्यातक), मैसर्स सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका (निर्यातक) और मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर (निर्यातक) की निर्यात कीमत

68. सेनिक्स कं. लि., शानडोंग (जिसे यहां बाद में "सेनिक्स शानडोंग" अथवा "कंपनी" के रूप में संदर्भित किया गया है) चीनी कानून के तहत चीन में निगमित एक सीमित दायित्व कंपनी है। सेनिक्स शानडोंग, सेनिक्स कं. लि. ("सेनिक्स शंघाई") के 100 प्रतिशत स्वामित्व में है।
69. यह नोट किया जाता है कि सेनिक्स कं. लि., शानडोंग, चीन. जन. गण. (उत्पादक) और सेनिक्स कं. लि., ताइवान (उत्पादक), चीन जन. गण. ने अपनी संबद्ध कंपनियों अर्थात् सेनिक्स कं. लि., शंघाई, चीन जन. गण., सेनिक्स सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर और सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। अपने प्रश्नावली के उत्तर में, मैसर्स सेनिक्स कं. लि., शानडोंग और मैसर्स सेनिक्स कं. लि., ताइवान, चीन जन. गण. ने घोषित किया है कि इन कंपनियों ने मैसर्स सेनिक्स कं. लि., शंघाई, चीन जन. गण. के माध्यम से भारत को उनके द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है।

सेनिक्स कं. लि., शानडोंग, चीन. गण. (उत्पादक)

सेनिक्स कं. लि., शानडोंग, चीन. जन. गण. (उत्पादक), सेनिक्स कं. लि., शंघाई, चीन जन. गण. (निर्यातक), मैसर्स सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका (निर्यातक) और मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर पीटीई. लि., सिंगापुर (निर्यातक) की निर्यात कीमत

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स सेनिक्स कं. लि., शानडोंग, चीन. जन. गण. ने मैसर्स सेनिक्स कं. लि., शंघाई के माध्यम से भारत को जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का \*\*\* मी. टन निर्यात किया है जिसमें से मैसर्स सेनिक्स कं. लि., शंघाई ने भारत को सीधे ही \*\*\* मी. टन का निर्यात किया है, भारत को \*\*\* मी. टन और \*\*\* मी. टन का निर्यात क्रमशः मैसर्स सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका और मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर के माध्यम से किया गया है।
71. यह नोट किया गया है कि सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका और मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर ने भारत को विचाराधीन उत्पाद की निर्यात बिक्री में हानियां सूचित की हैं। सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका और मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर द्वारा दर्शाई गई हानियों की सीमा तक निर्यात कीमत समायोजित की गई है।
72. प्राधिकारी ने कारखानाबाह्य स्तर पर भारित औसत निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन एवं अन्य संबद्ध खर्चों, ऋण एवं बैंक प्रभार के निमित्त समायोजन किए हैं। प्राथमिक जांच परिणामों के लिए किए गए दावों के अध्यधीन स्वीकार किया गया है। निर्धारित कारखाना बाह्य निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

#### **सेनिक्स कं. लि., ताइवान, चीन जन. गण. (उत्पादक)**

सेनिक्स कं. लि., ताइवान, चीन. जन. गण. (उत्पादक), सेनिक्स कं. लि., शंघाई, चीन जन. गण. (निर्यातक), मैसर्स सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका (निर्यातक) की निर्यात कीमत

73. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मैसर्स सेनिक्स कं. लि., ताइवान, चीन. जन. गण. ने मैसर्स सेनिक्स कं. लि., शंघाई के माध्यम से भारत को जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का \*\*\* मी. टन निर्यात किया है जिसमें से मैसर्स सेनिक्स कं. लि., शंघाई ने भारत को सीधे ही \*\*\* मी. टन का निर्यात किया है और भारत को \*\*\* मी. टन तथा \*\*\* मी. टन का निर्यात मैसर्स सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से किया गया है।
74. यह नोट किया गया है कि सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका और मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर ने भारत को विचाराधीन उत्पाद की निर्यात बिक्री में हानियां सूचित की हैं। सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका और मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर द्वारा दर्शाई गई हानियों की सीमा तक निर्यात कीमत समायोजित की गई है।
75. प्राधिकारी ने कारखानाबाह्य स्तर पर भारित औसत निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन एवं अन्य संबद्ध खर्चों, ऋण एवं बैंक प्रभार के निमित्त समायोजन किए हैं। प्राथमिक जांच परिणामों के लिए किए गए दावों को दायर सूचना के सत्यापन के अध्यधीन स्वीकार किया गया है। निर्धारित कारखाना बाह्य निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

#### **चीन जन. गण. के असहयोगी निर्यातकों के लिए**

76. चीन के किसी भी निर्यातक के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आगे की जांच होने तक अनंतिम रूप से निर्धारित की गई है। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस में सूचित तथा उत्पादक एवं निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर में सूचित किए गए अनुसार आयातों पर अनंतिम रूप से विचार किया है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

#### **च.6 पाटन मार्जिन का निर्धारण**

77. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच में कई सहयोगी उत्पादक तथा निर्यातक एक-दूसरे से संबद्ध हैं तथा संबद्ध कंपनियों का एक समूह बनते हैं। प्राधिकारी की यह सतत् परिपाटी रही है कि वे संबद्ध निर्यातक उत्पादकों तथा निर्यातकों को पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एक एकल कंपनी मानें और इस प्रकार उनके लिए एकल पाटन मार्जिन स्थापित करें। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि अलग पाटन मार्जिन परिकलित करने से पाटनरोधी उपायों की प्रवंचना को प्रोत्साहन मिल सकता है जिससे वे अप्रभावी हो सकते हैं और जिससे संबद्ध निर्यातक उत्पादक न्यूनतम अलग पाटन मार्जिन से कंपनी के माध्यम से भारत को अपने निर्यातों का जरिया बना सकते हैं।

78. उपर्युक्त के अनुसार, चीन जन. गण. के संबद्ध उत्पादकों/ निर्यातकों को एकल कंपनी माना गया है और एकल पाटन मार्जिन दिया गया है जो सहयोगी संबद्ध उत्पादकों एवं निर्यातकों के पाटन मार्जिन के भारत औसत के आधार पर परिकलित किया गया था।
79. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन अनंतिम रूप से नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित किया गया है :

पाटन मार्जिन तालिका

देश	उत्पादक/ निर्यातक	सामान्य मूल्य/ सीएनवी (अमे. डॉ./ मी. टन)	निर्यात कीमत (अमे. डॉ./ मी. टन)	पाटन मार्जिन अमे. डॉ./ मी. टन	भारत औसत पाटन मार्जिन	भारत औसत पाटन मार्जिन %	रेंज
चीन जन. गण.	सेनिक्स कं. लि., शानडोंग	***	***	***	***	***	30-40
	सेनिक्स कं. लि., ताइवान	***	***	***	***	***	30-40
	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	***	50-60
कोरिया गणराज्य	कुम्हो पैट्रोकेमिकल कं. लि.	***	***	***	***	***	20-30
	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	***	40-50
संयुक्त राज्य अमेरिका	लैक्सस कारपोरेशन	***	***	***	***	***	10-20
	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	***	10-20

**ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच**

**ज. 1. घरेलू उद्योग के अनुरोध**

80. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं :

- क. संबद्ध देशों से वस्तुएं घरेलू उद्योग की समान वस्तुओं के साथ सीधे ही प्रतिस्पर्धा करती हैं और इसीलिए आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करना ही उपयुक्त है।
- ख. उत्पाद के लिए मांग 2017-18 में बढ़ी, 2018-19 में आंशिक रूप से घटी और जांच की अवधि में उसमें और गिरावट आई। संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में पूर्ण दृष्टि से वृद्धि हुई और जब मांग में गिरावट के कारण पूर्व वर्ष से तुलना की गई तो जांच की अवधि में गिरावट आई। संबद्ध देशों से आयातों में तुलनात्मक दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- ग. संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है। संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों का हास हो रहा है। इसके अलावा, कम कीमत पर बिक्री/ क्षति मार्जिन सकारात्मक है और पर्याप्त है।
- घ. संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में, लैक्सस यूएसए भारत में अपने संबद्ध पक्षकार अर्थात् लैक्सस इंडिया को निर्यात करता है और इसीलिए आवेदक की बिक्री कीमत पर घरेलू उद्योग द्वारा यूएसए से आयातों की पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए लैक्सस इंडिया की पुनः बिक्री कीमत के रूप में विचार किया गया है।

- ड. क्षमताएं पूरी क्षति अवधि में स्थिर थीं और माल सूची में गिरावट आई। उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में जांच की अवधि में गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में उत्पाद की बिक्री करने में असमर्थता के कारण हानियों में निर्यात किया।
- च. संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में गिरावट आई है।
- छ. लाभप्रदता में गिरावट आई और घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में काफी वित्तीय हानियों का सामना किया और इसके प्रभावस्वरूप पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता कमजोर हुई है। नकद लाभ, पीबीआईटी, आरओसीई जांच की अवधि में नकारात्मक हैं। यह भी कोरिया तथा चीन से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने के कारण है। घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच की अवधि में नकारात्मक है।
- ज. संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा पैदा करते हैं। और पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं।
- झ. निर्यातकों के कार्य-निष्पादन मापदंड भारत को निर्यातों में वृद्धि के संदर्भ में घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति और पर्याप्त क्षति की आशंका प्रकट करते हैं। भारत निर्यातकों के लिए एक आकर्षक बाजार है।
- ञ. पाटन घरेलू उद्योग को क्षति होने का एक मात्र कारक होना जरूरी नहीं और घरेलू उद्योग को केवल “एक” कारणात्मक संबंध स्थापित करने की जरूरत नहीं है।
- ट. निर्यात बिक्रियों में घरेलू उद्योग की कुल बिक्रियों का केवल 13 प्रतिशत शामिल है। घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अधिक मात्रा में बिक्री करने में अपनी असमर्थता को देखते हुए निर्यात करने के लिए विवश था। चयन अथवा तरजीह की बाजार निर्यात विवशता से अधिक है।
- ठ. घरेलू उद्योग ने वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा है कि पाटन के कारण क्षति हो रही है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने बिना यह प्रमाणित किए वार्षिक रिपोर्ट का हवाला दिया है कि कैसे यह विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है अथवा संगत है। वार्षिक रिपोर्ट में सार्वजनिक वितरण इस निष्कर्ष को नहीं बदलते कि उत्पाद के ने घरेलू उद्योग की क्षति में योगदान दिया है।
- ड. एक नई जांच में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार करने के लिए कोई कानूनी जरूरत नहीं है।
- ढ. जहां तक कूड कीमतों में गिरावट का संबंध है, विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बिक्री कीमत और लागत, दोनों में गिरावट आई है, बिक्री कीमत में गिरावट लागतों में गिरावट से अधिक थी। यह इस कारण से है कि आयातों की पहुंच कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान लागत से कम थी।
- ण. एनआईपी की गणना अनुबंध-III के अनुसार की गई है।
- त. हितबद्ध पक्षकार चुनिंदा रूप से वार्षिक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। इसके अलावा, रासायनिक संयंत्रों में अचानक से हुई वृद्धि चीन के संबंध में है न कि भारत के संबंध में।
- थ. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिफल दर पर विचार किए बिना सभी स्थितियों में और विगत कई वर्षों से 22 प्रतिशत आरओसीई की अनुमति दी गई है। 22 प्रतिशत की दर वास्तविक दर से कम है।
- द. लैंक्सेस ने अपने लिखित अनुरोधों में वर्तमान आवेदन का समर्थन किया है। अन्य कारकों की घरेलू उद्योग द्वारा पहले ही जांच की गई है।
- ध. अंतिम रूप से यह पाया गया कि यूएसए से आयातों के कारण भी क्षति हो रही है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त है।

## ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

81. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :

- क. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि अर्थात् मार्च, 2020 के अंतिम माह के लिए वास्तविक आंकड़ों पर विचार नहीं किया है। इसके बजाए, क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए आंकड़ों को वार्षिकीकृत किया है। इसके परिणामस्वरूप, सबसे हाल की अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति का विश्लेषण करने के लिए घरेलू उद्योग की याचिका में अपर्याप्त सूचना है।

- ख. चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से पीएक्स-13 के आयात पर पाटनरोधी शुल्क 24 जुलाई, 2019 तक विद्यमान था। इस प्रकार, जांच की अवधि से पूर्व विचाराधीन उत्पाद के आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति इस प्रकार का शुल्क लगाए जाने के कारण बेअसर हो गई होती।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि हाल की अवधि अर्थात् जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा में गिरावट है। इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ता उद्योग मांग-आपूर्ति अंतराल के कारण आयात करने के लिए मजबूर है।
- घ. चूंकि घरेलू उद्योग पूरी मांग को पूरा करने में असमर्थ है, जो कि क्षति की अवधि में बढ़ी है, अतः उसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई। इसी प्रकार, जब विचाराधीन उत्पाद की मांग में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा खुद ही स्वीकार किया गया है, तो उसके परिणामस्वरूप उस अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के आयातों में कमी आई।
- ङ. सापेक्ष दृष्टि से अधिकतम वृद्धि पाटनरोधी शुल्क वाले देशों, अर्थात् यूरोपीय संघ ("ईयू") से देखी जा सकती है जो कि वर्तमान जांच में संबद्ध देशों से काफी अधिक है।
- च. क्षति की अवधि के दौरान कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक पहुँच मूल्य 48 प्रतिशत तक बढ़ा है जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि से काफी अधिक है।
- छ. घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग 2018-19 तक लगातार बढ़ा है। जांच की अवधि (क) के लिए दिए गए आंकड़े अनुमानित आंकड़ों पर आधारित हैं, अतः उनकी मार्च, 2020 के लिए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पुष्टि की जानी चाहिए।
- ज. घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट अनुभव की गई है।
- झ. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में बढ़ा है।
- ञ. घरेलू उद्योग की ब्याज लागत और मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय जांच की अवधि (क) के दौरान बढ़े हैं।
- ट. भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आर्थिक मंदी के कारण विचाराधीन उत्पाद की मांग/ खपत में गिरावट थी। इस प्रकार, इन कारकों से वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है और घरेलू उद्योग को हानियों का संभावित कारण हो सकता है।
- ठ. निर्यात बिक्री से हानियां पाटनरोधी जांच में क्षति विश्लेषण का भाग नहीं हो सकती और उन्हें वर्तमान विश्लेषण में मानदंडों से अलग किया जाना चाहिए।
- ड. घरेलू उद्योग का प्रमुख उत्पादन निर्यात बिक्रियों में उपयोग में लाया जाता है और यह घरेलू उद्योग को हुई हानियों, यदि कोई हैं, में योगदान करने का एक कारण है। घरेलू उद्योग ने मांग-आपूर्ति अंतराल के बावजूद संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के लिए कारण स्पष्ट नहीं किए हैं।
- ढ. जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा में वृद्धि भारत में घरेलू आपूर्ति के अभाव के कारण हो सकती है जो निर्यात बाजारों के प्रति घरेलू उद्योग के आकर्षण के कारण है।
- ण. विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमतें विश्व भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण जांच की अवधि में गिरी हैं जिससे कच्ची सामग्री की लागत 40 प्रतिशत तक कम हुई है जिसे घरेलू उद्योग ने अपनी 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट में खुद ही स्वीकार किया है। तथापि, घरेलू बिक्री कीमत अब भी कच्ची सामग्री लागत में भारी कमी के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में 2018-19 में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाती है।
- त. अनुरोध है कि संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों को चीन और कोरिया से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण क्षति हो रही है। यह भी अनुरोध है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित संबद्ध सामान चीन और कोरिया की तुलना में काफी अधिक कीमत पर हैं और इसीलिए भारत में घरेलू उत्पादकों को क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं।
- थ. घरेलू उद्योग पाटनरोधी एवं रक्षोपायों के माध्यम से 10 वर्षों से संरक्षण का दावा करता आ रहा है जिसके बावजूद वह मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है।

- द. घरेलू उद्योग को संयुक्त राज्य अमेरिका के आयातों से कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि (क) संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात चीन तथा कोरिया से कीमतों पर हैं, (ख) आयात द्रव रूप में हैं, जिसे भारत में टुकड़ों (फ्लेक्स) में परिवर्तित किया जाता है, (ग) द्रव पीएक्स-13 का बहुत ही कम बाजार हिस्सा है, (घ) घरेलू उद्योग को कोरिया गणराज्य और चीन जन. गण. से आयातों के कारण हानियां और घाटे हो रहे हैं, (ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात प्रतिस्पर्धी रहे हैं। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों को जांच से अलग किया जाना चाहिए।
- ध. घरेलू उद्योग द्वारा वर्ष 2018 में दायर पूर्व निर्णायक समीक्षा शुरू नहीं की गई थी क्योंकि क्षति की कोई संभावना नहीं थी और अनंतिम शुल्क उसकी प्रवंचना में होगा। शुल्क लगाना प्रयोक्ताओं को हित में पूर्वाग्रहयुक्त होगा।
- न. उत्पाद की कीमतें मंदी, बेहतर उपलब्धता, सीआईएफ कीमतों और इनपुट कीमतों में सामान्य गिरावट के कारण कम हुई हैं। ओईएम उद्योग में मंदी से प्रमुख टायर कंपनियों का क्षमता उपयोग प्रभावित हुआ है। घरेलू उद्योग की मूल्यहास लागत, ब्याज लागत, छोड़ने के अवसर की लागत में वृद्धि, ऑटो उद्योग में मांग में गिरावट आदि से लाभप्रदता में गिरावट आती है। साथ ही, घरेलू उद्योग क्षमता विस्तार की योजना बना रहा है।
- प. कीमत कटौती की रेंज (15-25 प्रतिशत) समाप्त एसएसआर जांच में रेंज से कम है। आयातों की वर्तमान कीमतें (बिना पाटनरोधी शुल्क) घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रही है, जांच की अवधि में कीमत कटौती रेंज 2017-18 में प्रचलित कीमत से कम है।
- फ. आपूर्ति के अभाव के कारण आयात बड़े हैं। निर्यातानुमुखता में वृद्धि हुई है जबकि क्षमता वही रही।
- ब. पीएक्स-13 के लिए जांच की अवधि में प्रतिफल 15 प्रतिशत है। जांच की अवधि के दौरान प्रतिफल ऐतिहासिक प्रतिफल की रेंज में नहीं आता और यह नहीं कहा जा सकता कि संबद्ध आयातों के कारण प्रतिफल में गिरावट आ रही है।
- भ. नोसिल के एमडी द्वारा दिनांक 03.02.2021 को हुई कांग्रेस काल के अनुसार जांच की अवधि के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों में सुधार आया है।
- म. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने की कोई आशंका नहीं है।
- य. घरेलू उद्योग के समक्ष आयातों की मात्रा, कीमत कटौती और हानियों के बीच कोई कारणात्मक संबंध की समस्या नहीं है। क्योंकि घरेलू उद्योग की कीमत कटौती और लाभ मापदंडों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।
- र. कीमत कटौती ऊंची कीमतों पर फिक्स हुई थी।
- ल. लाभप्रदता में गिरावट आने का कारण असामान्य घटनाएं जैसे संयंत्रों का बंद होना, रासायनिक संयंत्रों में विस्फोट होना और कोविड-19 के कारण से है।
- व. 22 प्रतिशत आरओसीई का अनुमान आयात बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है, न कि यह कानून के अनुसार है और घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ प्रदान करता है।
- श. नोसिल के खिलाफ लैंक्सेस द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की कारणात्मक संबंध का विश्लेषण करते समय जांच की जानी चाहिए। उत्पादकों की उनके बीच ही गहन प्रतिस्पर्धा है, जिससे नोसिल को क्षति हुई है।
- ष. चीन जन.गण. और कोरिया से आयातों के कारण घरेलू उत्पादकों को क्षति हो रही है।
- स. यूएसए से निर्यात कीमत चीन को कोरिया से काफी अधिक है और घरेलू उत्पादकों को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। आंकड़ों की जांच यह दर्शाती है कि लैंक्सेस यूएसए से निर्यात कीमत से आवेदक को भी कोई क्षति नहीं हुई है।
- ह. घरेलू उद्योग ने इस प्रकार की इच्छा की घोषणा किए जाने के बाद भी एक दश में अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं की है। घरेलू बाजार में 100 प्रतिशत उत्पादन की बिक्री करने की बजाय, वह निर्यात बाजार की पूर्ति करने पर ध्यान दे रहा है।
- क्ष. यह माना जा सकता है कि घरेलू उद्योग की निर्यात बाजार में आयातों के पास कुछ व्यवस्थाएं हैं और वह घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने का इच्छुक नहीं है।

- त्र. भावी योजनाओं के संबंध में कंपनियों द्वारा किए गए दावों में परिवर्तन की संभावना है अथवा पूरे नहीं किए जाएंगे लेकिन इससे आयातक के आकड़ों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

### ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

82. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों तथा प्रति-तर्कों पर ध्यान दिया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का इसके अंतर्गत समाधान करता है।
83. जहां तक शामिल पूंजी पर प्रतिफल के रूप में 22 प्रतिशत के तर्क पर विचार करने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के तहत एनआईपी का निर्धारण किया है।
84. जहां तक जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए सूचना पर विचार करने के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच चूंकि एक नई जांच है, अतः जांच की अवधि के बाद की सूचना पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है।

### ज.3.1 संचयी मूल्यांकन

85. नियमावली के अनुबंध-II पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है कि:
- प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन का मार्जिन दो प्रतिशत से अधिक निर्यात की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, आयात सार्वजनिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए होता है, और
  - आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।
86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:
- संबद्ध सामान संबद्ध देशों से भारत में पाटित किए जा रहे हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन के मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक हैं।
  - प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।
  - आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात उनमें से प्रत्येक द्वारा पेश समान वस्तुओं के साथ सीधे ही प्रतिस्पर्धा नहीं करते बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश समान वस्तुओं से भी करते हैं। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग से खरीदने वाले उपभोक्ता भी संबद्ध देशों से आयात कर रहे हैं।
87. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त मानते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यहां तक कि यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यातक ने द्रव रूप में उत्पाद की आपूर्ति की, तथापि संबद्ध आयातक द्वारा संभावित रूप से ठोस रूप में बिक्री की गई है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगा है और इसीलिए उसके पास उत्पाद को ठोस में परिवर्तित करने के लिए सभी सुविधाएं हैं। उपभोक्ताओं ने अंततः ठोस रूप में ही उत्पाद की खपत की है।
88. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना



में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

### ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

#### क. मांग का मूल्यांकन/ स्पष्ट खपत

89. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों की मात्रा के रूप में विचार किया है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	POI
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	117	107	92
अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	113	108	83
संबद्ध देश	मी.टन	5,812	6,797	7,455	7,191
शुल्क लगने वाले देश – यूरोपीय संघ	मी.टन	1,197	2,440	2,591	2,320
अन्य देश	मी.टन	0	0	10	312
कुल भारतीय मांग	मी.टन	21,130	25,577	25,184	22,411
	सूचीबद्ध	100	121	119	106

90. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामान के लिए मांग जांच की अवधि में आंशिक गिरावट के साथ क्षति की अवधि में बढ़ी है। संबद्ध सामानों की समग्र मांग में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

#### ख. संबद्ध देशों से आयात मात्रा में वृद्धि

91. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। वास्तविक स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संबद्ध देश	मी. टन	5,812	6,797	7,455	7,191
चीन	मी. टन	2,004	3,537	3,882	3,749
कोरिया	मी. टन	2,657	2,170	1,342	2,085
संयुक्त राज्य अमेरिका	मी. टन	1,152	1,090	2,231	1,357
शुल्क लगने वाले देश – यूरोपीय संघ	मी. टन	1,197	2,440	2,591	2,320
अन्य देश	मी. टन	0	0	10	312
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
उत्पादन	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	95	105	135
खपत	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	97	108	117

92. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 2018-19 तक वृद्धि हुई है, परंतु जांच की अवधि के दौरान उनमें आंशिक गिरावट आई है। तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के समग्र आयातों में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में कुल भारतीय उत्पादन तथा खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।

### ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

93. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतें कम करने अथवा कीमत की वृद्धि रोकने के लिए अन्यथा है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुँच कीमत से की गई है।

#### क) कीमत कटौती

94. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुँच मूल्य के साथ की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश के पाटित आयातों के कटौती प्रभाव निम्नलिखित रूप में आते हैं :

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
निवल बिक्री वसूली	₹/ कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	131	132	104
<b>चीन</b>					
पहुँच कीमत	₹/ कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	₹/ कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	40-50	30-40	40-50	20-30
<b>कोरिया</b>					
पहुँच कीमत	₹/ कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	₹/ कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	50-60	30-40	20-30	20-30
<b>संयुक्त राज्य अमेरिका</b>					
पहुँच कीमत	₹/ कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	₹/ कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20	40-50	10-20	(0-10)

संबद्ध देश					
पहुँच कीमत	₹/ कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	₹/ कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	40-50	30-40	20-30	10-20

95. यह देखा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर आ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हो रही है। संचयी आधार पर, संबद्ध देशों से कीमत कटौती मार्जिन सकारात्मक है।
96. जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात लैक्सेस इंडिया द्वारा किए गए हैं जिन्होंने द्रव रूप में सामग्री का आयात किया है, उसे ठोस रूप में प्रसंस्कृत किया है और उसके बाद उसे भारत में बेचा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से इस तथ्य के कारण कीमत कटौती नकारात्मक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातक अधिक कीमत पर भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात करते हैं और भारतीय बाजार में उनके संबद्ध पक्षकारों की बिक्री कीमत उस कीमत लागत से कम है जिसमें द्रव पीएक्स-13 की आयात कीमतें और द्रव से भारतीय प्रयोक्ता के लिए टुकड़े में द्रव से परिवर्तन लागत शामिल है। इस प्रकार, उनकी पहुँच कीमत से उपयुक्त समायोजन किया गया है। अतः, यह नोट किया जाता है कि डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों में रिकार्ड की गई आयात कीमत भारतीय बाजार में संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यातकों की वास्तविक विद्यमान कीमत नहीं दर्शा रही है।

#### ख) कीमत न्यूनीकरण/ ह्रास

97. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का काफी मात्रा तक न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हो गई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है :

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि*
बिक्रियों की लागत	₹./ कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	93	109	106
बिक्री कीमत	₹./ कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	131	132	104
पहुँच मूल्य (संबद्ध देश)	₹./ कि.ग्रा.	143	195	212	183
	सूचीबद्ध	100	137	148	128

98. यह देखा जाता है कि :

- संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत से कम रही है।
- यहां तक कि यद्यपि लागत क्षति की अवधि में बढ़ी है, तथापि घरेलू उद्योग लागतों में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में समर्थ नहीं रहा है।
- जबकि लागतें 2017-18 में कम हुई हैं, आयात कीमत एवं बिक्री कीमत दोनों इस अवधि में काफी बढ़ी हैं।

- घ. जबकि पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बिक्री कीमत एवं लागतें दोनों में गिरावट आई, बिक्री कीमत में गिरावट लागतों में गिरावट से कहीं अधिक थीं।

इस प्रकार, यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं।

#### ज.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

99. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।
100. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

#### i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

101. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है :

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	128	129	97
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	128	129	97
घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	117	107	92
औसत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	74	95	91

102. यह देखा जाता है कि :

- क. घरेलू उद्योग का उत्पादन एवं क्षमता उपयोग 2018-19 तक बढ़ा है और फिर उसमें जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है।
- ख. जबकि जांच की अवधि में मांग सकारात्मक थी, जांच की अवधि में उत्पादन और क्षमता उपयोग आधार वर्ष से निम्न स्तर पर थे।
- ग. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में उत्पादन की प्रवृत्ति की तरह ही दर्शाई है। घरेलू बिक्री 2017-18 में बढ़ी और फिर जांच की अवधि में उसमें काफी गिरावट आई। जांच की अवधि में बिक्री आधार वर्ष से नीचे के स्तर पर थी।
- घ. समग्र रूप से, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ड. घरेलू उद्योग में मालसूची में 2017-18 में गिरावट आई, परंतु उसके बाद उसमें वृद्धि हुई। तथापि, मालसूची में क्षति की अवधि में गिरावट आई है।

## ii. मांग में बाजार हिस्सा

103. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि*
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	97	90	87
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	93	90	78
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
चीन	%	100	97	108	117
कोरिया	%	***	***	***	***
संयुक्त राज्य अमेरिका	%	100	146	163	176
शुल्क लगने वाले देश – यूरोपीय संघ	%	***	***	***	***
अन्य देश	%	100	67	42	74

104. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की पूरी अवधि में निरंतर गिरावट आई है। संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में बढ़ा है, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

## iii. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

105. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय नीचे तालिका में दिए गये हैं:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि*
लाभ/हानि	₹/ कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	260	108	-120
लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	304	115	-111
पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	341	128	-120
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	356	139	-114
नियोजित पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	318	125	-144

106. यह देखा जाता है कि :

- क. घरेलू उद्योग को 2016-17 में वित्तीय हानियां हो रही थीं। लागतों में गिरावट और कीमतों में वृद्धि से घरेलू उद्योग ने 2017-18 में लाभ कमाया जिसमें 2018-19 में और फिर जांच की अवधि में गिरावट आई। जांच की अवधि में लाभप्रदता में गिरावट काफी अधिक थी और घरेलू उद्योग को एक बार फिर जांच की अवधि में वित्तीय हानियां हुई।
- ख. नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय में लाभ की तरह वही प्रवृत्ति रही। नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में पहले 2017-18 में सुधार हुआ और उसके बाद जांच की अवधि काफी गिरावट आई। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में नकद हानियां, नकारात्मक पीबीआईटी और निवेश पर आय की क्षति हुई।

**iv. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता**

107. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि*
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	95	95	95
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	128	129	97
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	89	79	71

108. यह देखा जाता है कि:

- क. रोजगार स्तर पिछले तीन वर्षों में स्थिर रहे हैं।
- ख. प्रति दिन उत्पादकता 2018-19 तक निरंतर बढ़ी, परंतु जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई।
- ग. प्रदत्त मजदूरी में पूरी क्षति अवधि में गिरावट आई है।

109. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये मानदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

**v. वृद्धि**

110. उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि 2017-18 में सकारात्मक थी और उसके बाद जांच की अवधि में काफी गिरावट के साथ नकारात्मक हो गई :

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन	वर्ष/वर्ष	28	1	(25)
घरेलू बिक्री	वर्ष/वर्ष	17	(9)	(14)
बिक्रियों की लागत	वर्ष/वर्ष	(7)	16	(3)
बिक्री कीमत	वर्ष/वर्ष	31	0	(21)
लाभ/हानि	वर्ष/वर्ष	(360)	(59)	(211)
नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	(456)	(61)	(182)
आरओसीई	वर्ष/वर्ष	(418)	(61)	(215)

**vi. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता**

111. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग में लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है जिसने उसकी पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को कमजोर किया है।

**vii. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

112. यह देखा जाता है कि आयात कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे ही प्रभावित कर रही हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की लागत एवं बिक्री कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग देश में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण बाजार में अपनी कीमतें बनाए रखने में असमर्थ है। आयातों की कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों का काफी मात्रा तक न्यूनीकरण हुआ है। तीसरे देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क है अथवा वे न्यूनतम स्तरों पर हैं अथवा अधिक कीमतों पर हैं। पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। अतः अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात हैं।
113. प्राधिकरण नोट करता है कि डंपिंग मार्जिन डी-मिनिममस से अधिक है और महत्वपूर्ण भी है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों पर ध्यान दिया है। प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
114. जहां तक मांग-आपूर्ति अंतराल के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि संभावित मांग-आपूर्ति अंतराल घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले पाटित आयातों के विरुद्ध समाधान की मांग करने से वंचित नहीं कर सकता। यदि निर्यातक भारतीय बाजार में आवश्यकता पूरी करना चाहते हैं तो वह अपाटित कीमत पर आवश्यकताएं पूरा करके किया जा सकता है। यह भी अनंतिम रूप से नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता घरेलू बाजार की तुलना में निर्यात बाजार में अत्यधिक प्रतिकूल है। यह सिद्ध नहीं है कि घरेलू उद्योग ने घरेलू बिक्री में निर्यात को प्राथमिकता दी। इसके अतिरिक्त, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग वर्तमान जांच की अवधि में काफी कम हुआ है।
115. जहां तक घरेलू उद्योग के क्षति पहुँचाने वाले निर्यातों के तर्क का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन का उसके घरेलू प्रचालनों के संबंध में ही विश्लेषण किया गया है। निर्यातों में हुई हानियां अलग की गई हैं और उन पर वर्तमान जांच परिणाम में विचार नहीं किया गया है।
116. जहां तक कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर कच्ची सामग्री की वास्तविक कीमतों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कच्ची सामग्री की कीमतों में इन गिरावटों के बावजूद काफी गिरावट आई।
117. इस तर्क के संबंध में कि लाभप्रदता में गिरावट ब्याज तथा मूल्यहास लागतों में वृद्धि के कारण नहीं है। यह भी देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में ब्याज पूर्व लाभ (आरओआई) तथा मूल्यहास पूर्व लाभ (नकद लाभ) के संबंध में गिरावट आई।
118. मांग में गिरावट के संबंध में यह देखा जाता है कि जबकि उत्पाद के लिए मांग में गिरावट आई, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई।
119. जहां तक पूर्व पाटनरोधी शुल्क और उसके कारण क्षति के अभाव का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति पर विचार किया है।
120. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना प्रयोक्ताओं के हितों के प्रति पूर्वाग्रहयुक्त नहीं होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है।
121. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सतत् शुल्क के मामले के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान में उत्पाद पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं है। वस्तुतः प्राधिकारी ने इस आधार पर पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की पूर्व में सिफारिश की थी कि घरेलू उद्योग को क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग से संबंधित

सूचना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को एक बार फिर संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों द्वारा हुए काफी कीमत न्यूनीकरण के कारण क्षति हो रही है।

**viii. कम कीमत पर बिक्री/ क्षति मार्जिन की मात्रा**

122. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों तथा पेशेवर लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए कच्ची सामग्री का सर्वोत्तम उपयोग और यूटिलिटीयों पर क्षति की अवधि में विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा अनावर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से अलग किया गया है। अंत से ठीक पहले के उत्पाद जो विचाराधीन उत्पाद अर्थात् 4एडीपीए में पूरी तरह से खपाया जाता है, को नियमावली के अनुबंध-III के तहत अनुकूल बनाया गया है। विचाराधीन उत्पाद और 4एडीपीए के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ की अनुमति दी गई थी और उसे अपनाया जा रहा है।
123. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुँच कीमत पाटन मार्जिन निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्धारित सीआईएफ निर्यात कीमत से निर्धारित की गई है। लागू सीमा शुल्क आयातों की पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए शामिल किए गए हैं। संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की है।
124. जैसा कि इस पाटन मार्जिन विश्लेषण में उल्लेख किया गया है, लैक्सेस कारपोरेशन, यूएसए (उत्पादक/ निर्यातक) द्वारा दायर उत्तर से यह नोट किया जाता है कि उनके भारत में संबद्ध प्रयोक्ता/ आयातक लैक्सेस इंडिया को टुकड़े रूप में संबद्ध सामानों की बिक्री के दौरान हानि हुई है। चूंकि टुकड़े रूप में संबद्ध सामानों की उनकी बिक्री कीमत लागत कीमत से कम है जिसमें द्रव पीएक्स-13 की आयात कीमतें और द्रव से टुकड़े में परिवर्तन लागत शामिल है, अतः उनकी पहुँच कीमत से उपयुक्त समायोजन किया गया है।
125. उपर्युक्त निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

देश	उत्पादक	क्षति रहित कीमत (अमे. डॉ./ मी. टन)	पहुँच मूल्य (अमे. डॉ./ मी. टन)	क्षति मार्जिन अमे. डॉ./ मी. टन	क्षति मार्जिन भारित	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज
चीन जन. गण.	सेनिक्स कं. लि., शानडोंग	***	***	***	***	***	20-30
	सेनिक्स कं. लि., ताइवान	***	***	***	***	***	20-30
	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	***	40-50
कोरिया गणराज्य	कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि.	***	***	***	***	***	20-30
	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	***	20-30
संयुक्त राज्य अमेरिका	लैक्सेस कारपोरेशन	***	***	***	***	***	(10-20)
	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	***	(10-20)



**ज.3.5 क्षति संबंधी निष्कर्ष**

126. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से तथा तुलनात्मक दृष्टि से बढ़ी है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं। घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में जांच की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में काफी ह्रास हुआ है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई है। इनके मद्देनजर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

**झ. गैर-आरोपण विश्लेषण**

127. प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक की जांच की जो साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाते आ रहे हों ताकि इन अन्य कारकों, यदि कोई हैं, से क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में, जो संगत कारक हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा तथा कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

**क) पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा तथा मूल्य**

128. अन्य देशों से आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क लग रहा है अथवा न्यूनतम स्तरों पर है। इस प्रकार, अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले प्रतीत नहीं होते।

**ख) मांग में संकुचन**

129. यद्यपि समग्र मांग में वृद्धि हुई है, तथापि जांच की अवधि में मांग में गिरावट आई है। तथापि, जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं है।

**ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

130. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत के पैटर्न में परिवर्तनों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

**घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां**

131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में यह नहीं आया है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हैं।

**ड.) प्रौद्योगिकी में विकास**

132. प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तनों की मौजूदगी, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

**च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

133. प्राधिकारी ने केवल क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों हेतु आंकड़ों पर विचार किया है। अतः निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह घरेलू बाजार से उत्पाद के लिए मांग के अभाव के कारण भी निर्यात के लिए मजबूर है।

**छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन**

134. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन के क्षतिकारक आंकड़े दिए हैं और उन्हें प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए अपनाया गया है। अतः आवेदक द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

**ज. कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष**

135. प्राधिकारी अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण जांच की अवधि में क्षति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कारक दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध पाटित आयातों के कारण है:
- आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की लागत से कम कीमत की हैं।
  - आयातों के कारण घरेलू उद्योग उत्पादन लागत से कम कीमत पर उत्पाद को बेचने के लिए मजबूर हुए हैं। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण कीमत ह्रास हुआ है।
  - संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण प्रतिकूल मात्रात्मक एवं कीमत प्रभाव के परिणामस्वरूप जांच की अवधि में वित्तीय हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई है।
  - कीमत कटौती से आयातों में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है।
  - घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से, उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
136. इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध सामानों के पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

**ट. प्रकटन पश्चात विवरण अनुरोध****घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध**

137. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं :

- लेनसेस ने कमियों को ठीक करने के उद्देश्य से प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का कोई अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत नहीं किया और उसके कारण इस नियमावली के अंतर्गत गोपनीयता के प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। फाइबर बोर्ड के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच का संदर्भ लिया गया था, जहां प्राधिकारी ने निर्यातक के उत्तरों को अस्वीकार किया क्योंकि पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध नहीं कराया गया था।
- प्राधिकारी द्वारा परिकलित एन आई पी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार नहीं है। प्रकटन विवरण याचिका में सूचित की गई एन आई पी और प्राधिकारी द्वारा गणना की गई एन आई पी में बहुत अधिक अंतरों के कारण का उल्लेख नहीं करता है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे किये गये संशोधनों के साथ संबद्ध फाइल को साझा करें जिसके बिना याचिकाकर्ता एन आई पी पर टिप्पणियां देने में सक्षम नहीं है।
- अनुबंध III को कैप्टिव इनपुट्स पर लागू किया गया है जो अनुबंध III, डी जी टी आर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये अनेक शपथ पत्रों, विगत कार्यपद्धतियों और सार्वजनिक ब्यानों और डी जी टी आर द्वारा किये गये पत्राचारों के अनुरूप नहीं है।
- आवेदक द्वारा सूचित किए गये निवल निर्धारित परिसंपत्तियों का डी जी टी आर द्वारा संशोधन के लिए कारण और उसके परिणामस्वरूप अवमूल्य को प्रकट नहीं किया गया है। यदि इस प्रकार की कटौती आईएनडी - एएस के आवेदन में देय हो तब घरेलू उद्योग ने पहले ही ऐसी राशि की उपयुक्तता की पुष्टि कर दी है।

- v. घरेलू उद्योग द्वारा सूचित की गई कार्यशील पूंजी की तुलना में कार्यशील पूंजी की बहुत अधिक कटौती के कारण प्रकट नहीं किये गये हैं जिसके बिना घरेलू उद्योग टिप्पणियां देने में सक्षम नहीं हैं।
- vi. शुल्कों को लगाये जाने से उद्योग के कार्यनिष्पादन में गिरावट रुक जायेगी, हुई क्षति का निवारण हो पायेगा और घरेलू उत्पादक अर्थक्षम तथा प्रतिस्पर्धी होने में सक्षम होंगे।
- vii. उचित कीमत पर आयातों से प्रतिस्पर्धा करते हुए उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग उपभोक्ता के हितों में है।
- viii. यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है तब उद्योग को आगे क्षति का सामना करना पड़ेगा और अंततः विदेशी उत्पादकों को बड़े हुए लिबरेज देते हुए समाप्त हो जायेगा और उपभोक्ता उनकी दया पर निर्भर हो जायेंगे।
- ix. उपभोक्ता को माल सूची के उच्चतर परिमाण को बनाये रखना होगा यदि वे आयात की गई सामग्री पर निर्भर करते हैं जबकि घरेलू उद्योग से खरीद के मामले में, माल सूची होल्डिंग अपेक्षाकृत बहुत कम स्तरों पर रखा जा सकता है।
- x. घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण अपनी क्षमताओं का कम उपयोग करता रहा है।
- xi. पाटनरोधी शुल्क एक समान अवसर उपलब्ध करायेगा, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में गिरावट का समाधान करेगा और साथ ही अंतिम उपभोक्ताओं पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। पाटनरोधी शुल्क कीमत सुधार का केवल एक माध्यम है और न कि घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने का माध्यम है।
- xii. रेडियल टायरों की कीमत 20,000/- भारतीय रुपए से 25,000/- भारतीय रुपए के बीच में है और पीएक्स - 13 की लागत 90 रुपए प्रति टायर है। पीएक्स - 13 की कीमत में पाटनरोधी शुल्कों के लगाये जाने के कारण 20 प्रतिशत वृद्धि के फलस्वरूप भी प्रति टायर 18 रुपए तक लागत में वृद्धि होगी, जो रेडियल टायर की कीमत का 0.09 प्रतिशत है। उपभोक्ता उद्योग पर शुल्क का प्रभाव बहुत कम है।
- xiii. घरेलू उद्योग के पास भविष्य की आवश्यकताओं के लिए घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए पीएक्स - 13 की पर्याप्त क्षमता है।
- xiv. चूंकि ईस्टमेन केमिकल ने अपने रबड़ केमिकल व्यापार को वन रॉक केपिटल को बेच दिया है, ग्राहक 4 एडीपीए की आपूर्ति के लिए चीन और नोसिल पर निर्भर होने के लिए बाध्य होंगे और शुल्कों को नहीं लगाने के फलस्वरूप प्रचालन स्थगित होगा अथवा उसमें कटौती होगी और उपभोक्ता चीन के आपूर्तिकर्ताओं की दया पर रह जायेंगे।
- xv. पीएक्स - 13 अर्थात् 4 एडीपीए के उत्पादन में उपयोग किया गया कच्चा माल इसकी कुल लागत का 85 प्रतिशत होता है। 4 एडीपीए का प्रमुख आपूर्तिकर्ता चीन और भारत है। आवेदक भारत में 4 एडीपीए का एकमात्र निर्माता है। पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के कारण आपूर्ति चेन व्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न होगा।
- xvi. घरेलू उद्योग ने देश में मांग - आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए विचाराधीन उत्पाद की क्षमताओं में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग द्वारा निवेशों में वृद्धि के फलस्वरूप और अधिक रोजगार सृजित होगा जिसके द्वारा समग्र रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा।
- xvii. और अधिक बढ़ रहे व्यापार घाटे तथा अस्थिर विदेशी मुद्रा भंडार के कारण, यह महत्वपूर्ण है कि घरेलू उत्पादन की क्षमताओं पर अधिक विश्वास किया जाये और आयात पर निर्भरता कम हो सके।
- xviii. चूंकि चीन का सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर आधारित है अतः उसे प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा गणना प्राधिकारी की गणना की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक पाटन मार्जिन को दर्शाती है।

- xix. प्राधिकारी को प्रश्नावली के उत्तरों और सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद भाग लेने वाले निर्यातकों को भेजे गये पत्रों और उत्तरों का अगोपनीय रूपांतर दिखाना चाहिए।

### **अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध**

138. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं :

- i. प्राधिकारी ने अपनी जांच में बाद के पैरा 28 में इस तथ्य का विश्लेषण नहीं किया है कि किस प्रकार से यह घरेलू उद्योग द्वारा कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश कर सकता है जिसे प्रारंभिक जांच परिणामों के जारी किये जाने के समय पहले ही प्रस्तुत नहीं किया गया था जब उसे पहले ही केंद्र सरकार द्वारा अस्वीकार किया गया है। इस प्रकार, उपर्युक्त को देखते हुए प्रतिवादी आदरपूर्वक यह अनुरोध करते हैं कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं करनी चाहिए।
- ii. संबद्ध देशों से आयातों और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के विश्लेषण का अभाव है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डीए के पैरा 127 – 135 में अपने गैर आरोपण विश्लेषण में एटीएमए द्वारा किये गये किसी अनुरोध का उल्लेख नहीं किया है जो स्पष्ट रूप से कारणात्मक संबंध में विच्छेद को दर्शाता है।
- iii. मांग आपूर्ति में अंतर है और घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में प्रचलित मांग को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है।
- iv. पाटन मार्जिन की गणना करते समय मैसर्स के के पी सी के संबंध में, निर्यात कीमत पर विचार भारी मात्रा में बेचे गए विचाराधीन उत्पाद के लिये किया गया है जबकि सामान्य मूल्य थोक और पैक किये हुए रूप दोनों के लिए लिया गया है। प्राधिकारी को भारी और पैक किये गये हुए वस्तुओं के सामान्य मूल्य के साथ भारी मात्रा में वस्तुओं की निर्यात कीमत से तुलना करनी चाहिए।
- v. घरेलू उद्योग यह दावा करता है कि इसे दिसंबर 2018 के बाद मुश्किल से 3 महीनों तक 'वास्तविक क्षति' उठानी पड़ रही है। ऊपर में उल्लेख किये गये निर्णायक समीक्षा में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी का निर्णय किसी तार्किक व्याख्या का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है। इस कारण से माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के कथन का दिसंबर 2018 में इसका अपना निर्धारण अब असंगत नहीं है, का कोई औचित्य अथवा आवश्यक संदर्भ के बिना है। इस प्रकार माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे इस संबंध में अपने निष्कर्ष पर दुबारा विचार करें।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

139. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और वह नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियों को दोहराया गया है जिनकी पहले ही जांच उपयुक्त रूप से की गई है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में समुचित रूप से समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/ अनुरोधों में पहली बार उठाये गये और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये मुद्दों की जांच नीचे की गई है।
- क. जहां तक अत्यधिक गोपनीयता, गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में चीन का बर्ताव, लगाई गई औसत पूंजी पर 22 प्रतिशत की दर से प्रति लाभ के संबंध में तर्क का प्रश्न है, उसका समाधान इन जांच परिणामों के संगत पैराओं में किया गया है।
  - ख. जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि घरेलू उद्योग इस देश में उत्पाद के लिये मांग को पूरा नहीं कर सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में मांग - आपूर्ति में अंतर, देश में उत्पाद के पाटन, विशेषकर जब उसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, को न्यायोचित नहीं ठहराता है।
  - ग. जहां तक सामान्य मूल्य के संबंध में मैसर्स के के पी सी की चिंता का प्रश्न है प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जांच की है और उपयुक्त रूप से सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में संशोधन किया है तथा इसकी व्याख्या इस जांच परिणाम में संगत शीर्षों में किया है।

- घ. जहां तक घरेलू उद्योग के रूप में लेंसेस इंडिया की पात्रता का प्रश्न है, लेंसेस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह देखा जाता है कि कंपनी ने यू एस ए से विचाराधीन उत्पाद का भारी मात्रा में आयात किया है। यह भी नोट किया जाता है कि यह कंपनी निर्यातक से संबंधित नहीं है और यह अपने आप में एक आयातक है और ऐसे आयातों की मात्रा बहुत अधिक है (यू एस से संपूर्ण आयात इस कंपनी द्वारा किया गया है)। प्राधिकारी ने लेंसेस को एक घरेलू उत्पादक के रूप में माना है लेकिन नियम 2 (ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग नहीं है। जहां तक लेंसेस, इंडिया की पात्रता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लेंसेस इंडिया की अपात्रता पीएक्स - 13 के आयातों और यू एस ए के निर्यातक के साथ इसके संबंध के कारण है।
- ङ. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा एन आई पी के अपर्याप्त प्रकटन के संबंध में दिये गये विभिन्न तर्कों का प्रश्न है, अनुबंध III पर तर्क कैप्टिव इनपुट्स, और निवल निर्धारित परिसंपत्ति के संशोधन पर तर्क, अवमूल्य और कार्यशील पूंजी के संबंध में तर्क पर लागू किया गया है जबकि एन आई पी का परिकलन करते समय प्राधिकारी ने दोहराया कि क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, कच्चे माल और यूटिलिटी के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार क्षति की अवधि के दौरान किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा गैर आवर्ती खर्च को उत्पादन की लागत से बाहर रखा गया है। अंतिम उत्पाद जिसकी कैप्टिव रूप से खपत विचाराधीन उत्पाद अर्थात् 4 एडीपीए में की जाती है, का आदर्शतम उपयोग पाटनरोधी नियमाली के अनुबंध III के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद और 4 एडीपीए के लिए लगाई गई औसत पूंजी पर 22 प्रतिशत की दर से उचित प्रतिफल (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति योग औसत कार्यशील पूंजी) की अनुमति इस नियमावली के अनुबंध III में यथानिर्धारित क्षति रहित कीमत तय करने के लिए ब्याज, कर और लाभ के प्रति दी गई थी। दावा किये गये तथा अनुमति दिये गये एन आई पी के मूल्य के बीच बहुत अधिक अंतर रिकार्ड पर आंकड़ों के उचित सत्यापन के बाद प्राधिकारी द्वारा विचार किये गये अनुसार उपर्युक्त संगत कारकों के कारण है।
- च. जहां तक निर्दिष्ट प्राधिकारी के 2018 में दिये गये जांच परिणामों के संबंध में तर्क का प्रश्न है यह अनुरोध किया जाता है कि उस मामले में जांच की अवधि जुलाई 2017 – जून 2018 थी, जबकि वर्तमान मामले में जांच की अवधि 2019-20 है। प्राधिकारी ने इन जांच परिणामों के संगत पैराओं में यह निर्धारण किया है कि निर्यातक जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का पाटन कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

#### ठ. भारतीय उद्योगों का हित एवं अन्य मुद्दे

140. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से भारत में इस उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से कमी नहीं आयेगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से पाटन की कार्यपद्धतियों के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जायेंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट रुक जायेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्य तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार कार्यपद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। इस कारण से पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से किसी भी तरीके से संबद्ध देशों से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
141. प्राधिकारी ने इस पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की कि क्या जांच के अधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना व्यापक जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, इस उत्पाद के आयातकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों और रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने पर आधारित है।

142. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांचों, जिसमें उनके क्रियाकलापों पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव शामिल है, के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ताओं के वास्ते प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किये गये उत्पाद के परस्पर परिवर्तन की क्षमता, घरेलू उद्योग के स्रोतों की ओर जाने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, वे कारक जो संभवतः तेज गति से प्रभावित करेंगे अथवा पाटनरोधी शुल्क लगाकर उत्पन्न नई स्थिति के समायोजन में विलंब करेंगे, के संबंध में सूचना मांगी।
143. चार प्रयोक्ताओं, नामतः मैसर्स अपोलो टायर लिमि., मैसर्स सिएट लिमिटेड, मैसर्स जे के टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स एम आर एफ लिमिटेड और एक संबंधित आयातक नामतः लेंसेस इंडिया प्रा. लिमि. ने निर्धारित प्रयोक्ता/ आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। हालांकि, जैसा कि इन जांच परिणामों में पहले नोट किया गया है, इन प्रयोक्ताओं में से किसी ने भी उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को दर्शाने के उद्देश्य से कोई सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इसके अलावा, इस संबंध में प्राधिकारी इस तथ्य को दोहराते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से किसी भी रूप में संबद्ध देशों से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
144. भले ही प्राधिकरण ने उपयोगकर्ताओं के लिए एडीडी के प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रारूप निर्धारित किए हैं और विस्तार से बताया है कि एडीडी लगाने से उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह नोट किया जाता है कि किसी भी उपयोगकर्ता ने प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की है। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि इच्छुक पार्टियों ने सत्यापन योग्य जानकारी के साथ उपयोगकर्ता उद्योग पर एडीडी के प्रभाव को स्थापित नहीं किया है। इसके अलावा घरेलू उद्योग ने उपभोक्ता उद्योग पर अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है और प्रस्तुत किया है।

#### ड. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

145. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों और उनमें उठाये गये मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:
- क. आवेदक इस नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और वह यह मानते हैं कि इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को आवेदन ने पूरा किया।
  - ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद संबद्ध देशों से आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।
  - ग. सरल और ठोस रूप को दो अलग अलग वस्तुओं के रूप में नहीं माना जा सकता है और सरल रूप को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है।
  - घ. इस आवेदन में जांच की शुरुआत के उद्देश्य से संगत सभी सूचना निहित थे और इस आवेदन में वर्तमान जांच की शुरुआत करने का निर्णय लेने संबंधी जांच की शुरुआत करने को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य था।
  - ङ. कुम्हो द्वारा सूचित की गई 4 एडीपीए की खपत कीमत को अस्वीकार करने के मुद्दे का निपटारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया गया है और आगे माननीय सेस्टेट और और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे सही ठहराया गया है।
  - च. उक्त गैर बाजार अर्थव्यवस्था कंपनी से के के पी सी द्वारा 4 एडीपीए की वास्तविक खरीद कीमत का उपयोग पीएक्स 13 (6 पी पी डी) के उत्पादन से जुड़ी लागतों को तर्कसंगत तरीके से नहीं दर्शायेगा और इस कारण से कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स द्वारा सूचित की गई 4 एडीपीए की खपत कीमत को उत्पादन की लागत के निर्धारण के उद्देश्य से नहीं अपनाया जा सकता है।
  - छ. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और ये मार्जिन पर्याप्त हैं।

- ज. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष दोनों दृष्टियों से वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तुओं की मात्रा में 23% से अधिक की वृद्धि हुई है जबकि मांग में केवल 6% की वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कीमत में कटौती का मार्जिन कम हो रहा है।
- झ. घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुआ है।
- ञ. किसी भी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश यू एस ए से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के विरुद्ध नहीं की जाती है क्योंकि क्षति मार्जिन नकारात्मक है।
- ट. प्रयोक्ताओं के लिए पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताने तथा इस तथ्य को विस्तार से बताने के लिए कि किस प्रकार से पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से उन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा, सभी प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के बावजूद, किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को सिद्ध नहीं किया है। पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाये जाने से संबंधित उत्पाद के स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा और यह तथ्य कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर बहुत कम है। प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित में होगा।
146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग तथा, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबद्ध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए समुचित अवसर दिये गये थे। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबद्ध की जांच शुरू करने और उसे पूरा करने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना और क्षति के प्रभाव को इस जांच के पूरा होने तक कम करने के लिए अपेक्षित है। प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
147. प्राधिकारी द्वारा अपनाये गये कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये जाने वाली अधिसूचना की तिथि से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं। इस उद्देश्य से आयातों के पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य और सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाये गये शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों का लागू स्तर होगा। यू एस ए से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के विरुद्ध कोई पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि क्षति मार्जिन नकारात्मक है।

#### शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	उद्गम देश	निर्यात करने वाला देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3812, 2921, 2934 (टिप्पण 1)	रबड़ केमिकल पीएक्स 13 (टिप्पण 2)	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	सेनिक्स कं., लिमि. शानडॉंग	591.36	मी. ट.	यू एस डॉलर
2	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	सेनिक्स कं., लिमि. ताइवान	591.36	मी. ट.	यू एस डॉलर

3	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 1 और 2 पर उल्लिखित उत्पादक को छोड़कर कोई भी उत्पाद	924.47	मी. ट.	यू एस डॉलर
4	- वही -	- वही -	उन देशों के अलावा कोई देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है	चीन जन. गण.	कोई भी	924.47	मी. ट.	यू एस डॉलर
5	- वही -	- वही -	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लिमि.	489.56	मी. ट.	यू एस डॉलर
6	- वही -	- वही -	कोरिया गणराज्य	कोरिया सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित को छोड़कर कोई भी उत्पाद	612.18	मी. ट.	यू एस डॉलर
7	- वही -	- वही -	उन देशों के अलावा कोई देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है	कोरिया गणराज्य	कोई भी	612.18	मी. ट.	यू एस डॉलर

टिप्पण-1 – ऊपर में उल्लिखित सीमा शुल्क वर्गीकरण संसूचक मात्र है।

टिप्पण-2 - विचाराधीन उत्पाद का विवरण “रबड केमिकल्स पीएक्स - 13” भी है जिसे 6 पीपीडी, एंटीटोक्सिडेंट 6 पीपीडी, कुमानोक्स 13, सेंटोफेलेक्स 6 पीपीडी, सिरानटॉक्स 6 पीपीडी, बलकेनॉक्स – 4020, एंटीऑक्सीडेंट 4020, दुसानटॉक्स 6 पीपीडी, एनटेग 6सी, एन-1, 3-डाइमेथाबुटाइल) – एन – फिनाइल – पी – फिनाइलनेडिमाइन के रूप में भी जाना जाता है।

#### ढ. आगे की प्रक्रिया

148. केंद्र सरकार के इस आदेश के विरुद्ध अपील जो इस सिफारिश के परिणामस्वरूप की जा सकती है, इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जायेगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी



**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 26th July 2021

**(Case No: OI 17/2020)**

**Subject : Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Rubber Chemical PX-13” from China PR, Korea RP and USA.**

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

**F. No. 6/20/2020-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof.

1. M/s NOCIL Limited (hereinafter referred as “Applicant”) has filed an application, through TPM Consultants, before the Designated Authority in accordance with the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation concerning the imports of Rubber Chemical PX-13 (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) from China PR, Korea RP and United States of America (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. The Authority, on the basis of a prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 06/20/2020-DGTR dated 27<sup>th</sup> May, 2020, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.
3. The Authority having regard to the Act and the Rules, considered it appropriate to recommend interim duties and issued preliminary findings vide Notification No. 6/20/2020-DGTR dated 11<sup>th</sup> November, 2020, recommending the imposition of provisional anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from subject countries. However, vide Office Memorandum No. 354/158/2020-TRU dated 6<sup>th</sup> January, 2021, the Central Government decided not to impose the provisional ADD.

**B. PROCEDURE**

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
  - a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
  - b. The Authority issued a public notice dated 27<sup>th</sup> May, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of subject goods from subject countries.
  - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 27<sup>th</sup> May, 2020, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers, importer/user Associations and other interested parties, as per the addresses made available by the Applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.

- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.
- e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/ exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- f. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties to file their response as well as submissions. Vide communication dated 30<sup>th</sup> June, 2020, the time was extended upto 24<sup>th</sup> July 2020. Vide communication dated 23<sup>rd</sup> July, 2020, the time was extended upto 7<sup>th</sup> August, 2020.
- g. The following Government provided written submissions:
  - i. Government of Korea
- h. The Authority sent questionnaires to the following known producers/ exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
  - i. M/s. China Sunsine Chemical Holdings Ltd.
  - ii. M/s. Sennics Co., Ltd. – Sinochem International (Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd.)
  - iii. M/s. Shandong Yanggu Huatai Chemical Co. Ltd.
  - iv. M/s. Changde Dingyuan Chemical Industrial Limited
  - v. M/s. Dongying Bo Chen Chemical Co. Ltd.
  - vi. M/s. Jinan Runguan Chemical Co. Ltd.
  - vii. M/s. Nanjing Chemical Plant (NCP)
  - viii. M/s. Zhejiang Yongjia Chemical Plant
  - ix. M/s. Henan Kailun Chemical Co., Ltd.
  - x. M/s. Rongcheng Chemical General Factory Co. Ltd.
  - xi. M/s. Dalian Richon Chem Co., Ltd.
  - xii. M/s. Zhenjiang No. 2 Chemical Factory
  - xiii. M/s. Hebei Haufeng Chemical Group
  - xiv. M/s. Shenzhen Huaren Industrial Co.
  - xv. M/s. Yixing Dongfang Fince Chemicals
  - xvi. M/s. Zhejina Yueging Ultrafine Powders & Chemicals Co. Ltd.
  - xvii. M/s. Lion Industries Ltd.
  - xviii. M/s. Linkwell Rubber Chemicals Co. Ltd.
  - xix. M/s. Kemai Chemical Co. Ltd.
  - xx. M/s. Hebi Huaxia Auxiliary Co., Ltd.
  - xxi. M/s. Qingdao Zhongjian Rubber Chemicals Co. Ltd.
  - xxii. M/s. Northeast Auxiliary Chemical Industry Co. Ltd.
  - xxiii. M/s. Puyang Willing Chemicals Co. Ltd.
  - xxiv. M/s. Zhejiang Huangyan Zhedong Rubber Auxiliary Co. Ltd.
  - xxv. M/s. Dongying Wantong Rubber Auxiliary Co. Ltd.
  - xxvi. The Organic Chemical Industry Limited, Company of Tongling Chemical Industry Group

- xxvii. M/s. Shangyu Lixing Chemical Co. Ltd.
- xxviii. M/s. Tianjin East Richon Rubber Additives Co. Ltd.
- xxix. M/s. Donglong Industry Limited, Company of Jiangsu
- xxx. M/s. Jincheng Sky Success Chemical Industry Co. Ltd.
- xxxi. M/s. Hebei Hanxing Chemical Co. Ltd.
- xxxii. M/s. Jingcheng Tiancheng Chemical Co.
- xxxiii. M/s. Hebi Uhoo Rubber Chemicals co. Ltd.
- xxxiv. M/s. Kumho Petrochemicals Co. Ltd.
- xxxv. M/s. Daewoo International Corporation
- xxxvi. M/s. Lanxess Corporation USA
- i. In response to the above notification, following exporters/ producers and their related exporters/traders have responded and submitted exporter's questionnaire responses and/or legal submissions:
  - i. M/s. Lanxess Corporation USA (Lanxess)
  - ii. M/s. Kumho Petrochemical Co. Ltd. Korea RP (Kumho)
  - iii. M/s. Sennics Co., Ltd. Shandong, China PR
  - iv. M/s. Sennics Co., Ltd. Tai'an, China PR
  - v. M/s. Sennics Singapore Pte. Ltd.
  - vi. M/s. Sennics Inc., USA
  - vii. M/s. Sennics Co., Ltd., China PR
  - viii. M/s. Posco International Cooperation, Korea (Posco)
- j. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
  - i. M/s. Lanxess India P Ltd
  - ii. M/s. PMC Rubbchem P Ltd.
  - iii. M/s. Appollo Tyres Limited
  - iv. M/s. ATC Tires Private Limited
  - v. M/s. Birla Tyre
  - vi. M/s. Balkrishna Industries Limited
  - vii. M/s. Bridgestone India Private Limited
  - viii. M/s. J.K. Fenner (India) Limited
  - ix. M/s. CEAT Ltd.
  - x. M/s. Ralson Limited
  - xi. M/s. MRF Ltd.
  - xii. M/s. JK Tyres & Industries Limited
  - xiii. M/s. TVS Srichakra
  - xiv. M/s. Goodyear India Ltd.
  - xv. M/s. Malhotra Rubbers Ltd.
  - xvi. M/s. Metro Tyres Limited
  - xvii. M/s. Speedways Rubber Company

- k. In response to the above notification, following importers or users have responded and submitted importer/user questionnaire responses and/or legal submissions:
  - i. M/s Lanxess India Pvt. Ltd.
  - ii. M/s Rishiroop Limited
  - iii. M/s Apollo Tyres Limited
  - iv. M/s CEAT Limited
  - v. M/s JK Tyre & Industries Limited
  - vi. M/s MRF Limited
- l. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 27<sup>th</sup> May, 2020 to the following known Associations of the subject goods in India.
  - i. Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA)
- m. In response to the above notification, following Associations have responded to the initiation notification and filed legal submissions:
  - i. Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA)
  - ii. All India Rubber Industries Association (AIRIA)
- n. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held through video conferencing on 4<sup>th</sup> March, 2021. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- o. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.
- p. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1<sup>st</sup> April 2019 to 31<sup>st</sup> March 2020 (12 months). The injury examination period has been considered as the period from 1<sup>st</sup> April 2016 - 31<sup>st</sup> March 2017, 1<sup>st</sup> April 2017 – 31<sup>st</sup> March 18, 1<sup>st</sup> April 2018 – 31<sup>st</sup> March 2019, and the period of investigation.
- q. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation, which has been received by the Authority. The Authority has relied upon DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- r. Further information was sought from the Applicant to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- s. The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and reasonable profits the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- t. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered in this Final Finding.
- u. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this Final Finding, to

the extent possible, and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.

- v. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- w. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 15<sup>th</sup> July, 2021, and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these Final Findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- x. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded this Final Finding on the basis of facts available.
- y. ‘\*\*\*’ in this Final Finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

z. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 71.65.

#### **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as-

*“The product under consideration is “Rubber Chemicals PX-13” (hereinafter also referred to as PX-13) also known as 6PPD, Antioxidant 6PPD, Kumanox 13, Santoflex 6PPD, Sirantox 6PPD, Vulkanox 4020, Antioxidant 4020, Dussantox 6PPD, Antage 6C, N-1,3-Dimethylbutyl)-N'-Phenyl-P-Phenylenediamine, etc.*

*PX-13 is an alkyl-aryl-PPD antidegradant most widely used in the tyre and non-tyre sector of the rubber industry. PX-13 offers excellent resistance to rubber vulcanizates against degradative forces such as ozone (static as well as dynamic), flex-cracking and fatigue, oxidative heat ageing, metal-ion catalyzed oxidative ageing, UV light and weathering. It is used as antioxidants in treating natural rubber, synthetic rubber (SBR, Butadiene Rubber, Nitrile Rubber, Carboxylated Rubber) and other synthetic rubber-based compounds used for manufacture of various rubber products to achieve the desired life cycle of the rubber product. PX-13 is manufactured by reductive alkylation of 4ADPA and MIBK.*

*The product is classified under the Chapter 38 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff custom classification 3812. However, there are also imports for the product under consideration under the Chapter 29 of the First Schedule. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.”*

#### **C.1. Submissions of the domestic industry**

6. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
- i. The product under consideration in the Application is “Rubber Chemical PX-13”. PX-13, also known as 6PPD, Antioxidant 6PPD, Kumanox 13, Santoflex 6PPD, Sirantox 6PPD, Vulkanox 4020, Antioxidant 4020, Dussantox 6PPD, Antage 6C, N-1,3-Dimethylbutyl)-N'-Phenyl-P-Phenylenediamine, etc.
  - ii. PX-13 is an alkyl-aryl-PPD anti degradant most widely used in the tyre and non-tyre sector of the rubber industry. PX-13 offers excellent resistance to rubber vulcanizates against degradative forces such as ozone (static as well as dynamic), flex-cracking and fatigue, oxidative heat ageing, metal-ion catalyzed oxidative ageing, UV light and weathering. PX-13 pastilles are easy to handle on all

types of weighing systems and quickly disperse in rubber compounds even at lower processing temperatures.

- iii. The product is classified under the Chapter 29 and 38 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975). The PUC is being imported under the 8-digit HS codes, 29215130, 29215190, 38121000, 38123030, 38123910, 38123990 and 38123100. The duties have always been recommended by the Authority at 4-digit levels in previous findings of Rubber Chemicals.
- iv. There is no difference in the subject goods produced by the domestic industry and exported from subject countries and are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods.
- v. The Applicant has produced like article to the imported products.

## **C.2. Submissions of other interested parties**

7. Following submission have been made by the exporters/other interested parties with regard to the product under consideration and like article.
  - i. The liquid/melt form is not like article and hence should be excluded from the scope of subject goods.
  - ii. The company has exported liquid form to India, whereas has sold both liquid and solid form in India.
  - iii. The liquid form exported to India was entirely sold to affiliated company who processed it further and sold solid form to eventual consumers in India.

## **C.3. Examination by the Authority**

8. The product under consideration is “Rubber Chemicals PX-13” also known as 6PPD, Antioxidant 6PPD, Kumanox 13, Santoflex 6PPD, Sirantox 6PPD, Vulkanox 4020, Antioxidant 4020, Dussantox 6PPD, Antage 6C, N-1,3-Dimethylbutyl)-N’-Phenyl-P-Phenylenediamine.
9. PX-13 is an alkyl-aryl-PPD anti degradant most widely used in the tyre and nontyre sector of the rubber industry. PX-13 offers excellent resistance to rubber vulcanizates against degradative forces such as ozone (static as well as dynamic), flexcracking and fatigue, oxidative heat ageing, metal-ion catalyzed oxidative ageing, UV light and weathering. It is used as antioxidants in treating natural rubber, synthetic rubber (SBR, Butadiene Rubber, Nitrile Rubber, Carboxylated Rubber) and other synthetic rubber-based compounds used for manufacture of various rubber products to achieve the desired life cycle of the rubber product. PX-13 is manufactured by reductive alkylation of 4ADPA and MIBK.
10. The product is classified under the Chapter 38 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff custom classification 3812. However, the product under consideration has also been imported under Chapter 29 of the First Schedule. The customs classification has been considered only indicative and not binding on the scope of the product under consideration. Imports of the product under consideration wherever reported have been considered for the purpose of present determination.
11. As regards exclusion of liquid/melt form, the Authority notes that the importer has imported liquid form from its affiliated company in USA, and the affiliated exporter/producer in USA has sold both liquid and solid form in domestic market. The importer in India is a producer of PX-13. The company has processed the imported liquid PX-13 into solid and has thereafter sold to the eventual consumers, along with PX-13 produced by the company. Thus, as far as consumer of the product under consideration are concerned, they have bought solid form of PX-13. Such being the case, the liquid and solid form cannot be treated as two different articles and liquid form cannot be excluded from the scope of the product under consideration.
12. It is seen from the information available on record that the product produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from subject countries is comparable in terms of physical &

chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably.

#### **D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

##### **D.1 Submissions of the domestic industry**

13. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
  - a. The Applicant NOCIL Limited account for a 'major proportion' of Indian production of subject goods in India. The applicant accounts for 70.13% of the total Indian production for the subject goods in India.
  - b. The Applicant has not imported the subject goods in the period of investigation from the subject countries.
  - c. The Applicant is not related to any exporters in the subject countries or importers of the subject goods in India.
  - d. Lanxess India cannot be considered as eligible domestic industry and its production cannot be considered to calculate applicant's share in Indian production as it is importing the subject goods from its affiliate i.e., Lanxess Corporation, USA and merely converts the form of the imported goods without engaging in manufacturing. Reference has been made to findings in SDH transmission equipment, CPVC resin wherein the Authority held that every domestic producer cannot be recognized as domestic industry.
  - e. Lanxess wanted to ensure that material continues to be available to the company at dumped prices.

##### **D.2. Submissions of other interested parties**

14. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
  - a. Lanxess cannot not be excluded from the scope of the domestic industry merely on a ground that it has imported the PUC from a subject country, without determining the status of the quantum of imports made by Lanxess
  - b. The fact that Lanxess is importing 4ADPA cannot change its status as a domestic manufacturer of the product under consideration.
  - c. NOCIL on its own will not be able to fulfil the requirement of 'major proportion' under the Indian AD rules. Request to re-assess NOCIL's standing as the domestic industry including Lanxess' production in the total Indian production and whether it constitutes major proportion in the total Indian production.
  - d. Lanxess is one of the major domestic producers and has imported subject goods in liquid form and converted to flakes to supplement its production. Imported goods have not been sold in liquid form in POI.
  - e. Lanxess India approached DGTR requiring anti-dumping duties on imports from China and Korea, which did not satisfy standing and was opposed by NOCIL.
  - f. The domestic industry has failed to consider the discretion available with the authority to include a domestic producer regardless of the imports made by them.
  - g. Domestic industry has not made any substantiated claims to show that Lanxess is importing a significantly large quantity of product under consideration, thereby making it ineligible to be considered domestic industry or that is thrust has moved from production to imports.
  - h. The Authority has considered domestic producer who has imported or is related to an exporter or imports as eligible domestic industry in investigations concerning imports of Pigments, Caprolactam. In anti-subsidy investigations concerning imports of Atrazine Technical and

continuous cast copper wire rods, domestic producers who had imported raw material constituting significant portion of total cost as domestic industry.

- i. Lanxess cannot be excluded for the purposes of injury analysis irrespective of whether it is an eligible domestic producer or not.
- j. The claim to not treat Lanxess India as domestic industry should be closely examined and if facts establish eligibility, major proportion test must be conducted.

### **D.3. Examination by the Authority**

15. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*

16. The Application has been filed by M/s NOCIL Limited. The Applicants has certified that they have neither imported the PUC from the subject countries in the POI nor they are related to any exporter or producer of PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India.
17. The product under consideration is produced in India by following companies:
- i. Lanxess India P Ltd
  - ii. PMC Rubbchem P Ltd
18. It is seen from the information provided by the Lanxess that the company has imported significant volumes of the product under consideration from USA. It is also noted that the company is related to exporter and is itself an importer, and the volume of such imports is quite significant (entirety of the imports from US are by this company). The Authority has considered Lanxess as a domestic producer, but not domestic industry within the meaning of Rule 2(b). As regards submissions made by interested parties concerning eligibility of Lanxess, India, the Authority notes that ineligibility of Lanxess India is not on account of import of 4-ADPA. The same is on account of imports of PX-13 and its relationship with the exporter from USA.
19. The Production of applicant accounts of \*\*\* % in gross Indian production (including Lanxess) and \*\*\* % after excluding production of Lanxess.
20. Considering the information on record, the Applicant accounts for a major proportion of the Indian production. Accordingly, the Authority holds that the Applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. Further, the Authority considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rule.

## **E. CONFIDENTIALITY**

### **E.1. Submissions by the domestic industry**

21. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:
- i. The exporters have claimed excessive confidentiality in their questionnaire responses regarding sales channels, corporate structure, list of products sold, etc.
  - ii. The exporters have claimed information that is freely available in the public domain as confidential.
  - iii. The users/importers have claimed excessive confidentiality of questionnaire responses and have not provided a reasonable summary of the information claimed confidential.
  - iv. The responses filed by users/importers are incomplete. Further, information in the public domain have been claimed confidential.
  - v. The petition filed by the domestic industry is as per Rule 7 of the Rules, Trade Notice No. 1/2013 and Trade Notice 10/2018.



- vi. As regards confidentiality of costing information, it is a business proprietary information not amenable to summarization. The exporters themselves have claimed costing information confidential and different standards should be applied for all parties. Reference was made to Anwar Jute Spinning Mills Ltd. v. Union of India/Designated Authority wherein it was stated that cost of production and related data of the domestic industry are confidential in nature. The domestic industry also relied on Nitro Chemical Industry Limited v. Designated Authority.
- vii. The petitioner has not claimed confidentiality of Annual Reports and is freely available on the website.

## **E.2. Submissions of the other interested parties**

22. The following submission have been made by other interested parties with regard to confidentiality:
- i. The domestic industry has failed to appropriately analyse the parameters under the Trade Notice 10/2018, it has also failed to provide the actual figures of some specified parameters in violation of the Trade Notice 10/2018. The domestic industry should be directed to refile the trend, performance parameters and data considering the actuals for March 2020, which is now available.
  - ii. The non-confidential version of the petition does not allow for a reasonable understanding and violates requirements in Rule 7 of the Rules and Trade Notice No. 1/2013 dated 9<sup>th</sup> December, 2013.
  - iii. Section VI (Costing Information) has not been furnished at all, and no justification has been provided. Significant data has not been properly indexed or provided in the NCV. Petitioners should be directed to provide these documents and a summary/indexed data of the same.
  - iv. The petitioner has claimed excessive confidentiality of Annual reports, which is already available in the public domain. Trade Notice 1/2013 states that the petitioner should mandatorily provide annual reports and balance sheets.
  - v. The users have provided sufficient information in the questionnaire response. Information claimed confidential are business sensitive and not amenable to summarization.
  - vi. Investigation should not be trivialized by raising issues regarding reasonable confidentiality.
  - vii. Equity acquisition in Shandong HuaHong Chemical Co., Ltd. does not mean there is structure change in Sennics Co, Ltd. as they are two different companies. Sinochem International itself is not involved with the PUC.

## **E.3. Examination by the Authority**

23. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non- confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
24. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provide as follows:

*“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

25. As regards the argument of excessive confidentiality claims, the Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that an information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
26. As regards the argument of information on period of investigation, it is noted that following the initiation of investigation, the updated copy of application for the POI was filed by the petitioner, and the same was duly has been circulated to all interested parties. It may be recalled that the Application filed by the domestic industry for initiation of investigation was based on information for the period April 2019 to February 2020 as the investigation period, since the accounts of March 2020 were yet to be finalized. The Authority has considered the information filed by the interested parties for period of investigation i.e. April 2019 to March, 2020 in this Final Finding.

## **F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

### **F.1. Submissions by the domestic industry**

27. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
- i. The user association, namely All India Rubber Industries Association (AIRIA) has registered itself but none of its members or the association itself has filed any comments to the petition or other information within time limits prescribed by the Authority.
  - ii. The information filed by Kumho Petrochemicals is false and misleading. The exporter has claimed same cost for domestic and exports. There is no consistency between cost-price and profits.
  - iii. Lanxess has filed a deficient response and the same should not be accepted. The exporter did not file a complete response despite being given 72 days after initiation and failed to rectify the deficiency even after it was noted by the Authority in the preliminary findings.
  - iv. As regards excessive duty protection, there is no excessive protection to the domestic industry and anti-dumping duty is to only prevent unfair trade measure. The Authority imposes duty only when all legal requirements are met. The exporters are habitually exporting at unfair prices and the domestic industry cannot be barred from approaching the Authority.
  - v. The Applicant filed the present application on 28th April, 2020. The application filed on 24th January 2020 was withdrawn by the Applicant and the same was accepted by the Authority.
  - vi. The arguments of the interested parties regarding the argument that the grounds for rejection that existed in 2017-18 also exists in the period of investigation is without basis. The present investigation is a fresh investigation and the domestic industry is required to only establish material injury. The Authority has held that the imports are causing material injury and posing a threat of material injury.
  - vii. Seeking relief from the courts is a legal right of the domestic industry. As regards Delhi High Court order, the same has no relevance in the present investigation.
  - viii. The requirements of Rule 5 have been adequately met by the domestic industry. The quantity and quality of evidence improves as an investigation progresses. Information sufficient for the purpose of initiation may not be sufficient for the purpose of determination, and information required for determination need not be insisted upon at the time of initiation. The respondents omitted to quote the finding of the WTO Panel in Mexico-Steel Pipes and Tubes while referring to the case wherein it was noted that it is not necessary to have irrefutable proof during initiation.
  - ix. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
  - x. The impact of the possible anti-dumping duty on the user industry is grossly insignificant.

- xi. The duties were terminated with Delhi High Court Order and therefore the petition is filed as per Article 2.19 of CEPA.

## **F.2. Submissions by other interested parties**

28. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

- i. NOCIL has been under duty protection with respect to PX-13 for more than 10 years. Duties have also been imposed on Accelerator chemicals and other ancillary products such as Oxo-Alcohols, acyclic alcohols and isopropyl alcohol.
- ii. There exists a discrepancy in the date of filing of the petition by the domestic industry.
- iii. In a previous safeguard investigation in 2011, NOCIL had argued that it is seeking duty protection so that it can increase its capacity to be able to cater to the domestic demand and also to decrease its costs. Reference has been provided to Final Findings in Safeguard investigation concerning imports of PX-13 or 6PPD (Rubber Chemicals) into India, dated 06<sup>th</sup> June 2011. Thereafter, in the review investigation of the safeguard duty that had been imposed in 2011, the DI had failed to follow through its adjustment plan to increase its capacity, pursuant to which the Director General of Safeguards terminated the safeguard duty on the PUC in 2014. Reference has been provided to Final Findings in Review of Safeguard duty imposed on PX-13 or 6PPD (Rubber Chemicals) into India dated 24<sup>th</sup> April 2014.
- iv. The factors and circumstances considered by DGTR while rejecting the SSR application filed by the domestic industry in 2018, wherein it was observed that there was no information on record to show that there was injury or likelihood of injury to the domestic industry also currently exists.
- v. The return during the POI in the present investigation falls within the range of the historical returns. Thus, it cannot be said the current imports of PUC from subject countries has resulted in declining returns. Moreover, there are other factors which have played a significant part in declining performance of the DI which are not related to the PUC imported from subject countries.
- vi. Petitioner used multiple forums to get anti-dumping duties imposed by going to the extent of almost forcing the Authority to initiate the second sunset review when the underlying anti-dumping notification had already been quashed by the High Court of Delhi dated 31.05.2018. Submissions by the petitioner should be examined with highest scrutiny to ensure that favourable recommendations are not obtained by deceit.
- vii. The present initiation is bad in law and should be terminated. Standard of review applied by Authority does not meet standards laid down under law. The allegations in the petition are largely based on estimates and assumptions, and petitioner failed to draw a logical conclusion. Reference was made to US-Softwood Lumber from Canada, Guatemala – Cement II and Mexico – Steel Pipes and Tubes.
- viii. The factors considered by Ministry of Finance while not imposing provisional ADD should also be taken note of. ADD will adversely affect the economies of MSME sectors, End users, Tyre industries etc. The unemployment rate at present is the highest in India and MSME sector is the main employment generator.
- ix. Initiation of a new investigation prior to one year is not proper, in reference to Article 2.19 of CEPA.
- x. The preliminary findings are non est in the eye of the law as Central Government did not accept the conclusion and findings made by the Authority, and the DI has not given any new arguments or evidence in their written submissions.
- xi. The totality of circumstances should be considered and the present investigation should be terminated.
- xii. The response filed by Lanxess is full and complete. Further, no deficiency memo was issued by the Authority regarding the minor deficiencies mentioned in the preliminary findings.

- xiii. Domestic industry has been unfairly protected due to the rejection of actual raw material price of Kumho in determining normal value, leading to inflated dumping margins has also been a huge burden on the user industry.
- xiv. A user association is an interested party and has the right to participate in the investigation. Rishiroop Limited is a member of the association and has responded.

### **F.3. Examination by the Authority**

- 29. As regards excessive protection to the domestic industry, the Authority notes that the recommendation for imposition of duty is made only when the requisite legal requirements are met. Further, there is no bar on the number of times a duty can be imposed or extended on a given product.
- 30. As regards the submission that the petition does not have prima facie evidence to justify initiation, the Authority notes that the Application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after satisfaction that application contained sufficient prima facie evidence to justify initiation of investigation decided to initiate the present investigation.
- 31. As regards the contention that the facts and circumstances that existed in 2018 still exists, the Authority notes that the present investigation only concerns the period of investigation and the factors existing during the current period has been sufficiently considered. The factors that existed in 2018 holds no relevance in the present investigation.
- 32. As regards the contention that the present initiation was prior to the completion of one year, the Authority notes that the duties against the subject countries were terminated by the Delhi High Court. Therefore, the initiation of the present investigation has been done only after meeting all legal requirements.
- 33. As regards the argument regarding the impact of ADD on the user industry, it is noted that the interested parties have not demonstrated how the anti-dumping duty will impact the consumers. Despite providing all formats for users to quantify the impact of ADD and elaborate on how imposition of ADD will adversely impact them, none of the users have provided relevant information. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information. Further, even if it is considered that the imposition of ADD might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods, it is noted that fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the ADD is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. The objective of imposition of anti-dumping measure is to remove the unfair advantages gained by dumping practices, to prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
- 34. As regards argument of deficient response of Lanxess, it is noted that the required information has been provided by the exporter after the preliminary findings, and the same has been taken into account in the Final Finding.
- 35. As regards status of All India Rubber Industries Association (AIRIA) as an interested party, it is noted that neither any of the members of the Association has filed the prescribed questionnaire nor the Association has provided any information during the course of investigation. However the Authority has considered their submissions for the purpose of the present investigation.

## **G. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**

### **G.1. Submissions of the domestic industry**

- 36. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to market economy, normal value, export price and dumping margin are as follows:
  - i. Efforts were made to get evidence of the price of subject goods in Korea and USA.  
However, normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in an appropriate third country for the reason that the relevant information is not publicly available and that the product does not have a dedicated customs classification.

- ii. The Applicant has claimed consideration of normal value for Korea and USA on the basis of constructed cost of production with the addition of reasonable profit margins as information regarding price or constructed value in an appropriate third country was not publicly available.
- iii. Since it is an established fact that Korea Kumho (the sole known manufacturer of PX-13 in Korea) is sourcing its requirement of the major raw material 4ADPA which constitutes 70-80% of the total cost, from Chinese companies, as already stated in the Preliminary Findings, the cost and price of Korea cannot be adopted for normal value determination.
- iv. Price of Korea Kumho should not be accepted as Kumho is faced with a particular market situation. It is highly unusual that Kumho never invested in production of 4ADPA despite being a major producer of PX-13 and having capacities of 80,000 MT. The company was also granted patent in June 2012. Korea Kumho procures 4ADPA from Sennics. Further, even though it is easy for Sennics to stop supplying to Kumho and grab the market, it has not done so. The import of the major raw material in the present conditions show that the sale price in the record is naturally distorted.
- v. Cost of production of Kumho is distorted as 4ADPA, which is the penultimate intermediate in the production of PX-13 is being procured at a distorted price.
- vi. Article 6.10 of ADA and Rule 17(3) of AD Rules cannot be read to imply individual normal value and the sole obligation of the Authority is to determine individual dumping margin.
- vii. Domestic sales made by the subject exporter does not pass the normal value tests and should be discarded for determination of normal value. The Authority is not obliged to consider transactions under consideration just because they represent domestic sales transactions.
- viii. Even if the elements of costs might be based on the records kept by the exporter, it does not imply that the Authority is bound to adopt the cost of production of the exporter without being satisfied as to whether they reasonable reflect the cost associated with production and sale of the product under consideration.
- ix. Provisions relating to determination of SGA and profits under Annexure I further establishes that the constructed normal value is not always solely based on the data of the producer concerned and so it cannot be said that normal value can be determined only on the basis of the data of the producer.
- x. Korean costs cannot be accepted particularly when the Chinese costs are being rejected on grounds of distortion, and the treatment cannot be any different for a Korean producer who has procured its penultimate intermediate from China.
- xi. Written agreement is not mandatory to undertake business and the actions of the parties are also clearly indicative of such an agreement. Further, Kumho has never denied the existence of an agreement even when the issue was raised in previous investigations. There were no exports by Kumho to Sennics or by Sennics to Korea despite holding significant capacities far exceeding demand and having significant export orientation, thereby clearly indicative of a tacit agreement between them to not compete.
- xii. The Authority has rejected 4ADPA cost of Kumho in the past for determination of normal value and it was upheld by CESTAT and the Supreme Court.
- xiii. Other countries such as EU has an established practice of rejecting raw material consumption price if the input constitutes 17% more than total cost of production and there is sufficient evidence of distortion.
- xiv. Kumho and Sennics should be deemed as related parties as Kumho exclusively purchases 4ADPA which constitutes majority of the cost, from Sennics.
- xv. The Designated Authority shall follow Para 1-6 of Annexure I for determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined and shall reject the claim of individual dumping margin.
- xvi. Since the Chinese producers are not entitled to market economy treatment, Para 7 of Annexure I may be followed to determine the normal value. Since the normal value could not be

- determined on the price or constructed value in a market economy third country as the relevant information is not publicly available, The Applicant has claimed the determination of normal value for China on the basis of price payable in India duly adjusted.
- xvii. The Authority should consider actual cost of production for determination of normal value. Normal value should not be based on any normation – whether for raw materials or for conversion costs while determining normal value
  - xviii. Since Lanxess USA is exporting the product under consideration to Lanxess India, it is a related party transaction and therefore the export price of these transactions cannot be considered for export price determination. Export price needs to be constructed from resale price of Lanxess India, duly adjusted.
  - xix. Export price of Lanxess USA is required to be adjusted as its related party in India has converted the liquid form into flakes, the selling price of Lanxess India is selling at losses as its selling price is lower than purchase costs including import prices and conversion costs, and the questionnaire response filed by Lanxess USA also shows it is exporting to India at losses for the last three years including period of investigation.
  - xx. The dumping margins of the subject countries are above de-minimus levels, significant and substantial.
  - xxi. The level of trade adjustments on export price claimed by Kumho for its domestic sales have been rightly rejected and the reasoning of the exporter lacks legal basis as well.
  - xxii. As regards Delhi High Court order, the same was not on merits. CESTAT order upholding rejection of 4ADPA prices is binding on the Authority.
  - xxiii. While interpreting Article 2.2.1.1 of the AD Agreement, the term “normally” should be read as referring to a situation wherein the costs of an exporter can be calculated on the basis of records kept by the exporter or producer. This implies that there can exist a situation wherein the records of the exporter or producer cannot be relied upon. The exporters’ interpretation of the WTO Panel’s decision in *EU-Biodiesel* is incorrect. Reference was also made to WTO Panel Reports in *Broiler* and *Egypt – Steel Rebar*.
  - xxiv. The WTO Panel in *EU-Biodiesel* states that the rule may be derogated from under certain conditions which was later affirmed in *Australia – A4 copy paper* wherein it was also observed that the Authority can disregard the costs of the exporters even for reasons distinct from the two conditions mentioned in the provision in a situation where the Authority may find a compelling reason to do so.
  - xxv. China PR has been considered as non-market economy by the Authority in all recent investigations.
  - xxvi. India has not acted inconsistently with the provisions of “*pacta sunt servanda*”. China is not being treated as a non-market economy merely based on domestic regulations, but also on the basis of Article 15(a)(i) of China’s Accession Protocol which continues to operate even after 11<sup>th</sup> December 2016. China has failed to fulfill its obligations under the Accession Protocol and failed to remove distortions, to allow prices to be set by the market, as a result of which even other WTO members, including USA and European Union, have continued to treat China as a non-market economy.

## G.2. Views of the interested parties

37. The following submissions have been made by the exporter/producer/other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin:
  - i. Dumping margin should be determined based on the questionnaire response filed by the producers/exporters and actual procurement price of raw material. Rejection of raw material consumption price is in violation of Article 2.2.1.1 of AD Agreement and with the reports of the Appellate Body in *EU – Biodiesel*, *Ukraine – Ammonium Nitrate* and Panel in *EU-Cost Adjustment Methodologies* and *Anti-dumping Measures on Imports from Russia – Second Complaint* which specify that there is no requirement to assess the reasonableness of the prices provided by the exporter / producer.

- ii. The fact that Chinese producers are non-market economy companies does not imply that the purchase price can be rejected. CESTAT decision upholding rejection of actual cost of 4ADPA in the previous investigation is not relevant, as it is contrary to the WTO jurisprudence.
- iii. Petitioner has relied on the earlier final findings concerning the subject goods wherein the actual price of raw material 4-ADPA had been rejected by the Authority. However, the final findings dated 29.04.2014 have already been quashed by the High Court of Delhi via its judgement dated 31.05.2018. Thus, there is no basis for the Authority to apply the same principle again in this case.
- iv. As regards the issue of special agreement between Kumho and Sinorchem, Authority has previously held in Sunset Review Anti-dumping investigation concerning imports of “White Cement” originating in or exported from Iran and UAE that competition issues are to be raised in Competition Commission and it is unnecessary for DGTR to examine such issues.
- v. The calculation of cost on the basis of records kept by the producer or exporter is in accordance with Article 2.2.1.1 of AD Agreement. Unless Korean exporters are not fulfilling the two conditions under Article 2.2.1.1 the Authority may consider the records maintained by these producers/exporters. The price of Kumho cannot be rejected just because they imported raw materials for China PR.
- vi. Kumho had procured most of 4-ADPA during the POI from an unrelated supplier in China PR who is also participating in the present investigation as a producer and exporter of the subject goods. It is commercially impractical that Kumho’s competitor based in China PR would sell key raw material 4-ADPA to Kumho at a price lower than the market price and there is no evidence of record to support the view.
- vii. Contrary to the Petitioner’s contention, Kumho has no explicit or implied agreements or commitments regarding the sale or production of raw material and subject goods to limit each other’s sales market or limit competition.
- viii. The petitioner has been protected by unfairly high duties on Kumho as the Authority has rejected actual raw material price of 4-ADPA reported by Kumho in determining normal value has led to inflated dumping margins and such treatment is unfair and in violation of Article 2 of the AD agreement.
- ix. The methodology adopted by Authority for rejection of cost based on CESTAT’s decision is inappropriate based on the Supreme Court’s decision in Customs, Bangalore v. G.M. Exports, wherein it was held that where a statute is enacted pursuant to an international treaty, an interpretation based on international treaty should be followed rather than earlier domestic precedents.
- x. The surrogate country methodology should not be used in calculating the normal value for this case, regardless of whether China is treated as a market economy country. India has no basis for calculating normal value using the non-market economy methodology.
- xi. India is bound by ‘pacta sunt servanta’ and must fulfill its obligations under relevant agreements and recognize China’s full market economy status, by amending relevant domestic regulations.
- xii. Domestic industry has not argued whether records kept by Kumho Korea are in accordance with GAAP of Korea RP and unless it is not so, the records maintained and submitted by it should be considered.
- xiii. Input prices cannot be disregarded when those prices are lower than other price internationally.
- xiv. The records of Korea Kumho should be considered where its records reflect the price paid to acquire the raw material 4-ADPA from Sennics, sufficiently correspond to the production and sale of the PUC in domestic market.
- xv. The costs of an investigated exporter reflect the price at which it has procured the raw material and subsequently the costs incurred in production and sale of PUC and it is immaterial whether it is procured from China PR, a non-market economy. There is no provision in law to adjust landed value and such a contention is untenable in law.

- xvi. Kumho and Sennics are not related parties and their relationships is only with regard to commercial activities. They do not fall under the definition of related party under Rule 2(2) of the Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007 and Trade Notice No 9/2018 dated 10<sup>th</sup> May 2018.
- xvii. Korea RP is a market economy and India has been consistently applying Section 9A(c) of the Act to determine normal value in anti-dumping investigations involving Korea RP.
- xviii. Domestic industry has failed to establish how the domestic selling price of Kumho is not in the ordinary course of trade and how Kumho's cost is distorted and the preliminary findings has ruled that domestic sales of Kumho is in ordinary course of trade.
- xix. The raw material supplier of Kumho is also participating in the present investigation and competing with Kumho in several markets, including India. It is commercially impractical for a competitor based in China PR to sell key raw material 4-ADPA to Kumho at a price lower than market price. Kumho had purchased 4-ADPA during the POI on internationally prevailing market prices only.
- xx. Kumho and the raw material supplier in China PR do not have any explicit or implied agreements or commitments regarding the sale or production of raw materials and subject goods to limit each other's sales market or limit competition.
- xxi. Presumption of NME status does not provide for rejection of actual export price to other countries.
- xxii. There is no requirement to assess reasonableness of price under Article 2.2.1.1 of AD Agreement or Annexure I of the AD Rules.
- xxiii. Kumho has correctly requested for level of trade adjustment in the present case and the same must be allowed by the Authority.

### **G.3. Examination by Authority**

38. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
  - a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
  - b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

39. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

- i. M/s Lanxess Corporation USA
- ii. M/s Kumho Petrochemical Co. Ltd.
- iii. M/s Sennics Co., Ltd. Shandong, China PR
- iv. M/s Sennics Co., Ltd. Tai'an, China PR
- v. M/s Sennics Singapore Pte. Ltd.
- vi. M/s Sennics Inc., USA



- vii. M/s Sennics Co., Ltd., China PR
  - viii. M/s Posco International Cooperation, Korea
40. The normal value and export price for all producers/exporters from the subject countries have been determined as below.

#### **G.4. Determination of normal value**

##### **Normal Value in Korea**

##### **Kumho Petrochemical Co. Ltd. (“KKPC”) or (“Kumho”)**

41. M/s Kumho Petrochemical Co. Ltd. (“KKPC”) is a limited liability company established under the Korean Commercial Law. The company has filed Exporter’s Questionnaire response furnishing the requisite information.
42. It is noted from the response that M/s KKPC has sold the subject goods to directly to unrelated customers in the domestic market. It is also noted that KKPC has exported the subject goods directly to India as well as indirectly through an unrelated Korean trader namely, POSCO International Corporation. M/s POSCO International Corporation (“POSCO”) has also provided all the relevant information in the prescribed questionnaire format.

##### **Normal Value**

43. M/s KKPC has submitted Exporter’s Questionnaire response furnishing details of domestic sales and cost of sales of subject goods during the POI. During the POI, M/s KKPC has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market.
44. The Authority notes that 4-ADPA is a major raw material in production of the product under consideration. The information provided by the petitioner domestic industry and Kumho show that 4ADPA constitutes significant part of the total cost of production of PX-13. As per information available on record, 4-ADPA is being largely produced only by Chinese and Indian producer, with some quantity being produced in EU. Information provided by responding producers showed that Kumho have largely sourced 4-ADPA from China PR. Questionnaire response filed by Chinese producers show that they produce their own 4-ADPA. The responding producers from China PR have not claimed market economy treatment.
45. With regard to determination of Normal Value for KPC in the present investigation, it is noted that the Authority has consistently rejected 4ADPA cost of Kumho in the past anti-dumping investigations for determination of normal value. No evidence or argument has been provided that the situation in the present investigation has undergone any major change from the previous investigations of this product from the same country where the same cooperating producer and exporter had participated, i.e., the original investigation, midterm review investigation and sunset review investigations. It is further noted that the very issue has also been upheld by Hon’ble CESTAT, and the Supreme Court and now attained finality with regard to treatment of 4ADPA cost reported by the Kumho. Relevant extract of the Hon’ble CESTAT reproduced below.
46. The Hon’ble CESTAT in its judgment reported as 2015 (322) E.L.T. 514 (Tri. - Del.) held as under:
- “19. In dumping investigations, the Authority routinely requests both price and cost information in order to check whether domestic sales are made below cost. In determining normal value, sales of the like product in the domestic market of the exporting country at prices below per unit (fixed and variable) costs of production plus SGA costs will be treated as not being in ordinary course of trade by reason of price. In order to ascertain the comparable price for the like article when meant for consumption in ordinary course of trade in the exporting country under Section 9A(1)(c)(i) ibid, the sales reflected in the accounts/record for the relevant period at the price shown therein will normally be accepted when the record reasonably reflects the cost associated with the production and sale of such article. However, when a major input is imported from a non-market economy country, the sale price reflected in the record will have to be scrutinized to detect and correct the distortion resulting from the non-market economy price of the input used, the cost of which is required to be worked out in order to correct the distorted cost of production of the article. The Authority is justified in rejecting the domestic sales price shown as the record when the input in question was produced within a non-market economy country, because the price for such input would be distorted, as they*

*do not reflect the normal market economy purchase price. The prices or costs in non-market economies are not accepted as an appropriate basis for the calculation of normal value on the ground that prices and costs are controlled and regulated by the government and therefore not subject to market forces. Export price of 4 ADPA from China to India, would also suffer from the same distortions. Thus, in our view, the international price, as evidenced by the import data for 4 ADPA from a market economy country to India, is a fair basis for ascertaining the actual value of 4 ADPA... ..”*

47. The Hon’ble Supreme Bench c on 8-5-2015 disposed of the Petition for Special Leave to Appeal (Civil) No. 12086-12087 of 2015 with S.L.P. (C) CC No. 8088 of 2015 filed by Kumho Petrochemicals Co. Ltd. against the CESTAT Final Order Nos. AD/A/54808-54810/2014-CU(DB), dated 26-12-2014 as reported in 2015 (322) E.L.T. 514 (Tri.-Del.) (Kumho Petrochemicals Co. Ltd. v. Designated Authority). While disposing of the petitions, the Supreme Court passed the following order :

“SLP (C) Nos. 12086-12087/2015

*Learned counsel for the petitioners, on instructions, seeks permission of this Court to withdraw these special leave petitions with liberty to the petitioners, if they so desire, to question the correctness or otherwise of the order that may be passed by the designated authority, Director General of Anti-Dumping and allied duties, before an appropriate forum by taking up all such contentions which are available to them including the contentions raised in these special leave petitions.*

48. Kumho again challenged the remand finding before Hon’ble CESTAT, the Hon’ble CESTAT rejected the appeal vide its Final Order Nos. AD/A/53452-53453/2016-CU(DB), dated 9-9-2016 reported as 2016 (342) E.L.T. 573 (Tri. - Del.) and held as follows;

*6. We have heard all the interested parties and perused the appeal records including the written submissions. We note that in the first round of appeal, the Tribunal examined two issues for decision. The first one being the correctness of cost construction for production of 6 PPD (one of the subject goods) for arriving at normal value and consequently, the dumping margin and injury decision on the said goods. After elaborate discussion, the Tribunal recorded that the DA rightly rejected the price of 4 ADPA from Sinorgchem and after for construction of normal value based on the international price of 4 ADPA which is a main raw material for 6 PPD. The Tribunal upheld the rejection of 4 ADPA price from China and arriving of normal value based on international price of 4 ADPA. Hence, the issue relating to methodology adopted by the DA in constructing the normal value for the appellants has reached finality. The conclusion of the Tribunal has not been challenged before any higher judicial forum.*

49. The Hon’ble Supreme Court Bench on 13-2-2017 dismissed Petition for Special Leave to Appeal (C) No. 3079 of 2017 filed by Kumho Petrochemicals Co. Ltd. against the CESTAT Final Order Nos. AD/A/53452-53453/2016-CU(DB), dated 9-9-2016 as reported in 2016 (342) E.L.T. 573 (Tri.-Del.) (Rishiroop Polymers Pvt. Ltd. v. Union of India). While dismissing the petition, the Supreme Court passed the following order :

**“The special leave petition is dismissed.”**

50. In view of the above, the very issue has been settled by the Designated Authority and further upheld by Hon’ble CESTAT and Hon’ble Supreme Court, that the Designated Authority has not accepted consumption price of 4-ADPA reported by Kumho.
51. In the present investigation, Kumho Petrochemicals continues to source majority of 4ADPA from the same non-market economy company with whom Kumho Petrochemicals had earlier reported to have special relationship and no facts or evidence have been brought before the Authority in the present investigation that either status of the said company or business activities of the two companies has undergone any change since the previous determination by the Designated Authority.
52. It is therefore considered that the use of actual purchase price of 4ADPA by KKPC from the said non-market economy company would not reasonably reflect the cost associated with production of PX13 (6 PPD), and therefore, the consumption price of 4-ADPA reported by Kumho Petrochemicals cannot be adopted for the purpose of determination of cost of production. Further, there are no imports of 4ADPA to India from a market economy third country during the POI in the present

investigation. However, during the process of investigation, the export price of 4ADPA from India to USA has been made available by the interested party, and the same has been accepted, after adding adjustments as ocean freight, insurance and inland freight, as the prevailing international price of 4ADPA during the POI, and cost of production of Kumho for the product under consideration has been modified accordingly. Rest of the cost of production of Px-13 as claimed by Kumho has been accepted. The revised cost of sales of PX-13 (6PPD) so constructed has been taken into account for ordinary course of trade ("OCT") test.

53. On the basis of cost of sales determined as above, the Authority has carried out ordinary course of trade ("OCT") test, which indicates that less than 80% of domestic sales made during the POI were profitable. Accordingly, profitable domestic sales have been considered for determination of normal value. It is noted from the response that M/s KKPC, during the POI, has sold \*\*\* MT of subject goods at average invoice price of KRW \*\*\* per kg (USD \*\*\* per kg) in the domestic market. It is noted that KKPC has sold subject goods both in bulk and packed forms in the domestic market, while it has sold subject goods to India in packed form only. Thus, for fair comparison, the Authority has taken only packed sales into account for determination of normal value for KKPC.
54. M/s KKPC has claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost, packing cost and level of trade. The Authority notes that KKPC has not provided reasonable evidences to substantiated level of trade adjustment in the EQR submitted. Therefore, level of trade adjustment has not been considered for the normal value determination. Other adjustments claimed by M/s KKPC have been accepted for determining the normal value at ex-factory level. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

### **Normal Value in USA**

#### **i. Lanxess Corporation**

55. M/s. Lanxess Coporation has filed response to exporter's questionnaires, in the prescribed formats. From the data filed by the M/s Lanxess Corporation, the cooperating producer and exporter from USA, it is noted that they have exported the subject goods directly to India to their related party Lanxess India in liquid form. It is further noted that in India, the related party has sold the material in flake form only and therefore, it is considered appropriate to compare Flake to Flake only for the purpose of dumping margin and injury margin. The questionnaire response has been examined and it is noted that the respondent has provided domestic sales price details of the subject goods in respective Appendix. It is noted that M/s. Lanxess Corp., USA has sold \*\*\* MT of subject goods in the domestic market. Out of this \*\*\* MT \*\*\* MT is liquid and remaining \*\*\* MT of flakes in the market. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, only profitable domestic sales have been taken into account for determination of normal value, as it is seen that more than 20% sales are below cost of production.
56. For arriving at the ex-factory normal value, the Authority has considered adjustments (in USD/MT) on account of inland freight and credit cost from the invoice price of the responding producer. Accordingly, the ex-factory normal value is calculated and mentioned in the dumping margin table.

#### **ii. Non-Cooperative exporters in USA**

57. The Authority notes that no other exporter/producer from USA has responded to the Authority in present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in USA, the Authority determined the normal value on the basis of facts available, and the same is mentioned in the dumping margin table.

**Normal Value in China****Market Economy Status for Chinese Producers**

58. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

*"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

*(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

*(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

*(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

59. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted response to questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.

60. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.

**Normal Value for all Producers in China PR.**

61. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under:

*In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other*

*reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

62. It is noted that the prices or constructed value of the product in an appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, has neither been made available by the Applicant or an interested party, nor is available with the Authority from any public source. Thus, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering optimised cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The normal value so determined is given below in dumping margin table.

#### **G.5. Determination of export price**

##### **Korea RP**

##### Kumho Petrochemical Co. Ltd.

63. During the POI, M/s KKPC has exported the subject goods directly to India as well as indirectly through an unrelated Korean trader namely, POSCO International Corporation. M/s KKPC and M/s POSCO have provided all the relevant information in the requisite formats. It is noted from the response that during the POI, M/s KKPC has exported \*\*\* MT of subject goods to India at an average invoice price of KRW \*\*\* per kg (USD \*\*\* per kg).
64. M/s KKPC has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, port and other related expenses, overseas insurance, custom broker fees, commission expenses, packing expenses, credit cost, bank charges and duty drawback and the same have been allowed by the Authority except duty drawback. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

##### For Non-cooperative Exporters from Korea

65. Export price in respect of any other exporters from Korea has been determined, pending further investigation, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S and the questionnaire response of the responding producer and exporters. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

##### USA

##### Lanxess Corporation

66. In the exporters' questionnaire response, the producer / exporter stated that during the POI they directly exported \*\*\* MT to their related party in India. The related importer in India has converted the liquid form of the subject goods in to Flake form and therefore, the Authority has made necessary adjustments on account of the conversion cost. As their selling price of subject goods is lower than their purchase price which includes import prices and conversion cost, suitable adjustments have been made from their landed price and net export price. Further, the Authority has accepted the adjustment as claimed by the exporter on account of inland freight, overseas freight, marine insurance, credit cost, and inland transportation, subject to verification. Accordingly, the export price determined is provided in the dumping margin Table below. The export price so determined has been considered as ex-factory export price of Lanxess USA in respect of solid & packed material. The same has therefore been compared with the normal value of solid and packed material sold by Lanxess USA. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

##### For Non-Cooperative exporters in USA

67. Export price in respect of any other exporters from USA has been determined, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S and the questionnaire response of the producer and exporters. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

**China PR**

Export price of Sennics Co., Ltd. Shandong, China PR (Producer), Sennics Co., Ltd. Shanghai, China PR (Exporter), M/s Sennics Inc., USA (Exporter) and M/s Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore (Exporter)

68. Sennics Co., Ltd. Shandong (hereinafter also referred to as “Sennics Shandong” or “the Company”) is a limited liability company incorporated in China under the Chinese law. Sennics Shandong is 100% owned by Sennics Co., Ltd. (“Sennics Shanghai”).
69. It is noted that Sennics Co., Ltd., Shandong (Producer) and Sennics Co., Ltd. Tai’an, (Producer), China PR, have filed questionnaire response along with its related trading companies, namely, M/s Sennics Co., Ltd. Shanghai, China PR, Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore and Sennics Inc., USA. In their questionnaire response, M/s Sennics Co., Ltd., Shandong and M/s Sennics Co., Ltd. Tai’an, China PR, have declared that these companies have exported the PUC produced by them to India through M/s Sennics Co., Ltd. Shanghai, China PR.

**Sennics Co., Ltd. Shandong, China PR (Producer),**

Export price of Sennics Co., Ltd. Shandong, China PR (Producer), Sennics Co., Ltd. Shanghai, China PR (Exporter), M/s Sennics Inc., USA (Exporter) and M/s Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore (Exporter)

70. The Authority notes that M/s Sennics Co., Ltd., Shandong China PR, has 901.00 MT of the PUC during POI to India through M/s Sennics Co., Ltd. Shanghai, out of which M/s Sennics Co., Ltd. Shanghai, has exported \*\*\* MT, directly to India, \*\*\* MT and \*\*\* MT have been exported to India through M/s Sennics Inc., USA and M/s Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore respectively.
71. It has been noted that Sennics Inc., USA and M/s Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore have reported losses in exports sales of PUC to India. The Export Price has been adjusted to the extent of losses shown by Sennics Inc., USA and M/s Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore.
72. The Authority made adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expenses, credit and bank charges, in order to arrive at the weighted average export price at ex-factory level. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

**Sennics Co., Ltd. Tai’an, China PR (Producer)**

Export price of Sennics Co., Ltd. Tai’an, China PR (Producer), Sennics Co., Ltd. Shanghai, China PR (Exporter), M/s Sennics Inc., USA (Exporter)

73. The Authority also notes that M/s Sennics Co., Ltd. Tai’an, China PR, has exported \*\*\* MT of the PUC during POI to India through M/s Sennics Co., Ltd. Shanghai, out of which M/s Sennics Co., Ltd. Shanghai, has exported \*\*\* MT, directly to India and \*\*\* MT has been exported to India through M/s Sennics Inc., USA.
74. It has been noted that Sennics Inc., USA and M/s Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore have reported losses in exports sales of PUC to India. The Export Price has been adjusted to the extent of losses shown by Sennics Inc., USA and M/s Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore.
75. The Authority made adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expenses, credit and bank charges, in order to arrive at the weighted average export price at ex-factory level. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

**For Non-cooperative Exporters from China PR**

76. Export price in respect of any other exporters from China has been determined, pending further investigation, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S and the questionnaire response of the responding producer and exporters. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

**G.6 Determination of dumping margin (DM)**

77. It is noted that in the subject investigation many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping margin and thus to establish one single dumping margin for them. This is in particular because calculating individual dumping margins might encourage circumvention of antidumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin.
78. In accordance with the above, related producers and exporters from China PR have been regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margins of the cooperating related producers and exporters.
79. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject countries have been determined as follows:

Dumping margin Table

Country	Producer/Exporter	Normal Value/ CNV (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin US\$/MT	Weighted Average DM	Weighted Average DM%	Range
China PR	Sennics Co., Ltd. Shandong	***	***	***	***	***	30-40
	Sennics Co., Ltd. Tai'an	***	***	***	***	***	30-40
	Other Producers and Exporters	***	***	***	***	***	50-60
Korea RP	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	***	***	***	***	***	20-30
	Other Producers and Exporters	***	***	***	***	***	40-50
USA	Lanxess Corporation	***	***	***	***	***	10-20
	Other Producers and Exporters	***	***	***	***	***	10-20

**H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK****H.1. Submissions of the domestic industry**

80. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link. They are as follows:
- The goods from the subject countries directly compete with the like goods by the domestic industry and therefore, it is only appropriate to assess the effect of imports cumulatively.
  - The demand for the product increased in 2017-18, marginally declined in 2018-19 and declined further in the POI. The imports from the subject countries increased in absolute terms in comparison with the base year and declined in the POI when compared to the previous year due to a decline in demand. The imports from subject countries have increased in relative terms.
  - Imports from subject countries, except USA are undercutting the prices of the domestic industry. The imports from subject countries are suppressing the prices of the domestic industry. Further, price underselling/injury margin is positive and significant.
  - With regards to USA, Lanxess USA exports to its related party in India i.e., Lanxess India and therefore, the selling price of the applicant has been considered by the domestic industry as the resale price of Lanxess India in order to determine the landed price of imports from USA.

- e. Capacities were constant throughout the injury period and inventories declined. Production, capacity utilization and domestic sales declined in the POI. Domestic industry exported in losses due to inability to sell the product in the domestic market.
- f. Market share of imports from subject countries have increased and that of the domestic industry has declined over the injury period.
- g. Profitability declined and the domestic industry faced significant financial losses in the POI and in effect, the ability to raise capital investment has weakened. Cash profits, PBIT, ROCE are negative in the POI. This is also because of cessation of anti-dumping duties against imports from Korea and China. Growth of the domestic industry is negative in the POI.
- h. Imports from subject countries pose threat of material injury to the domestic industry, and factors other than dumped imports are not causing injury to the domestic industry.
- i. The performance parameters of the exporters reveal both material injury and threat of material injury to the domestic industry in terms of increase in exports to India. India is a lucrative market for the exporters.
- j. Dumping need not be the sole cause of injury to the domestic industry and the domestic industry needs to only establish 'a' causal link.
- k. The exports sales constitute only 13% of the total sales of the domestic industry. The domestic industry was constrained to export in view of its inability to sell more volumes in the domestic market. Exports are more of a compulsion than a choice or preference.
- l. The domestic industry has stated in the annual reports that dumping is causing injury. Further, the interested parties have referred to the annual report without even establishing how the same pertains to or is relevant to the PUC. Public statements in the Annual Report do not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to injury to the domestic industry.
- m. There is no legal requirement to consider post-POI data in a fresh investigation.
- n. As regards fall in crude prices, the selling price and costs both declined in the POI as compared to the preceding year, the decline in the selling price was far more than the decline in the costs. This is due to the fact that the landed price of imports was below the cost throughout the injury period.
- o. NIP has been calculated as per Annexure III.
- p. The interested parties are selectively reading the annual report. Further explosion of chemical plants pertains to China and not India.
- q. 22% ROCE has been allowed in all situations and for the past many years without considering actual rate of return earned by the domestic industry. 22% is lower than actual rate.
- r. Lanxess has support the present application in their written submissions. Other factors have already been examined by the domestic industry.
- s. It was provisionally held that imports from USA is also causing injury. The dumping margin is positive and substantial.

## H.2. Submissions of other interested parties

81. The following are the submissions of the other interested parties with regard to injury and causal link:
- a. The domestic industry has not considered actual data for the last month of the POI i.e. March 2020. Instead, annualized the figures for the purpose of the injury analysis. This has resulted in insufficient information in the domestic industry petition for analyzing the injury to the domestic industry in the most recent period.
  - b. The anti-dumping duty on import of PX-13 from China PR and Korea RP was in existence till 24 July 2019. Thus, injury to the domestic industry on account of import of the PUC before the POI, would have been negated due to such levy.



- c. The data provided by the domestic industry shows that there is a decline in import volume of PUC during the recent period i.e., the POI. Moreover, user industry is forced to import on account of demand-supply gap.
- d. As the domestic industry is unable to meet the entire demand which increased during the injury period, the same resulted in increase in imports of PUC during the said period. Similarly, when the demand of the PUC declined during the POI, as admitted by the domestic industry itself, the same resulted in decrease in imports of the PUC for the period.
- e. Maximum increase in relative terms is visible from countries with AD duty levy, i.e. the European Union ('EU') which is much higher than the subject countries in the present investigation.
- f. There is no price suppression or depression during the injury period. the landed value from 2016-17 till 2018-19 has increased by 48% which is much more than the increase in selling price of the domestic industry.
- g. The production, sales and capacity utilization of the domestic industry has continuously increased till 2018-19. The data provided for POI(A) is based on estimated figures therefore, the same should be confirmed basis actual data for March 2020."
- h. Inventories of the domestic industry have experienced a decline during the injury period
- i. Market Share of domestic industry has increased in the period of investigation.
- j. Interest cost and depreciation and amortization expense of the domestic industry has increased during the POI(A).
- k. There was a fall in demand/consumption of PUC due to economic slowdown in the automobile sector in India. Thus, these factors may have impacted the profitability of the domestic industry in the present investigation and can be probable reason of losses to the domestic industry.
- l. Losses from export sales cannot be a part of the injury analysis in an anti-dumping investigation and must be separated from the parameters in the present analysis.
- m. Domestic industry's major production is utilized in export sales and it is one of the reasons to contribute to the losses suffered by the domestic industry if any. Domestic industry has not explained the reason for exporting subject goods despite a demand-supply gap.
- n. Increase in import volumes of the PUC during the investigation period may be attributable to the lack of domestic supply in India owing to the domestic industry's affinity towards export markets.
- o. Domestic selling prices of the PUC has dropped in the POI due to a massive fall in crude prices worldwide, which lowered the cost of raw materials by 40% which has been admitted to by the domestic industry itself in its 2018-19 annual report. However, the domestic selling price still shows an increase by 5% in 2018-19 as compared to the base year despite the massive reduction in raw material cost.
- p. It is submitted that the domestic producers of the subject goods are suffering injury because of imports of the subject goods from China and Korea. It is further submitted that the subject goods imported from USA are at substantially higher price, as compared to China and Korea and therefore, are not causing injury to domestic producers in India.
- q. Domestic industry has been claiming protection for 10 years through AD and safeguard measures, despite which it is not able to cater to the demand or improve its efficiency.
- r. The domestic industry has not suffered any injury from US imports as (a) imports from USA are at prices higher than China and Korea, (b) imports are in liquid form, which is converted into flakes in India, (c) liquid PX-13 has very little market share, (d) domestic industry domestic industry is suffering losses and distortions due to imports from Korea RP and China PR, (e) imports from USA have remained competitive. Imports from USA should therefore be excluded from investigation.
- s. Previous SSR filed in 2018 by domestic industry was not initiated since there was no likelihood of injury and a provisional duty would be in contravention to the same.

- t. Prices of the product have softened due to slow down, better availability, general decline in CIF prices and input prices. Slowdown in OEM industry impacted capacity utilization of major tire companies. Increase in depreciation cost, interest cost, foregoing opportunity cost of domestic industry, decline in demand in auto industry, etc. lead to decline in profitability. Also the domestic industry is planning capacity expansion.
- u. Price undercutting range (15-25%) is lower than the range in the terminated SSR investigation. Current prices of imports (without ADD) are not injuring the DI. Price undercutting range in the POI is lower than what prevailed in 2017-18.
- v. Imports increased due to lack of supply. Export orientation increased while capacity remained the same.
- w. Returns in the POI for PX-13 is 15%. Returns during POI do not fall within range of historical returns and cannot be said that subject imports has resulted in declining returns.
- x. DI's economic parameters have improved in Post-POI period according to the conference call on 03.02.2021 by the MD of NOCIL.
- y. There is no threat of material injury to the domestic industry.
- z. There is no causal link between volume of imports, price undercutting and losses suffered by the domestic industry, as there is no correlation between price undercutting and profit parameters of the DI.
- aa. NIP has been fixed at a very high price.
- bb. Decline in profitability is due to abnormal events such as shutdown of plants, explosion in chemical plants and COVID 19.
- cc. The assumption of 22% ROCE is highly inflated, not in accordance with the law and gives undue advantage to DI.
- dd. Serious allegations made by Lanxess against NOCIL should be examined while making causal relationship analysis. The producers have severe competition between themselves, thereby causing injury to NOCIL.
- ee. Domestic producers are suffering injury due to imports from China PR and Korea.
- ff. Export price from USA is higher than China and Korea and are not injuring the domestic producers. Examination of data will reveal that there is no injury to even the applicant from export prices from Lanxess USA.
- gg. DI has not increased its capacity in a decade despite declaring such an intention. Instead of selling 100% production in the domestic market, it's focused on catering on the export market.
- hh. It may be inferred that DI has some arrangement with importers in export market and is not interested in catering the domestic market demand.
- ii. Claims made by companies regarding future plans are likely to change or not be fulfilled, but it does not qualify to disregard the exporter's data.

### H.3. Examination by the Authority

- 82. The Authority has taken note of the arguments and counterarguments of all the interested parties with regard to injury to the Domestic Industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
- 83. As regards argument of considering 22% as return on capital employed, it is noted that Authority has determined NIP as per Annexure III of the AD Rules.
- 84. As regards argument of considering information for post period of investigation, it is noted that the present investigation being a fresh investigation, there is no requirement of considering post period of investigation information

**H.3.1 Cumulative assessment**

85. Annexure-II para (iii) of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- i. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
  - ii. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
86. The Authority notes that:
- i. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
  - ii. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
  - iii. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. It is noted that the consumers who are buying from the domestic industry are also importing from amongst the subject countries.
87. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry. The Authority notes that even though US exporter has supplied the product in liquid form, the same has been eventually sold in solid form by the related importer. Further, the related importer is engaged in production of the product under consideration, and therefore holds all facilities for conversion of the product into solid. The consumers have ultimately consumed the product in solid form only.
88. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

**H.3.2 Volume effect of dumped imports on domestic industry****a) Assessment of demand / apparent consumption**

89. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, the demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of Indian producers and imports from all sources.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>117</i>	<i>107</i>	<i>92</i>
Sales of other Indian producer	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>113</i>	<i>108</i>	<i>83</i>
Subject Countries	MT	5,812	6,797	7,455	7,191
Countries attracting duty - European Union	MT	1,197	2,440	2,591	2,320
Other Countries	MT	0	0	10	312
Total Indian Demand	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>121</i>	<i>119</i>	<i>106</i>

90. It is seen that the demand for the subject good has increased during the injury period, with a decline in the POI. The overall demand of subject goods have increased over the injury period.

**b) Import volumes from the subject countries**

91. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCIS. Factual position is as follows –

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Subject Countries	MT	5,812	6,797	7,455	7,191
China	MT	2,004	3,537	3,882	3,749
Korea	MT	2,657	2,170	1,342	2,085
USA	MT	1,152	1,090	2,231	1,357
Countries attracting duty -European Union	MT	1,197	2,440	2,591	2,320
Other Countries	MT	0	0	10	312
Subject Imports in relation to					
Production	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>95</i>	<i>105</i>	<i>135</i>
Consumption	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>108</i>	<i>117</i>

92. It is seen that the volume of imports from subject countries has increased till 2018-19 but declined marginally during the period of investigation. However, the overall imports of subject goods from subject countries have increased during the POI. The volume of imports from subject countries have increased in relation to total Indian production and consumption.

**H.3.3 Price effect of the dumped imports**

93. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

**a) Price undercutting**

94. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows-

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Net Sales Realisation	₹/Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>131</i>	<i>132</i>	<i>104</i>
<b>China</b>					
Landed Price	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	<i>Range</i>	<i>40-50</i>	<i>30-40</i>	<i>40-50</i>	<i>20-30</i>
<b>Korea</b>					
Landed Price	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	<i>range</i>	<i>50-60</i>	<i>30-40</i>	<i>20-30</i>	<i>20-30</i>
<b>USA</b>					
Landed Price	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	<i>range</i>	<i>10-20</i>	<i>40-50</i>	<i>10-20</i>	<i>(0-10)</i>
<b>Subject Countries</b>					
Landed Price	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	<i>range</i>	<i>40-50</i>	<i>30-40</i>	<i>20-30</i>	<i>10-20</i>

95. It is seen that the imports from subject countries except for USA are entering at a price below the domestic selling price of the Domestic Industry, resulting in positive price undercutting. On a cumulative basis, the price undercutting margins from subject countries are positive.
96. As regards USA, the Authority notes that imports have been made by Lanxess India, who has imported the material in liquid form, processed the same into solid form and thereafter sold the same into India. The Authority further notes that the price undercutting is negative from USA due to the fact that exporters from USA export the subject goods to India at a higher price and their related party sales price in Indian market is lower than the cost price which included import prices of Liquid PX-13 and conversion cost from liquid to Flake of the Indian user. Thus, suitable adjustment has been made from their landed price. Therefore, it is noted that the import price recorded in DGCI&S import data is not showcasing the actual prevailing price of USA exporters in the Indian market.

**b) Price suppression/depression:**

97. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which other would have occurred in normal course, the Authority has considered the changes in the costs and prices over the injury period. The table below shows factual position:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	<i>109</i>	<i>106</i>
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>131</i>	<i>132</i>	<i>104</i>
Landed Value (Subject Countries)	Rs/Kg	143	195	212	183
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>137</i>	<i>148</i>	<i>128</i>

98. It is seen that

- the landed price of imports from subject countries has remained below the cost of sales and the selling price of the domestic industry throughout the injury period
- Even though the cost has increased over the injury period, the domestic industry has not been able to increase its selling price in proportion to increase in costs.
- Whereas the costs declined in 2017-18, both the import price and selling price increased significantly in this period.
- Whereas the selling price and costs both declined in the POI as compared to the preceding year, the decline in the selling price was far more than the decline in the costs.

It is thus seen that imports of subject goods from subject countries are suppressing the prices of the domestic industry in the market.

#### **H.3.4 Economic parameters of the domestic industry**

99. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below

100. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

#### **i. Production, capacity, capacity utilization and sale**

101. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Production	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>128</i>	<i>129</i>	<i>97</i>
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>128</i>	<i>129</i>	<i>97</i>
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>117</i>	<i>107</i>	<i>92</i>
Average Stocks	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>74</i>	<i>95</i>	<i>91</i>

102. It is seen that

- a. Production and capacity utilization of the domestic industry increased till 2018-19 and then declined significantly in the period of investigation.
- b. Whereas demand over the injury period was positive, production and capacity utilization in POI were at a level below the base year.
- c. Domestic sales of the domestic industry have shown a trend similar to that of production. Domestic sales increased in 2017-18 and then declined significantly in the period of investigation. Sales in POI were at a level below the base year.
- d. Overall, the production, capacity utilization and sales have declined during the POI as compared to base year.
- e. Inventories with the domestic industry declined in 2017-18, but increased thereafter. However, inventories have declined over the injury period.

**ii. Market share in Demand**

103. The market share of the domestic industry is shown in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>90</i>	<i>87</i>
Other Indian producer	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	<i>90</i>	<i>78</i>
Subject Countries	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>108</i>	<i>117</i>
China	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>146</i>	<i>163</i>	<i>176</i>
Korea	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>67</i>	<i>42</i>	<i>74</i>
USA	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>78</i>	<i>163</i>	<i>111</i>
Countries attracting duty - European Union	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>169</i>	<i>182</i>	<i>183</i>
Other Countries	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>			<i>100</i>	<i>3475</i>

104. It is seen that the market share of the domestic industry has declined throughout the injury period. The market share of the subject countries have increased over the injury period, whereas market share of the domestic industry has declined.

**iii. Profitability, cash profits and return on capital employed**

105. Profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Profit/Loss	₹/Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>260</i>	<i>108</i>	<i>-120</i>
Profit/Loss	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>304</i>	<i>115</i>	<i>-111</i>

PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>341</i>	<i>128</i>	<i>-120</i>
Cash Profits	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>356</i>	<i>139</i>	<i>-114</i>
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>318</i>	<i>125</i>	<i>-144</i>

106. It is seen that

- a. The domestic industry was suffering financial losses in 2016-17. With decline in costs and increase in prices, the domestic industry earned profits in 2017-18 which declined in 2018-19 and further in POI. The decline in profitability in the POI was very significant and the domestic industry once again suffered financial losses in the POI.
- b. Cash profits, PBIT and return on investment have shown the same trend as profits. Performance of the domestic industry in respect of cash profits, PBIT and return on investment first improved in 2017-18 and thereafter declined significantly till POI. The domestic industry has suffered cash losses, negative PBIT and return on investment in the POI.

**iv. Employment, wages and productivity**

107. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
No. of Employees	Nos	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>95</i>
Productivity Per Day	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>128</i>	<i>129</i>	<i>97</i>
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>89</i>	<i>79</i>	<i>71</i>

108. It is seen that

- a. The employment levels have remained constant in the last three years.
  - b. The productivity per day increased steadily till 2018-19 but declined in the POI.
  - c. The wages paid has declined throughout the injury period.
109. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry.

**v. Growth**

110. The growth of the domestic industry in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits, and return on investment has become significantly negative during the period of investigation.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	POI
Production	Y/Y	28	1	(25)
Domestic Sales	Y/Y	17	(9)	(14)
Cost of Sales	Y/Y	(7)	16	(3)
Selling price	Y/Y	31	0	(21)



Profit/Loss	Y/Y	(360)	(59)	(211)
Cash profits	Y/Y	(456)	(61)	(182)
ROCE	Y/Y	(418)	(61)	(215)

**vi. Ability to raise capital investment**

111. It is seen that the domestic industry has faced significant decline in profitability, which has weakened its ability to raise capital investment.

**vii. Factors affecting domestic prices**

112. It is seen that the import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. The landed value of the subject goods from the subject countries are below the cost and selling price of the domestic industry. Further, the domestic industry is unable to retain its prices in the market due to presence of dumped imports in the country. The prices of imports have suppressed the prices of the domestic industry to a significant degree. The imports of subject goods from third countries are either attracting anti-dumping duty or at de-minimus levels or are at higher prices. The dumped imports are impacting the prices of the domestic industry. Hence, it is concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject countries.
113. The Authority notes that the Dumping Margin is more than de-minimus and also significant. The Authority has taken note of the arguments and counterarguments of all the interested parties with regard to injury to the Domestic Industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
114. As regards the argument of demand supply gap, the Authority considers that possible demand-supply gap cannot deprive a domestic industry from seeking redressal against dumped imports causing injury. If the exporters wish to meet the requirement in Indian market, that could be done by meeting the requirements at an undumped price. It is also noted that the profitability of the domestic industry is much adverse in the export market, as compared to domestic market. It is not established that the domestic industry preferred exports over domestic sales. Further, it is seen that the capacity utilisation of the domestic industry declined significantly in the present investigation period.
115. As regards the argument of exports of domestic industry causing injury, it is clarified that the performance of the domestic industry has been analysed with respect to its domestic operations only. Losses suffered in exports have been segregated and not considered in the present findings.
116. As regards the decline in the raw material prices, it is noted that the profitability of the domestic industry has been considered, having regard to actual raw material prices. It is seen that the profitability of the domestic industry significantly declined, despite these decline in raw material prices.
117. With regard to argument that the reasons of decline in profitability is due to increase in interest and depreciation costs. It is also seen that the performance of the domestic industry declined in respect of profit before interest (ROI) and profit before depreciation (cash profits).
118. As regards decline in demand, it is seen that whereas the demand for the product declined, the imports from subject countries increased and production, domestic sales and capacity utilisation of the domestic industry declined.
119. As regards previous ADD and absence of injury due to the same, it is clarified that the Authority has considered injury to the domestic industry in the present POI.
120. With regard to the contention of the interested parties that imposition of anti-dumping duty will not be prejudicial to interests of the users, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

121. With regard to the issue of continued duty raised by the interested parties, the Authority notes that there is no antidumping duty on the product at present. In fact, the Authority had earlier recommended cessation of antidumping duty on the grounds that there was no likelihood of injury to the domestic industry. The information relating to the domestic industry however shows that the domestic industry is once again suffering injury, due to significant price depression caused by the imports of subject goods from subject countries.

**viii. Magnitude of price underselling/injury margin (IM)**

122. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. The penultimate product which is captively consumed in PUC i.e. 4 ADPA has been optimised as per Annexure III of the Rules. A reasonable return @ 22% on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration and 4ADPA was allowed towards interest, tax and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.
123. Landed price for the cooperating exporters has been determined from the CIF export price determined for the purpose of dumping margin determination. Applicable customs duties have been added to determine landed price of imports. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
124. As mentioned in the dumping margin analysis, it is noted from the response filed by the Lanxess Corporation, USA (producer / exporter) that their related user / importer Lanxess India in India has incurred a loss during the sale of the subject goods in Flake Form. As their sales price of subject goods in Flake Form is lower than the cost price which included import prices of Liquid PX-13 and conversion cost from liquid to Flake of the Indian user, suitable adjustment has been made from their landed price.
125. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Country	Producer	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin US\$/MT	IM weighted	IM%	IM range
China PR	Sennics Co., Ltd. Shandong	***	***	***	***	***	20-30
	Sennics Co., Ltd. Tai'an	***	***	***	***	***	20-30
	Other Producers and Exporters	***	***	***	***	***	40-50
Korea RP	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	***	***	***	***	***	20-30
	Other Producers and Exporters	***	***	***	***	***	20-30
USA	Lanxess Corporation	***	***	***	***	***	(10-20)
	Other Producers and Exporters	***	***	***	***	***	(10-20)

### H.3.5 Conclusion on Injury

126. The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of dumped imports from subject countries has increased in both absolute and relative terms. The imports from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry. It is also noted that the imports of subject goods from the subject countries are suppressing the prices of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has declined in the period of investigation. The performance of the Domestic Industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed. The Domestic Industry has suffered financial losses, cash losses and negative return on investments in the period of investigation. In view of the foregoing, the Authority concludes that the Domestic Industry has suffered material injury.

### I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

127. The Authority examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

#### **a) Volume and value of Imports not sold at dumped prices**

128. The imports from other countries are either attracting anti-dumping duty or at de-minimis levels. Thus, imports from other countries do not appear to have caused injury to the domestic industry.

#### **b) Contraction in demand**

129. While overall demand has increased, the demand has declined in the period of investigation. However, the volume of imports have increased in POI. Thus, the claimed injury to the Domestic Industry is not on account of contraction of demand.

#### **c) Changes in pattern of consumption**

130. There have been no material changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the domestic industry.

#### **d) Conditions of competition and trade restrictive practices**

131. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

#### **e) Developments in technology**

132. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

#### **f) Export performance of the domestic industry**

133. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause for the injury to the domestic industry. However, the domestic industry has submitted that it is compelled to export only because of absence of demand for the product from the domestic market.

#### **g) Performance of other products**

134. The domestic industry has provided the injury data of PUC performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Therefore, performance of other products produced and sold by the applicant is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

**J. Conclusion on Causal Link**

135. The Authority concludes that the domestic industry has not suffered injury in the POI due to other factors. Further, the following factors show that the injury to the domestic industry is due to subject dumped imports:
- i. The imports are undercutting the prices of Domestic Industry and are priced below the cost of the Domestic Industry.
  - ii. The imports have forced the Domestic Industry to sell the product at a price below cost of production. The Domestic Industry has suffered price depression on account of dumped imports.
  - iii. The adverse volume and price effect on account of imports of subject goods from subject countries has resulted in financial losses, cash losses and negative return on investments in the POI.
  - iv. Price undercutting has led to increase in imports and decline in sales of the domestic industry.
  - v. Decline in sales of the domestic industry has led to decline in market share, production and capacity utilization of the domestic industry.
136. The Authority, thus, finally concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods and injury to the domestic industry.

**K. Post Disclosure statement submissions****Submissions by Domestic Industry**

137. The submissions made by the domestic industry is as follows
- i. Lanxess did not file any non-confidential version of the information filed by them post preliminary determination, in order to rectify the deficiency thereby violating confidentiality provisions under the Rules and the principles of natural justice. Reference was made to Anti-subsidy investigation against imports of Fibreboard where the Authority rejected exporter responses as sufficient non-confidential version was not provided.
  - ii. The NIP calculated by the Authority is not as per Annexure III of the AD Rules. The disclosure statement does not specify the reason for significant differences in NIP reported in petition and calculated by the Authority. The Authority is requested to share the linked file along with modifications made, without which, the petitioner is unable to offer comments on the NIP.
  - iii. Annexure III has been applied to captive inputs, which is inconsistent with Annexure III, a number of affidavits filed by DGTR before the Hon'ble High Court, past practices and public statements and communications made by DGTR.
  - iv. The reasons for modification by DGTR of net fixed assets reported by applicant and resultantly the depreciation has not been disclosed. If such deductions are due to the application of Indian accounting standards (IND-AS), the domestic industry has already substantiated the appropriateness of such amount.
  - v. The reasons for significant reduction of working capital as compared to the working capital reported by the domestic industry has not been disclosed, without which the domestic industry is unable to offer comments.
  - vi. Imposition of duties will arrest decline in the performance of the industry, redress the injury suffered and enable domestic producer to remain viable and competitive.
  - vii. A competitive domestic industry capable of supplying the product to the consumers in competition to fair priced imports is in consumer's interests.
  - viii. If the current situation continues, the industry will face further injury and eventually be wiped out, giving foreign producers increased leverage, and the consumers will be left at their mercy.
  - ix. The consumers will have to maintain higher degree of inventory if they have to depend on imported material, while, in case of procurement from the domestic industry, inventory holding can be kept at much lower levels.

- x. The domestic industry has been underutilizing its capacities due to the presence of dumped imports from the subject countries.
- xi. Anti-dumping duty will provide a level playing field, address the decline of the domestic industry's performance, and at the same time does not have an adverse impact on the eventual end consumers. Anti-dumping duty is only a means of price correction and not a protection to the domestic industry.
- xii. Radial tyres price ranges between INR 20,000/- to INR 25,000/- and the cost of PX-13 is INR 90 per tyre. Even a 20% increase in price of PX-13 due to imposition of anti-dumping duties will only result in an increase in cost by INR 18 per tyre, which is 0.09% of the price of a radial tyre. Impact of duty on the consumer industry is very miniscule.
- xiii. The domestic industry has sufficient capacity of PX-13 to cater to the domestic market for future requirements.
- xiv. Since Eastman Chemical has sold their rubber chemicals business to One Rock Capital, the customers will be forced to depend on China and NOCIL for 4ADPA supply, and non-imposition of duties will result in suspension or cut down of operations and the consumers will be left at the mercy of Chinese suppliers.
- xv. The raw material used in the production of PX-13 i.e., 4ADPA constitutes 85% of its total cost. The major suppliers of 4ADPA are China and India. The Applicant is the sole manufacturer of 4ADPA in India. Injury to the domestic industry due to the presence of dumped imports will cause an imbalance in supply chain arrangement.
- xvi. The domestic industry has increased capacities of the product under consideration to meet the demand-supply gap in the country. The increase in investments by the domestic industry will only lead to more employment, thereby benefitting the Indian economy as a whole.
- xvii. Due to widening trade deficit and dwindling forex reserves, it is important to rely more on the domestic production capacities and reduce import dependence.
- xviii. Since normal value of China is based on data of the domestic industry, the same should be disclosed. Further, calculations by the domestic industry shows a higher dumping margin than that of the Authority.
- xix. The Authority should disclose the non-confidential version of the communication sent to participating exporters and replies if any, post filing of questionnaire responses, and verification reports.

#### **Submissions by other interested Parties**

138. The submissions of other interested parties are as follows

- i. The Authority has not analyzed in its examination in the subsequent para 28, as to how it may recommend an ADD without the DI having adduced any additional evidence that was not already submitted at the time of issue of the preliminary findings, when the same has already been rejected by the Central Government. Thus, in view of the above, the respondents respectfully submit that the Hon'ble DA should not recommend a definitive ADD on the PUC.
- ii. The analysis of causal link between the imports from subject countries and the alleged injury is lacking. The Hon'ble DA in its non-attribution analysis in paras 127-135 of the DS has not accounted for any of the submissions made by ATMA which clearly demonstrate the break in causal link.
- iii. There is a demand supply gap, and the domestic industry is unable to cater prevailing demand in Indian market.
- iv. With respect to M/s. KKPC while calculating the dumping margin, export price has been considered for the PUC sold in bulk form whereas the normal value has been taken for the bulk and packed form together. The authority should compare the export prices of bulk with the normal value of bulk and packed.

- v. The DI's claims that it is suffering 'material injury' barely 3 months after the December 2018 decision of the Hon'ble DA in the SSR mentioned above, seemingly defies any logical explanation. Therefore, the Hon'ble DA's statement that its own determination in December 2018 is no longer relevant is without any justification or necessary context. The Hon'ble DA is thus requested to revisit its conclusion in this regard.

### **Examination by the Authority**

139. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
- a. As regards argument on excessive confidentiality, treatment of China as non-market economy, return @ 22% on average capital employed, the same has already been addressed in the relevant paragraphs of these findings.
  - b. As regards the contention that the domestic industry cannot meet the demand for the product in the country, the Authority notes that the demand-supply gap in the country does not justify dumping of the product in the country, particularly when the same is causing injury to the domestic industry.
  - c. As regards M/s KKPC's concern on Normal Value, the Authority has examined the issue and has appropriately modified the normal value and export price, and explained it in the relevant headings in this finding.
  - d. As regards eligibility of Lanxess India as domestic industry, it is seen from the information provided by the Lanxess that the company has imported significant volumes of the product under consideration from USA. It is also noted that the company is related to exporter and is itself an importer, and the volume of such imports is quite significant (entirety of the imports from US are by this company). The Authority has considered Lanxess as a domestic producer, but not domestic industry within the meaning of Rule 2(b). As regards submissions made by interested parties concerning eligibility of Lanxess, India, the Authority notes that ineligibility of Lanxess India is on account of imports of PX-13 and its relationship with the exporter from USA.
  - e. As regards various argument raised by domestic industry on the insufficient disclosure of NIP, argument on Annexure III has been applied to captive inputs, and argument on modification of net fixed asset, depreciation and working capital while computing NIP the authority reiterated that for determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. The penultimate product which is captively consumed in PUC i.e. 4 ADPA has been optimised as per Annexure III of the AD Rules. Moreover, a reasonable return @ 22% on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration and 4ADPA was allowed towards interest, tax and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules. The significant difference between the claimed and allowed value of NIP is because of the above said relevant factors as considered by the authority after due verification of data on record.
  - f. As regards the argument on 2018 findings of Designated Authority, it is submitted that the period of investigation in that case was July 2017-June 2018, whereas the period of investigation in the present case is 2019-20. The Authority has in the relevant paragraphs of these findings has determined that the exporters are dumping the product under consideration during the period of investigation resulting in injury to the domestic industry.

**L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

140. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
141. The Authority considered whether imposition of ADD shall have adverse public interest. For the same, the Authority examined whether the imposition of the anti-dumping duty on imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers and consumers of the product.
142. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of ADD on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchange ability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of ADD on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of ADD.
143. Four users, namely, M/s. Apollo Tyres Limited, M/s. CEAT Limited, M/s. JK Tyre & Industries Limited, M/s. MRF Limited and one related importer, namely M/s. Lanxess India Private Limited have filed the prescribed user/importer questionnaire response. However, as already noted in these findings, none of these users have provided any verifiable information in order to demonstrate the effect of anti-dumping duty on the consumers. Further, in this regard, the Authority re-iterates that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
144. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of ADD and elaborate how imposition of ADD shall adversely impact them, it is noted that none of the users have provided relevant information. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information. Further the domestic industry has quantified the impact of the recommended anti-dumping duty on the consumer industry and submitted that the impact is miniscule on different segments of the consumer. The fact that there are only three Indian producers of the product under consideration, i.e. PMC Rubbchem P Ltd which has stopped production of PUC, Lanxess India P Ltd, and NOCIL Ltd. It is also noted that the domestic industry is the sole producer of the major raw material, i.e., 4ADPA used in the production of the product under consideration. Thus, non-imposition of anti-dumping duty will adversely impact the indigenous production of the product concerned. From the information on record, it is also noted that the impact of anti-dumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration, and the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in public interest.

**M. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS**

145. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- a. The Applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
- b. The product produced by the domestic industry is like article to PUC imported from the subject countries.
- c. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation and the application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation decided to initiate the present investigation.
- d. The very issue of rejection of consumption price of 4-ADPA reported by Kumho has been settled by the Designated Authority and further upheld by Hon'ble CESTAT and Hon'ble Supreme Court.
- e. The use of actual purchase price of 4ADPA by KKPC from the said non-market economy company would not reasonably reflect the cost associated with production of PX13 (6 PPD), and therefore, the consumption price of 4-ADPA reported by Kumho Petrochemicals cannot be adopted for the purpose of determination of cost of production.
- f. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from each of the subject countries have been determined, and the margins are significant.
- g. The domestic industry has suffered material injury. The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry shows that the volume of dumped imports from subject countries has increased in both absolute and relative terms. The volume of subject goods has increased by more than 23% whereas demand has increased by only 6%. The imports from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry, and the margin of price undercutting is more than 10 percent. It is also noted that the imports of subject goods from the subject countries are suppressing the prices of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has declined in the period of investigation. It is noted that market share of domestic industry has declined by 13% . The performance of the Domestic Industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed. The profits, PBIT, cash profits, and ROCE have declined by 20%, 20% 14% and 44% respectively. The Domestic Industry has suffered financial losses, cash losses and negative return on investments in the period of investigation.
- h. The material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports.
- i. No anti-dumping duty is recommended against exports of subject goods from USA as injury margin is negative.
- j. Despite providing all formats for users to quantify the impact of ADD and elaborate on how imposition of ADD will adversely impact them, none of the users have provided relevant information. The interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information. Non-imposition of anti-dumping duty will adversely impact the indigenous production of the product concerned and the fact that the impact of anti-dumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration, the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in public interest.



146. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. The Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
147. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of antidumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975. No anti-dumping duty is recommended against exports of subject goods from USA as injury margin is negative.

Duty Table

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3812, 2921, 2934 (note 1)	Rubber Chemical PX 13 (note 2)	China PR	Any country including China PR	Sennics Co., Ltd. Shandong	591.36	MT	US\$
2	- do -	- do -	China PR	Any country including China PR	Sennics Co., Ltd. Tai'an	591.36	MT	US\$
3	- do -	- do -	China PR	Any country including China PR	Any producer other than Serial Number 1 & 2	924.47	MT	US\$
4	- do -	- do -	Any country other than countries attracting anti-dumping duty	China PR	Any	924.47	MT	US\$
5	- do -	- do -	Korea RP	Any country including Korea RP	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	489.56	MT	US\$

6	- do -	- do -	Korea RP	Any country including Korea	Any producer other than Serial Number 5	612.18	MT	US\$
7	- do -	- do -	Any country other than countries attracting anti-dumping duty	Korea RP	Any	612.18	MT	US\$

Note-1 - Customs classification mentioned above is only indicative.

Note-2 - The description of the product under consideration is "Rubber Chemicals PX-13" also known as 6PPD, Antioxidant 6PPD, Kumanox 13, Santoflex 6PPD, Sirantox 6PPD, Vulkanox 4020, Antioxidant 4020, Dussantox 6PPD, Antage 6C, N-1,3-Dimethylbutyl)-N'-Phenyl-P-Phenylenediamine.

#### N. FURTHER PROCEDURE

148. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority